https://informatics.nic.in

वॉल्यूम 35, सं. 01, जुलाई, 2026

इन्फॉर्मैटिक्स

ISSN 0971-3409

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र की
त्रैमासिक ई-शासन प्रकाशन

राजस्थान राज्य 06

त्रिपुरा राज्य 12

पेंशनर सेवा पोर्टल पंजाब 26

ई-एस.सी.एम.एस 28

यू.एम.पी.एस 30

वेदिका 32

जॉग फ्रेमवर्क 34

निकडीसाइन 3.0 36

इन्फॉर्मेटिक्स
वॉल्यूम 35 संख्या- 01, जुलाई 2026

संरक्षक
प्रियंक भारती, आईएएस

सलाहकार मंडल
वी. टी. वी. रमणा
सी. जे. एंटनी
डॉ. राजेश कुमार पाठक
जी. मयिल मुथु कुमारन
अंजलि ढींगरा

प्रधान संपादक
मोहन दास विश्वम्

क्षेत्रीय संपादक
अमित अग्रवाल
विनोद कुमार गर्ग
लाल बहादुर सिंह
स्वरूप दत्ता
अविनाश वी. पेडगांवकर
जॉयस आर. अमृतराज

सामग्री सहयोग
अर्चना शर्मा
हेमेंद्र कुमार सैनी

डिज़ाइन सहयोग
मुकेश भारती
रोहित कुमार मौर्या

तकनीकी सहयोग
सुनील कुमार
अमित कुमार लोधी
अंकित कुमार
मो. पिंटू

प्रिंट एवं समन्वय
यू.एक्स.डी.टी. विभाग

प्रकाशक
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी
मंत्रालय, भारत सरकार

संपर्क पता
इन्फॉर्मेटिक्स
379, ए4बी4, तृतीय तल, एनआईसी
ए-ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड
नई दिल्ली-110003, भारत
फोन: 011-24305363/ 65
ईमेल: editor.info@nic.in

संपादकीय

डिजिटल से बुद्धिमत्तापूर्ण सुशासन की ओर

प्रौद्योगिकी ने वर्षों से सरकारों की कार्यक्षमता बढ़ाई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब उन्हें अधिक बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करने में सक्षम बना रहा है।

पिछले एक दशक में भारत के उल्लेखनीय डिजिटल परिवर्तन ने सुशासन के अगले चरण की मजबूत नींव रखी है। सुदृढ़ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना तथा नागरिक-केंद्रित डिजिटल मंचों ने सरकारों द्वारा सेवाएँ प्रदान करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे सेवा वितरण अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं प्रभावी बना है। जैसे-जैसे ये डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र परिपक्व हो रहे हैं और अधिक समृद्ध अंतर्दृष्टियाँ उपलब्ध करा रहे हैं, सुशासन केवल डिजिटल सेवा वितरण तक सीमित न रहकर अधिक बुद्धिमान, डेटा-संचालित एवं सक्रिय स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभर रहा है। इसकी सबसे बड़ी शक्ति मानवीय निर्णय क्षमता का स्थान लेना नहीं, बल्कि उसे और अधिक सक्षम बनाना है। डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न की पहचान करने, नियमित प्रक्रियाओं का स्वचालन करने तथा सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकारों को अधिक उत्तरदायी, प्रभावी एवं नागरिक-केंद्रित बनाता है। साथ ही, यह सार्वजनिक संस्थाओं को अपने सबसे महत्वपूर्ण दायित्व—नागरिकों की सहानुभूति, जवाबदेही एवं विश्वास के साथ सेवा करने—पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाता है।

इस अंक में प्रकाशित लेख दर्शाते हैं कि यह परिवर्तन सुशासन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार आकार ले रहा है। राजस्थान का पढ़ाई विद एआई यह प्रदर्शित करता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सरकारी विद्यालयों में शिक्षण को किस प्रकार व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बना सकता है। वहीं पंजाब का पेंशनर सेवा पोर्टल, तथा एआई-संचालित पेंशन असिस्टेंट के लिए उसकी भावी रूपरेखा, यह दर्शाती है कि बुद्धिमान प्रौद्योगिकियाँ किस प्रकार सार्वजनिक सेवा वितरण को सरल बना सकती हैं तथा पेंशनभोगियों के अनुभव को बेहतर कर सकती हैं। ये सभी पहलें इस तथ्य को पुष्ट करती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब भविष्य की परिकल्पना मात्र नहीं, बल्कि ठोस सार्वजनिक मूल्य सृजित करने का एक व्यावहारिक माध्यम बन चुका है।

फिर भी, बुद्धिमान सुशासन केवल एल्गोरिद्म के आधार पर निर्मित नहीं किया जा सकता; इसकी नींव विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। जैसे-जैसे सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा उन्नत डेटा एनालिटिक्स को अपनाती जा रही हैं, वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा, डेटा के उत्तरदायी उपयोग, पारदर्शिता, गोपनीयता तथा नैतिक नवाचार को भी समान महत्व देना आवश्यक है। प्रत्येक सफल डिजिटल पहल का आधार नागरिकों का विश्वास है, जो यह सुनिश्चित करता है कि प्रौद्योगिकी प्रत्येक नागरिक की सुरक्षित, निष्पक्ष एवं समावेशी तरीके से सेवा करे।

लगभग पाँच दशकों से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) सुरक्षित, स्केलेबल एवं इंटरऑपरेबल डिजिटल मंचों के विकास के माध्यम से भारत की डिजिटल सुशासन यात्रा का अग्रणी भागीदार रहा है। ये मंच शासन के प्रत्येक स्तर पर सरकारों को सशक्त बना रहे हैं। जैसे-जैसे उभरती प्रौद्योगिकियाँ सार्वजनिक प्रशासन का अभिन्न हिस्सा बनती जा रही हैं, एनआईसी डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने की अपनी भूमिका से आगे बढ़ते हुए ऐसे विश्वसनीय, एआई-सक्षम सुशासन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है, जो संस्थागत क्षमता को सुदृढ़ बनाता है तथा सार्वजनिक सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी बनाता है।

सुशासन का भविष्य केवल इस बात से निर्धारित नहीं होगा कि हमारी प्रौद्योगिकियाँ कितनी बुद्धिमान बनती हैं, बल्कि इससे होगा कि हम उनका उपयोग कितनी दूरदर्शिता एवं जिम्मेदारी के साथ करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वास्तविक सफलता केवल उसकी संगणनात्मक क्षमता से नहीं, बल्कि उससे सृजित सार्वजनिक मूल्य से आँकी जाएगी, जो सुशासन को अधिक उत्तरदायी, समावेशी एवं मानवीय बनाता है। डिजिटल से बुद्धिमान सुशासन की यह यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और इसे सदैव नवाचार, उत्तरदायित्व एवं जनविश्वास के सुदृढ़ आधार पर आगे बढ़ना चाहिए।

- प्रधान संपादक

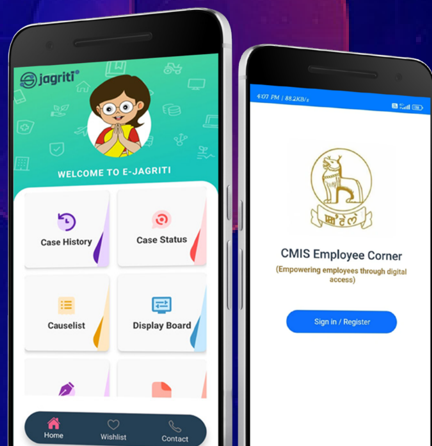

विषय सूची

संपादकीय	02
विषय वस्तु	03
महानिदेशक संदेश	05
राज्यों से	
राजस्थान	06
त्रिपुरा	12
जिलों से	
चित्तूर, आंध्र प्रदेश	18
केंद्रपाड़ा, ओडिशा	20
मोरीगांव, असम	22
उज्जैन, मध्य प्रदेश	24
ई-गवर्नेंस समाधान एवं सेवाएँ	
पेंशनर सेवा पोर्टल पंजाब	26
ई-एस.सी.एम.एस	28
यू.एम.पी.एस	30
वेदिका	32
प्रोद्योगिकी अद्यतन	
जॉग फ्रेमवर्क	34
निकडीसाइन 3.0	36
ऐपस्केप	38
अंतर्राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सेवाएँ	40
समाचारों में	44
पुरस्कार	48

अस्वीकरण

इस प्रकाशन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं, और ये संपादकों या राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। साथ ही, लेखों में दिए गए तथ्यों एवं सूचनाओं की सटीकता की ज़िम्मेदारी लेखकों पर ही होगी।

श्री प्रियंक भारती, आईएएस ने एनआईसी के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया

श्री प्रियंक भारती, आईएएस ने 21 मई 2026 को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के 20वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे अपने साथ सार्वजनिक नीति, सुशासन, प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवा वितरण तथा संस्थागत नेतृत्व के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का समृद्ध प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैं। उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, जब डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डेटा-आधारित सुशासन तथा उभरती प्रौद्योगिकियाँ देशभर में सार्वजनिक सेवा वितरण के भविष्य को नई दिशा प्रदान कर रही हैं।

पंजाब कैडर के वर्ष 2001 बैच के आईएएस अधिकारी श्री भारती को लोक प्रशासन, नीति क्रियान्वयन, संस्थागत नेतृत्व तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम सुशासन के क्षेत्र में दो दशकों से अधिक का व्यापक अनुभव प्राप्त है। इंजीनियरिंग तथा एमबीए की शैक्षणिक पृष्ठभूमि रखने वाले श्री भारती ने राज्य एवं केंद्र सरकार में अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है तथा नवाचार, प्रशासनिक सुधार एवं नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को बढ़ावा देने वाली विभिन्न पहलों से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं।

एनआईसी में पदभार ग्रहण करने से पूर्व श्री भारती पंजाब सरकार के विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग में प्रशासनिक सचिव के रूप में कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने सुशासन एवं सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

वर्षों के दौरान श्री प्रियंक भारती ने सचिव, संयुक्त सचिव, निदेशक, उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त तथा उप-मंडल मजिस्ट्रेट सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। इन विविध प्रशासनिक दायित्वों ने उन्हें लोक प्रशासन, जिला प्रशासन, नीति क्रियान्वयन, अवसंरचना विकास तथा सेवा वितरण के क्षेत्र में व्यापक व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया है। विभिन्न क्षेत्रों में उनके कार्य अनुभव ने सुशासन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग से जुड़ी संभावनाओं एवं चुनौतियों की गहन समझ विकसित की है।

उनके सहयोगी श्री प्रियंक भारती को संस्थागत विकास, सहभागी नेतृत्व तथा परिणामोन्मुखी सुशासन पर विशेष बल देने वाले एक दूरदर्शी प्रशासक के रूप में जानते हैं। नीतिगत उद्देश्यों को प्रभावी क्रियान्वयन से जोड़ने की उनकी क्षमता उनके प्रशासनिक कार्यकाल की एक प्रमुख विशेषता रही है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के महानिदेशक के रूप में श्री प्रियंक भारती ऐसे महत्वपूर्ण समय में पदभार ग्रहण कर रहे हैं, जब भारत डिजिटल परिवर्तन के एक निर्णायक चरण से गुजर रहा है। सुरक्षित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, क्लाउड अवसंरचना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स तथा नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं पर सरकारों की बढ़ती निर्भरता के बीच एनआईसी देशभर में प्रौद्योगिकी-संचालित सुशासन को सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

श्री प्रियंक भारती के नेतृत्व में एनआईसी से सरकार के लिए सुदृढ़, सुरक्षित एवं स्केलेबल डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के अपने मिशन को और अधिक सशक्त बनाने की अपेक्षा है। उनका व्यापक प्रशासनिक अनुभव तथा सुशासन में प्रौद्योगिकी की भूमिका के प्रति गहरी समझ, नागरिकों के लिए समावेशी, पारदर्शी एवं प्रभावी डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं के विकास की दिशा में एनआईसी के सतत प्रयासों का मार्गदर्शन करेगी।

सत्यमेव जयते

प्रियंक भारती, आईएएस
महानिदेशक

भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

प्रिय पाठकों,

प्रौद्योगिकी शासन के स्वरूप को निरंतर परिवर्तित कर रही है। यह सरकारों को नागरिकों तक सेवाएँ पहुँचाने, निर्णय लेने तथा जटिल सामाजिक चुनौतियों का प्रभावी समाधान करने के नए अवसर प्रदान कर रही है। डिजिटल सुशासन के क्षेत्र में देश की अग्रणी संस्था के रूप में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने सुरक्षित, स्केलेबल एवं नागरिक-केंद्रित डिजिटल समाधानों का विकास कर इस परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज ये समाधान देशभर में सुशासन व्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुके हैं।

वर्तमान समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन्नत डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा क्वांटम प्रौद्योगिकी जैसी उभरती प्रौद्योगिकियाँ डिजिटल परिदृश्य को नई दिशा प्रदान कर रही हैं। ऐसे परिवेश में एनआईसी सुशासन एवं सार्वजनिक सेवा वितरण में नवाचार के अगले चरण का नेतृत्व करने के लिए विशिष्ट रूप से सक्षम है।

वर्षों के दौरान हमारी उपलब्धियाँ देशभर में कार्यरत एनआईसी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पण, विशेषज्ञता तथा प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। हम सभी ने मिलकर ऐसे डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म एवं सार्वजनिक डिजिटल अवसंरचना का निर्माण किया है, जिन्होंने सुशासन को सुदृढ़ बनाया है, पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है तथा नागरिकों तक सेवाओं के प्रभावी वितरण को सुनिश्चित किया है। उत्कृष्टता की यही सामूहिक भावना हमारी सफलता का आधार रही है।

हमारे समक्ष उपलब्ध अवसर केवल प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे हमें सुशासन की नई परिकल्पना प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे इसे अधिक बुद्धिमान, उत्तरदायी, समावेशी एवं नागरिक-केंद्रित बनाया जा सके। इस दृष्टि को साकार करने के लिए हमें नवाचार, सतत अधिगम एवं सहयोग की संस्कृति को और अधिक सुदृढ़ करना होगा तथा ऐसी उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा, जो व्यापक स्तर पर सार्थक एवं स्थायी परिवर्तन लाने में सक्षम हों।

डिजिटल सुशासन का भविष्य सरकार, शिक्षण संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों, स्टार्टअप्स तथा उद्योग जगत के मध्य सुदृढ़ साझेदारी से निर्धारित होगा। सहयोग एवं ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देकर एनआईसी परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों को अपनाने की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकता है तथा सुशासन की उभरती आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी समाधान विकसित कर सकता है।

आगे बढ़ते हुए सुरक्षित, सुदृढ़ एवं विश्वसनीय डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता अटूट रहनी चाहिए। साइबर सुरक्षा, इंटरऑपरेबिलिटी, उत्तरदायी नवाचार तथा नागरिकों का विश्वास केवल तकनीकी आवश्यकताएँ नहीं हैं, बल्कि प्रभावी डिजिटल सुशासन के आधारभूत स्तंभ हैं।

एनआईसी की सबसे बड़ी शक्ति सदैव इसके अधिकारी एवं कर्मचारी रहे हैं, जो प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता के साथ-साथ सुशासन एवं सार्वजनिक सेवा की गहरी समझ रखते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सभी मिलकर एनआईसी की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए नवाचार के नए आयाम स्थापित करेंगे तथा डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में अपने योगदान को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।

आइए, हम प्रौद्योगिकी, नवाचार एवं ज्ञान की शक्ति का प्रभावी उपयोग करते हुए स्थायी सार्वजनिक मूल्य का सृजन करें तथा राष्ट्र के लिए डिजिटल सुशासन के भविष्य को नई दिशा प्रदान करें।

शुभकामनाओं सहित

सादर,
प्रियंक भारती

राज्यों से

राजस्थान

नागरिकों तक डिजिटल सेतु

संपादित : **अविनाश वी. पेडगांवकर**

वर्ष 1988 में राजस्थान में अपनी स्थापना के बाद से एनआईसी राज्य के डिजिटल सुशासन पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। राज्य सचिवालय, सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों तथा विभिन्न विभागीय परियोजना कार्यालयों में अपनी उपस्थिति के माध्यम से एनआईसी राजस्थान ने भारत के सबसे बड़े एवं भौगोलिक दृष्टि से विविध राज्यों में से एक के लिए सुदृढ़ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना विकसित की है।

एनआईसी राजस्थान ने राज्य सचिवालय, जिला कलेक्टर कार्यालयों तथा 100 से अधिक सरकारी संस्थानों को उच्च गति नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने वाला सुरक्षित संचार नेटवर्क विकसित एवं अनुरक्षित किया है। केंद्र नेटवर्क अवसंरचना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई-मेल सेवाएँ, क्लाउड आधारित समाधान तथा एंड-टू-एंड सूचना प्रौद्योगिकी सहायता जैसी महत्त्वपूर्ण डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जिससे राज्यभर में विभिन्न विभागों के बीच निर्बाध समन्वय तथा प्रभावी सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।

इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि जयपुर में अनुप्रयोग सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आर.सी.ओ.ई.ए.एस) की स्थापना है। यह केंद्र सात राज्यों में एनआईसी द्वारा विकसित ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों की सुरक्षा जाँच तथा सुरक्षित अनुप्रयोग विकास प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डिजिटल अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, कनेक्टिविटी तथा एंटरप्राइज प्रौद्योगिकी सेवाओं के क्षेत्र में अपने निरंतर प्रयासों के माध्यम से एनआईसी राजस्थान राज्य के डिजिटल परिवर्तन को नई गति प्रदान कर रहा है।

एनआईसी राजस्थान ने पूरे राज्य में प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए आईसीटी समाधानों के माध्यम से सेंटर ने नागरिक सेवाओं की व्यवस्था को बेहतर बनाया तथा कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाई है। गवर्नेंस और निर्णय प्रक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिटिक्स जैसी नई तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। नेटवर्किंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के अलावा, एनआईसी राजस्थान ने आई.एफ.एम.एस, पहचान, संस्था आधार, पी.सी.टी.एस, शालादर्पण और ई-पंजीयन जैसे प्रमुख डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए हैं। इन प्लेटफ़ॉर्मों के सरकारी ऐप्लिकेशन के साथ एकीकरण से समन्वय बेहतर हुआ है तथा सेवाओं का वितरण अधिक सरल और सुव्यवस्थित हुआ है। एनआईसी राजस्थान के योगदान को व्यापक सराहना मिली है और उन्हें कई नेशनल ई-गवर्नेंस अवॉर्ड प्राप्त हुए हैं।

डॉ गायत्री पांडुरंगी
उप महानिदेशक व एसआईओ
gayatri.ap@nic.in

अमित अग्रवाल
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
amit.agarwal@nic.in

राज्य में आईसीटी पहलें

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस)

https://ifms.rajasthan.gov.in

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) राजस्थान सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए प्रमुख डिजिटल प्रणाली है। यह बजट प्रबंधन, कोषागार संचालन, राजस्व प्राप्ति, व्यय प्रबंधन, निर्माण कार्यों के प्रबंधन, लेखांकन, पेंशन तथा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सहित संपूर्ण वित्तीय कार्यप्रवाह के लिए एकीकृत समाधान उपलब्ध कराती है। ऑनलाइन राजस्व संग्रहण एवं वास्तविक समय में मिलान सुनिश्चित करने के लिए यह ई-ग्रास के साथ एकीकृत है, जिससे राज्य की वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शी, दक्ष एवं जवाबदेह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित हुई है।

प्रमुख मॉड्यूल

- **बजट प्रबंधन** – बजट का आकलन, आवंटन, पुनर्विनियोजन तथा निगरानी।
- **कोषागार प्रबंधन** – सरकारी भुगतानों एवं प्राप्तियों का प्रसंस्करण तथा प्राधिकरण।
- **राजस्व प्रबंधन (ई-ग्रास/आरएमएस)** – सरकारी राजस्व का ऑनलाइन संग्रहण एवं मिलान।
- **कर्मचारी प्रबंधन** – वेतन प्रसंस्करण, कर्मचारी स्व-सेवा तथा पेरोल प्रबंधन।
- **पेंशन प्रबंधन** – सिविल एवं सामाजिक पेंशन का प्रसंस्करण तथा वितरण।
- **निर्माण कार्य प्रबंधन** – प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, कार्यादेश एवं भुगतान।
- **लेखांकन एवं मिलान** – सरकारी खातों का वास्तविक समय में संकलन एवं मिलान।
- **विक्रेता एवं लाभार्थी प्रबंधन** – पंजीकरण, चालान की निगरानी तथा भुगतान की मॉनिटरिंग।

- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) एवं इलेक्ट्रॉनिक भुगतान** – एकीकृत बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से निधियों का सुरक्षित अंतरण

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी)

राजस्थान में डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डी.आई.एल.आर.एम.पी) एक व्यापक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित हुआ है, जो भूमि अभिलेखों के कुशल, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। इस एकीकृत व्यवस्था में निम्नलिखित प्रमुख प्लेटफॉर्म सम्मिलित हैं-

अपना खाता https://apnakhata.rajasthan.gov.in

यह नागरिक-केंद्रित पोर्टल डिजिटल अधिकार अभिलेख (आरओआर), नामांतरण विवरण तथा ई-हस्ताक्षरित भूमि अभिलेखों तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करता है। इसके माध्यम से नामांतरण, सीमांकन तथा भूमि विभाजन जैसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

ई-धरती https://edharti.rajasthan.gov.in

यह कार्यप्रवाह-आधारित प्लेटफॉर्म कागजरहित आवेदन, डिजिटल सत्यापन एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुमोदन के माध्यम से भूमि नामांतरण प्रक्रिया को स्वचालित बनाता है। प्रणाली में सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ), ई-साइन, क्यूआर कोड तथा शिकायत निवारण जैसी सुविधाओं का एकीकरण किया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है तथा सेवाओं का वितरण अधिक त्वरित हुआ है।

भू-नक्शा https://bhunaksha.rajasthan.gov.in

यह भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित भू-अभिलेख मानचित्रण समाधान है, जो भूमि पार्सलों के डिजिटलीकरण, जियो-रेफरेंसिंग एवं दृश्यांकन की सुविधा प्रदान करता है। अपना खाता एवं ई-धरती के साथ एकीकृत यह प्रणाली स्थानिक एवं पाठ्य भूमि अभिलेखों का समन्वय सुनिश्चित करती है तथा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर (यू.एल.पी.आई.एन) आधारित भूमि पहचान का समर्थन करती है।

इन तीनों प्लेटफॉर्मों के माध्यम से राजस्थान में भूमि प्रशासन के लिए एक सुरक्षित, एकीकृत एवं प्रौद्योगिकी-संचालित ढाँचा विकसित हुआ है, जिससे भूमि अभिलेखों की उपलब्धता, शुद्धता एवं पारदर्शिता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ई-पंजीयन

https://epanjiyan.rajasthan.gov.in

ई-पंजीयन राजस्थान में संपत्ति पंजीकरण एवं स्टाम्प प्रशासन के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है। नागरिक-केंद्रित इस प्रणाली ने संपूर्ण पंजीकरण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करते हुए इसे अपना खाता के साथ एकीकृत किया है, जिससे संपत्ति के पंजीकरण के साथ ही भूमि अभिलेखों का स्वचालित नामांतरण सुनिश्चित होता है। यह प्रणाली राज्य के सभी 661 उप-पंजीयक कार्यालयों (एसआरओ) में संचालित है तथा अब तक 12.5 करोड़ से अधिक दस्तावेज़ों का पंजीकरण कर 43,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व अर्जित कर चुकी है।

प्रमुख विशेषताएँ

- विक्रय, उपहार एवं त्यागपत्रों का स्वचालित विलेख निर्माण।
- चुनिंदा एसआरओ पर कहीं भी रजिस्ट्रेशन
- संपत्ति के स्थान पर ऑन-साइट पंजीकरण
- कार्यालय में आने के लिए समय स्लॉट बुकिंग
- अप्रयुक्त या अतिरिक्त स्टांप शुल्क के लिए गुमनाम धनवापसी
- ई-ग्रास एवं ई-धरती के साथ एकीकरण, जिससे वित्तीय लेनदेन एवं भूमि अभिलेखों का अद्यतन सुगमता से होता है।

एक खास इनोवेशन जीआईएस-आधारित वैल्यूएशन सिस्टम है, जिसे 26 एसआरओ में लागू किया गया है। यह सिस्टम जियो-टैग किए गए डीएलसी रेट्स का इस्तेमाल करके प्रॉपर्टी की कीमत अपने-आप तय करता है। यह प्लेटफ़ॉर्म आरबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और अकाउंटेंट जनरल ऑफिस जैसी एजेंसियों के साथ सुरक्षित डेटा शेयरिंग की सुविधा भी देता है।

'ई-पंजीयन' सिटिज़न मोबाइल ऐप से प्रॉपर्टी की जानकारी डिजिटल रूप से जमा करने, जीपी एस-आधारित प्रॉपर्टी मैपिंग, जियो-टैग की गई तस्वीरें लेने, एप्लीकेशन को रियल-टाइम में ट्रैक करने और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही, 'स्टाम्प वेंडर' मोबाइल ऐप इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिक्री का रिकॉर्ड रखने और रिपोर्टिंग प्रोसेस को डिजिटल बनाता है, जिससे स्टाम्प एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने की क्षमता और पारदर्शिता बढ़ती है।

पी.सी.टी.एस

https://pctsrajmedical.rajasthan.gov.in

गर्भावस्था, शिशु ट्रैकिंग एवं स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली (पी.सी.टी. एस) राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एक व्यापक डिजिटल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना तथा ग्राम स्तर तक स्वास्थ्य सेवाओं के वितरण को सुदृढ़ बनाना है। यह प्रणाली वर्ष 2009 से सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में तथा अप्रैल 2023 से निजी अस्पतालों में भी संचालित है। इसके माध्यम से—

- गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों का पूर्ण टीकाकरण तक ट्रैकिंग।
- उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं तथा विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी।
- टीकों एवं औषधियों के भंडार का वास्तविक समय में प्रबंधन।

पी.सी.टी.एस के प्रभावी क्रियान्वयन से मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) 318 से घटकर 86, शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 63 से घटकर 29 हो गई है। वहीं प्रसवपूर्व जाँच (एएनसी) का कवरेज 28 प्रतिशत से बढ़कर 93 प्रतिशत तथा संस्थागत प्रसव 45 प्रतिशत से बढ़कर 98 प्रतिशत हो गए हैं।

यह प्रणाली पहचान पोर्टल, राज-पोषण, शालादर्पण, प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल तथा स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस) सहित विभिन्न प्रमुख प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत है, जिससे विभागों के बीच डेटा का निर्बाध आदान-प्रदान तथा स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक प्रभावी वितरण सुनिश्चित होता है।

आशासॉफ्ट

https://ashasoft.rajasthan.gov.in

आशासॉफ्ट मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) के कार्य निष्पादन की निगरानी तथा 56 स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को सक्षम बनाने वाला कार्यप्रवाह-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह प्रणाली स्वीकृति एवं भुगतान प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करती है, जिससे भुगतान में लगने वाला समय कई महीनों से घटकर एक सप्ताह

> एनआईसी राजस्थान राज्य की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदार के रूप में निरंतर योगदान दे रहा है। नवाचारी, नागरिक-केंद्रित डिजिटल समाधानों तथा सुदृढ़ आईसीटी अवसंरचना के माध्यम से एनआईसी ने विभिन्न विभागों में प्रभावी सुशासन एवं बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण को सतत सशक्त बनाया है। उत्कृष्टता के प्रति इसकी प्रतिबद्धता, ई-गवर्नेंस पहलों का समयबद्ध क्रियान्वयन तथा राज्य सरकार के साथ घनिष्ठ सहयोग ने पारदर्शिता, सुगमता एवं प्रशासनिक दक्षता को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है। उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग की दिशा में एनआईसी के निरंतर प्रयास डिजिटली सशक्त राजस्थान के विज़न को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
>
> **श्री वी. श्रीनिवास, आईएएस**
> मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार

▼ चित्र 2.1: राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री ने राज्य की ऐतिहासिक 'ऑटो-म्यूटेशन' (स्वतः नामांतरण) सेवा का शुभारंभ किया, जो संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया को भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली के साथ निर्बाध रूप से जोड़ती है

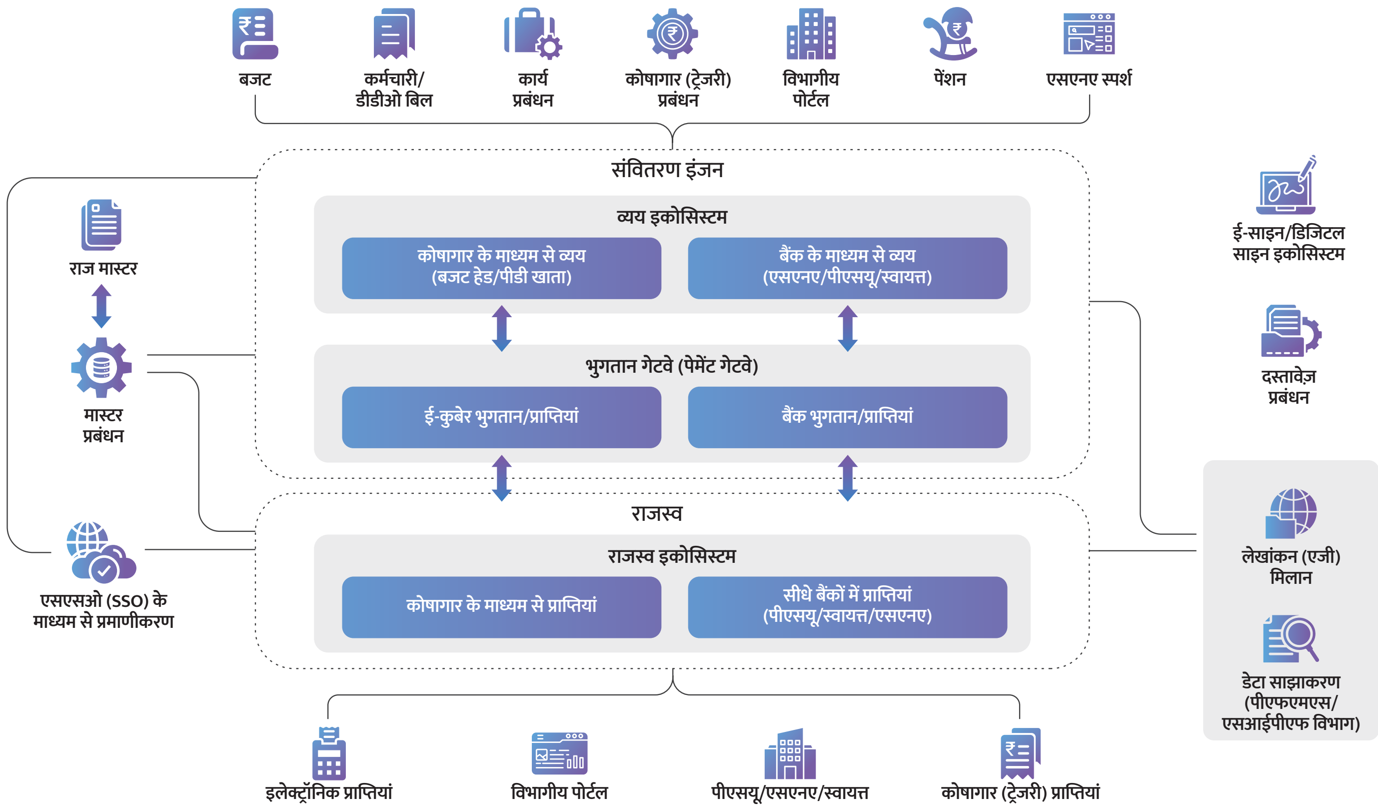

चित्र 2.2 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस) 3.0

से भी कम रह गया है। साथ ही, इसने पारदर्शिता, जवाबदेही एवं कार्यकुशलता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

ओजस

https://ojspm.rajasthan.gov.in

ओजस (ऑनलाइन जेएसवाई, राजश्री और शुभ लक्ष्मी पेमेंट सिस्टम) महिलाओं और बच्चों की भलाई वाली योजनाओं - जैसे JSY, राजश्री, शुभलक्ष्मी और लाडो प्रोत्साहन योजना - के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्लेटफॉर्म है। यह 'माँ वाउचर योजना' के तहत प्राइवेट सोनोग्राफी सेंटर्स को पेमेंट करने में भी मदद करता है। इस सिस्टम ने 1.7 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को ₹3,300 करोड़ से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर करने में मदद की है, जिससे समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ मिल पाता है।

राजहेल्थ

https://rajhealth.rajasthan.gov.in

राजहेल्थ राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के लिए विकसित एक समग्र मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली है, जो राज्य के 20,000 से अधिक स्वास्थ्य संस्थानों के कर्मचारियों का प्रबंधन करती है। यह प्रणाली पदस्थापन, स्थानांतरण, परिवीक्षा पूर्ण करना, वेतन निर्धारण, ऑनलाइन कार्यभार ग्रहण तथा कार्य निष्पादन प्रतिवेदन जैसी प्रमुख मानव संसाधन प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण कर पारदर्शी, कागजरहित एवं दक्ष कार्यबल प्रबंधन सुनिश्चित करती है।

एकीकृत शालादर्पण

https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in

एकीकृत शालादर्पण राजस्थान के विद्यालयी शिक्षा विभाग की डिजिटल आधारभूत प्रणाली है, जो राज्य के 72,000 से अधिक राजकीय विद्यालयों में विद्यालयी अवसंरचना, नामांकन, शैक्षणिक गतिविधियों, मानव संसाधन तथा छात्र कल्याण योजनाओं के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए एक समग्र निर्णय-सहायक प्रणाली उपलब्ध कराती है।

इस प्लेटफॉर्म पर 76 लाख से अधिक विद्यार्थियों तथा 4.4 लाख शिक्षकों एवं कर्मचारियों का वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध है, जिससे यह देश की सबसे बड़ी शैक्षिक सूचना प्रणालियों में से एक बन गया है। यह कक्षा 5 एवं 8 की परीक्षाओं के संचालन, परिणाम प्रसंस्करण, कार्मिक भर्ती एवं पदस्थापन, स्टाफिंग पैटर्न तैयार करने, शिक्षक इंटर्नशिप आवंटन, विद्यालय निरीक्षण, सिविल कार्यों की निगरानी, व्यावसायिक शिक्षा प्रबंधन तथा विद्यालय से बाहर के बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने जैसी प्रमुख शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों का समर्थन करता है।

शालादर्पण छात्रवृत्ति, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक एवं कार्यपुस्तिका वितरण, साइकिल एवं लैपटॉप वितरण, परिवहन वाउचर, वर्दी हेतु प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), राष्ट्रीय आय-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एन.एम.एम.एस), गार्गी पुरस्कार तथा बालिका प्रोत्साहन योजनाओं सहित विभिन्न छात्र कल्याण योजनाओं के संपूर्ण प्रशासन का भी समर्थन करता है, जिससे लाभार्थियों का पारदर्शी प्रबंधन तथा समयबद्ध लाभ वितरण सुनिश्चित होता है।

राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल

https://rajpsp.rajasthan.gov.in

राजस्थान प्राइवेट स्कूल पोर्टल (राजपीएसपी) राज्य के 36,000 से अधिक निजी विद्यालयों के लिए एक समग्र डिजिटल सुशासन मंच है। यह पोर्टल मान्यता, संबद्धता, निरीक्षण, अनुपालन निगरानी तथा शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के क्रियान्वयन को पारदर्शी एवं कागजरहित कार्यप्रवाह के माध्यम से संचालित करता है।

इस प्लेटफॉर्म का एक प्रमुख घटक आरटीई प्रवेश एवं प्रतिपूर्ति प्रणाली है, जिसके माध्यम से आरटीई अधिनियम के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त लगभग 14 लाख विद्यार्थियों का प्रबंधन किया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से निजी विद्यालयों को 5,000 करोड़ रुपये से अधिक की प्रतिपूर्ति वितरित की जा चुकी है, जिसमें केवल पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 1,000 करोड़ रुपये का भुगतान शामिल है। इससे निधियों का दक्ष, पारदर्शी एवं जवाबदेह प्रबंधन सुनिश्चित हुआ है।

ज्ञानसंकल्प

https://gyansankalp.nic.in

ज्ञानसंकल्प राजस्थान के डिजिटल शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने वाला एक अभिनव मंच है, जो राजकीय विद्यालयों को दानदाताओं, परोपकारी संस्थाओं, कॉर्पोरेट संगठनों तथा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहलों से जोड़ता है।

यह प्लेटफॉर्म विद्यालयी अवसंरचना, डिजिटल शिक्षण संसाधन, स्वच्छता सुविधाएँ, पुस्तकालय, खेल अवसंरचना तथा बालिका शिक्षा के लिए सहयोग उपलब्ध कराने में सहायता करता है। शालादर्पण के साथ एकीकृत यह प्रणाली दान, परियोजनाओं के क्रियान्वयन तथा उनके परिणामों की वास्तविक समय में निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करती है। साथ ही, यह शिक्षा के क्षेत्र में सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित

करती है तथा परोपकारी योगदानों के प्रभाव का डेटा-आधारित मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है।

श्रम विभाग प्रबंधन प्रणाली (एल.डी.एम.एस)

एल.डी.एम.एस राजस्थान सरकार के श्रम विभाग का एक समग्र डिजिटल शासन मंच है, जिसे श्रम प्रशासन का आधुनिकीकरण करने तथा एकीकृत डिजिटल प्रणाली के माध्यम से नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। एलडीएमएस श्रमिकों, प्रतिष्ठानों, ठेकेदारों, निरीक्षणों तथा श्रमिक कल्याण योजनाओं से संबंधित एक केंद्रीकृत वास्तविक समय डाटाबेस उपलब्ध कराता है। इससे प्रभावी विनियमन, आँकड़ा-आधारित निर्णय-निर्माण तथा बेहतर नीतिगत योजना सुनिश्चित होती है। यह प्रणाली श्रमिक एवं प्रतिष्ठान पंजीकरण, अनुज्ञापत्र प्रबंधन, संविदा श्रमिक प्रबंधन, निरीक्षण, अनुपालन निगरानी, शिकायत निवारण तथा प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन सहित श्रम प्रशासन की संपूर्ण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करती है।

यह मंच वित्तीय सहायता, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएँ, मातृत्व लाभ, पेंशन, आवास सहायता, कौशल विकास तथा दुर्घटना राहत जैसी श्रमिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को भी सरल बनाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) व्यवस्था के साथ एकीकरण के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को लाभों का पारदर्शी, सुरक्षित एवं समयबद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

नेवा

https://raj.neva.gov.in

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) एक वर्कफ़्लो-आधारित प्लेटफ़ॉर्म है जो विधानसभाओं के कामकाज को पेपरलेस बनाता है। राजस्थान विधानसभा ने विधायी प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने, कार्यक्षमता बढ़ाने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए नेवाको लागू किया है। इस प्रोजेक्ट में सदस्यों के लिए आईपैड, लैपटॉप, पीसी, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और लगभग 400 लैन नोड्स लगाना शामिल है। पुराने रिकॉर्ड, जिनमें सवाल, प्रस्ताव, बिल, सदस्यों की प्रोफ़ाइल और सदन की कार्यवाही शामिल हैं, को डिजिटल बनाकर इस प्लेटफ़ॉर्म पर लाया गया है, जिससे एक आधुनिक, पेपरलेस विधायी इकोसिस्टम तैयार हुआ है।

राजस्थान विधानसभा पोर्टल (https://assembly.rajasthan.gov.in)**:** राजस्थान विधानसभा पोर्टल के माध्यम से सदस्यों की प्रोफ़ाइल, कार्यसूची, प्रश्न, प्रस्ताव, विधेयक, सदन की कार्यवाही, समिति बैठकों, प्रेस कतरनों तथा ई-बुलेटिन सहित विधायी गतिविधियों से संबंधित व्यापक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।

एप्राइज़ (https://rlaaprise.rajasthan.gov.in)**:** एप्राइज़ (विधानसभा कार्यवाही सूचना प्रणाली) विधानसभा की कार्यवाहियों का डिजिटल भंडार है, जो वर्ष 1952 से अब तक के सभी सत्रों की संशोधित एवं असंशोधित कार्यवाहियों को सत्रवार एवं तिथिवार उपलब्ध कराता है। इसमें पूर्ण-पाठ (फुल-टेक्स्ट) खोज की सुविधा भी उपलब्ध है।

ओएसिस (https://rlaoasys.rajasthan.gov.in)**:** ओएसिस (ऑनलाइन आंसरिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम) के माध्यम से विधानसभा सदस्यों द्वारा पूछे गए तारांकित, अतारांकित तथा अल्प सूचना प्रश्नों एवं विभागों द्वारा दिए गए उत्तरों तक ऑनलाइन पहुँच उपलब्ध होती है। यह विधायी प्रश्नों एवं उत्तरों का एक खोजयोग्य डिजिटल भंडार भी उपलब्ध कराता है।

▲ चित्र 2.3: राजस्थान विधानसभा में नेवा के तहत पेपरलेस कार्यवाही

राजस्थान उच्च न्यायालय

https://hcraj.nic.in

एनआईसी राजस्थान, राजस्थान हाई कोर्ट और निचली अदालतों को शुरू से आखिर तक आईसीटी सपोर्ट देता है। नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड (एन.जे.डी.जी) से जुड़ा 'केस इंफॉर्मेशन सिस्टम' (सीआईएस 3.1), डिजिटल केस फाइलिंग, जांच-पड़ताल, कॉज़ लिस्ट और ऑर्डर बनाने में मदद करता है। नागरिक ऑनलाइन केस का स्टेटस, ऑर्डर और फैसले देख सकते हैं; इसमें हाई कोर्ट के 15 लाख से ज़्यादा और निचली अदालतों के 10 लाख से ज़्यादा फैसले शामिल हैं। कोर्ट की जानकारी डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और मोबाइल ऐप के ज़रिए तुरंत मिलती है, जबकि राजस्थान हाई कोर्ट का मोबाइल ऐप वकीलों और केस लड़ने वालों को केस के रिकॉर्ड देखने और केस डायरी को अच्छे से मैनेज करने की सुविधा देता है।

पीडीएस राजस्थान

https://food.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने एक पूर्णतः डिजिटल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लागू की है, जो राशन कार्ड प्रबंधन से लेकर खाद्यान्न वितरण तक संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा वास्तविक समय की निगरानी सुनिश्चित करती है।

नागरिक सिंगल साइन-ऑन (एसएसओ) तथा ई-मित्र के माध्यम से नए राशन कार्ड, संशोधन, डुप्लीकेट राशन कार्ड जारी कराने तथा राशन कार्ड समर्पण सहित सभी सेवाओं का ऑनलाइन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आधार से जुड़े राशन कार्डों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आई.एम.पी.डी.एस) के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर लाभों की अंतर-परिचालनीयता तथा पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन.एफ.एस.ए) तथा गिव-अप अभियान पोर्टल पात्र लाभार्थियों के सत्यापन, नए पात्र परिवारों को शामिल करने तथा अपात्र लाभार्थियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से लाभ छोड़ने की सुविधा प्रदान करते हैं। वहीं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के गोदामों से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न की आवाजाही की जियो-टैगिंग, मार्ग निगरानी तथा ऑनलाइन प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराकर संपूर्ण वितरण श्रृंखला में जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

यह प्रणाली आई.एम.पी.डी.एस, एन.एफ.एस.ए, डिजिलॉकर तथा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओ.एन.ओ.आर.सी) जैसे राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ एकीकृत है। राजस्थान ओ.एन.ओ.आर.सी को अपनाने वाले अग्रणी राज्यों में से एक है, जिससे लाभार्थी आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से देश में कहीं भी रियायती खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एनआईसी राजस्थान ने किसानों के लिए खरीद प्रक्रिया को सरल बनाने तथा समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) खरीद पोर्टल भी विकसित किया है।

▼ चित्र 2.4: माननीय उपमुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा द्वारा जयपुर में 'वाहन लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम' का आधिकारिक तौर पर शुभारंभ किया गया

अन्य प्रमुख डिजिटल पहलें

पहल	उद्देश्य	क्रियान्वयन की प्रमुख विशेषताएँ
ई-हॉस्पिटल	समग्र अस्पताल प्रबंधन प्रणाली	एम्स जोधपुर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर में लागू।
जीवन प्रमाण	पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र	निर्बाध सेवा वितरण के लिए ई-मित्र के साथ एकीकृत।
ई-प्रिजन	कारागार प्रशासन, आगंतुक प्रबंधन एवं ई-मुलाकात सेवाएँ	22 लाख से अधिक पूर्व बंदियों तथा 21,000 वर्तमान बंदियों का डिजिटलीकरण; लगभग 9,000 ई-मुलाकात सत्र आयोजित।
ई-प्रोक्योरमेंट	सरकारी खरीद के लिए एंड-टू-एंड ई-निविदा प्रणाली	निविदा आमंत्रण प्राधिकरणों एवं निविदाकारों के लिए मंच; प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक निविदाएँ प्रकाशित।
सार	राजस्थान का सांख्यिकीय सार तैयार करने हेतु अनुप्रयोग	80 से अधिक विभागों द्वारा उपयोग।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)	विभिन्न क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन सूचकांकों का निर्माण	विनिर्माण, खनन एवं विद्युत क्षेत्रों के लिए राज्यव्यापी क्रियान्वयन।
प्राइस स्टैटिस्टिक्स इन राजस्थान (पीएसआर)	थोक, खुदरा, निर्माण सामग्री एवं पशुधन मूल्य सूचकांकों की निगरानी	सभी जिलों एवं कृषि उपज मंडी समितियों में लागू।
राजस्थान एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स (राजस)	कृषि सांख्यिकी का समग्र प्रबंधन	सभी जिलों में फसल आकलन, वर्षा, कृषि उपज मूल्य, कृषि मजदूरी एवं संबंधित आँकड़ों का प्रबंधन।
राज-पोषण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मंच	सभी जिलों में ब्लॉक स्तर तक लागू।
मीडिया प्रबंधन प्रणाली	मीडिया समाचार, छायाचित्र एवं वीडियो का केंद्रीकृत भंडार	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय तथा एनआईसी राजस्थान में लागू।
ई-ऑफिस	कार्यालय स्वचालन एवं डिजिटल फाइल प्रबंधन	राजस्थान विधानसभा में कागजरहित कार्यालय व्यवस्था के लिए लागू।
आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस)	बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रबंधन	200 से अधिक केंद्रीय एवं राज्य सरकारी विभागों द्वारा उपयोग।

पहचान (सिविल पंजीकरण प्रणाली)

https://pehchan.rajasthan.gov.in

पहचान राजस्थान में जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण के लिए सत्य के एकल स्रोत के रूप में कार्य करता है। प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग 12,500 से अधिक रजिस्ट्रार, 3,500+ उप-रजिस्ट्रार, 2,500+ निजी अस्पताल और 80,000 ई-मित्र कियोस्क द्वारा किया जाता है। नागरिक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित, व्हाट्सएप्प सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित क्यूआर कोड-सक्षम प्रमाणपत्रों के साथ, पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। प्लेटफ़ॉर्म पर 4.15 करोड़ से अधिक पंजीकरण दर्ज किए गए हैं। पहचान को आधार, जन आधार, स्वास्थ्य प्रणालियों और सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ एकीकृत किया गया है, जो मैनुअल प्रमाणपत्र प्रसंस्करण को समाप्त करते हुए नवजात शिशुओं के लिए स्वचालित आधार नामांकन और मृत व्यक्तियों के लिए निष्क्रियकरण को सक्षम बनाता है।

संस्था आधार

https://san.rajasthan.gov.in

संस्था आधार राजस्थान में विभिन्न संस्थाओं के पंजीकरण एवं प्रबंधन के लिए विकसित एक डिजिटल मंच है। यह संस्थाओं के ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन की स्थिति की निगरानी तथा संस्थागत अभिलेखों की खोज जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। प्रणाली संस्थाओं से संबंधित सूचनाओं का केंद्रीकृत एवं प्रमाणिक डेटाबेस उपलब्ध कराते हुए सेवा वितरण में पारदर्शिता, दक्षता एवं सुगमता सुनिश्चित करती है।

ई-ग्राम

https://egram.rajasthan.gov.in

मुख्यमंत्री ई-ग्राम राजस्थान के गाँवों के समग्र विकास एवं वास्तविक समय की निगरानी के लिए विकसित एक एकीकृत वेब-आधारित मंच है। यह 25 विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आँकड़ों का एकीकरण कर ग्रामीण अवसंरचना, सार्वजनिक सेवाओं तथा सरकारी योजनाओं की व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है। यह मंच पारदर्शी प्रशासन, प्रभावी योजना निर्माण, विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाते हुए सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देता है।

अनुप्रयोग सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आर.सी.ओ.ई.ए.एस)

जयपुर में स्थापित अनुप्रयोग सुरक्षा के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्र (आर.सी.ओ.ई.ए.एस), राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन एवं दीव, दादरा एवं नगर हवेली, मध्य प्रदेश तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित आठ राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में एनआईसी द्वारा विकसित अनुप्रयोगों की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह केंद्र वेब अनुप्रयोगों, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) तथा मोबाइल अनुप्रयोगों का सुरक्षा परीक्षण एवं नियमित पेनेट्रेशन परीक्षण संचालित करता है, जिससे सरकारी डिजिटल सेवाओं की साइबर सुरक्षा और अधिक मजबूत होती है।

निक्की चैटबॉट एवं वॉयसबॉट सेवा

https://niccicms.raj.nic.in

निक्की एनआईसी राजस्थान द्वारा विकसित एक बहुभाषी एवं वॉयस-सक्षम चैटबॉट प्लेटफॉर्म है, जिसे बिना किसी अतिरिक्त प्रोग्रामिंग प्रयास के विभिन्न सरकारी पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। यह हिंदी, अंग्रेज़ी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का समर्थन करता है और बुद्धिमान नियम-आधारित उत्तर प्रणाली के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को सटीक जानकारी प्रदान करता है।

यह प्लेटफॉर्म राज्य के 100 से अधिक पोर्टलों पर कार्यरत है। इसमें एक उपयोगकर्ता-अनुकूल कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम (सीएमएस) भी उपलब्ध है, जिसके माध्यम से ज्ञान भंडार का प्रबंधन एवं निरंतर अद्यतन सरलता से किया जा सकता है।

ई-परिवहन

https://transport.rajasthan.gov.in

ई-परिवहन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की मिशन मोड परियोजना है, जो सरकार-से-सरकार (जी-टू-जी), सरकार-से-नागरिक (जी-टू-सी) तथा सरकार-से-व्यवसाय (जी-टू-बी) सेवाओं को केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) तथा राज्य के नियमों के अनुरूप एकीकृत रूप में उपलब्ध कराती है।

राजस्थान की परिवहन प्रणाली में 89 क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय, 3,500 से अधिक वाहन डीलर, 350 ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान, 83 स्वचालित फिटनेस केंद्र, 13 स्वचालित ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक तथा 1,500 ई-चालान पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) उपकरण शामिल हैं। राज्य में 2.29 करोड़ वाहन पंजीकरण तथा 1.35 करोड़ डिजिटलीकृत ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध हैं और इस प्रणाली के माध्यम से प्रतिवर्ष 8,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है। प्रत्येक माह लगभग 1 लाख नए वाहन पंजीकृत होते हैं, 65,000 ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाते हैं तथा 5 लाख से अधिक परिवहन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

ई-रवन्ना एकीकरण

यह सुविधा खान विभाग की ई-रवन्ना प्रणाली से अधिक भार वाले वाहनों का डेटा स्वतः आईटीएमएस को उपलब्ध कराती है, जिससे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नोटिस एवं ई-चालान स्वतः जारी किए जा सकते हैं। इससे प्रवर्तन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं डेटा-आधारित बनती है।

स्वचालित हाइपोथिकेशन समाप्ति (एचपीटी)

यह सुविधा वित्तीय संस्थानों से ऋण समाप्ति की सूचना स्वतः प्राप्त करती है। नागरिक हाइपोथिकेशन समाप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और स्वीकृति स्वतः प्रदान की जाती है। इससे क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त होती है तथा सेवा अधिक त्वरित एवं कागजरहित बनती है।

राजस्थान राजस्व न्यायालय निगरानी प्रणाली

यह परियोजना राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों के आधुनिकीकरण के लिए एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी समाधान

महत्त्वपूर्ण मोबाइल एप्लिकेशन

मोबाइल ऐप	उपयोगकर्ता	प्रमुख विशेषताएँ
बजट राजस्थान	नागरिक, सरकारी अधिकारी	राजस्थान सरकार के बजट दस्तावेज़, आवंटन एवं वित्तीय जानकारी तक पहुँच।
संस्था आधार	नागरिक, संस्थाएँ	ऑनलाइन पंजीकरण, आवेदन की स्थिति तथा संस्था आधार अभिलेखों की खोज।
एकीकृत कार्य निगरानी प्रणाली (आई.डब्ल्यू.एम.एस)	सरकारी अधिकारी	विकास कार्यों की तकनीकी एवं वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय में निगरानी।
पहचान	नागरिक	जन्म, मृत्यु एवं विवाह प्रमाण-पत्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन, डाउनलोड एवं स्थिति की जानकारी।
गर्भावस्था, शिशु ट्रैकिंग एवं स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली (पी.सी.टी.एस)	स्वास्थ्य अधिकारी	मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जाँच, टीकाकरण, कार्ययोजना तथा स्वास्थ्य संकेतकों की निगरानी।
राजस्थान उच्च न्यायालय	नागरिक, अधिवक्ता	वाद सूची, डिस्प्ले बोर्ड, वाद की स्थिति, फाइलिंग संबंधी त्रुटियाँ तथा प्रमाणित प्रतियों की जानकारी।
ई-ग्रास	नागरिक, करदाता	डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड सहित विभिन्न बैंकिंग माध्यमों से राजस्थान सरकार को कभी भी, कहीं से भी ऑनलाइन भुगतान।

विकसित करने पर केंद्रित है। इसके माध्यम से न्यायिक कार्यवाही के विभिन्न चरणों में बयान का डिजिटल अभिलेखन, नोटिस एवं अंतिम आदेश जारी करना तथा वाद सूची का स्वचालित निर्माण जैसी प्रक्रियाएँ संचालित की जाती हैं।

इस समाधान में दो मॉड्यूल विकसित किए गए हैं— एक राजस्व अधिकारियों के लिए तथा दूसरा नागरिकों एवं अधिवक्ताओं के लिए। राजस्व अधिकारियों का मॉड्यूल पूर्णतः विकसित कर राजस्व मंडल (बीओआर) के समक्ष सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया जा चुका है, जबकि नागरिक मॉड्यूल का विकास वर्तमान में प्रगति पर है।

रलैम्स

राजस्थान कृषि भूमि आवंटन निगरानी प्रणाली (रलैम्स) राजस्व विभाग द्वारा विकसित एक डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य सरकारी भूमि आवंटन प्रक्रिया का आधुनिकीकरण एवं सरलीकरण करना है। यह प्रणाली सार्वजनिक अवसंरचना, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों, औद्योगिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं तथा अन्य सार्वजनिक प्रयोजन की परियोजनाओं के लिए सरकारी भूमि के आवंटन की प्रक्रिया को कागजरहित, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी-संचालित बनाती है।

राज्य - जिला स्तर की प्रमुख पहलें

पढ़ाई विद एआई

पढ़ाई विद एआई टोंक जिले के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 के गणित शिक्षण को सुदृढ़ बनाने के लिए विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित शिक्षण मंच है। यह मंच विद्यार्थियों को व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव, प्रश्नों के त्वरित समाधान, स्वचालित अभ्यास सामग्री तथा द्विभाषी व्याख्या उपलब्ध कराता है, जिससे अवधारणात्मक समझ एवं विद्यार्थियों की सहभागिता में वृद्धि होती है।

इस प्लेटफॉर्म का उपयोग 11,500 से अधिक सक्रिय विद्यार्थी कर रहे हैं। वास्तविक समय के विश्लेषण, डिजिटल उपस्थिति तथा प्रदर्शन डैशबोर्ड के माध्यम से यह शिक्षण परिणामों, जवाबदेही तथा परीक्षा तैयारी को अधिक प्रभावी बनाता है।

गंग नहर विनियमन कम्प्यूटरीकरण प्रणाली

श्रीगंगानगर की गंग नहर विनियमन कम्प्यूटरीकरण प्रणाली नहर संचालन, जल स्तर, सिंचाई कार्यक्रम तथा ग्राम स्तर के अभिलेखों से संबंधित वास्तविक समय की जानकारी उपलब्ध कराती है। इसका कृषि मॉड्यूल मौसम पूर्वानुमान, मंडी भाव, फसल संबंधी परामर्श तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान करता है, जिससे किसानों को बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

इस प्रणाली के पूरक के रूप में ई-बारी किसानों को उनके सिंचाई जल आवंटन की जानकारी उपलब्ध कराती है, जबकि ई-अबियाना जल कर के डिजिटल संग्रहण एवं प्रबंधन की सुविधा प्रदान कर सिंचाई प्रशासन में पारदर्शिता एवं कार्यकुशलता को बढ़ावा देती है।

मूलभूत डिजिटल अवसंरचना

राज्य में सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए एनआईसी राजस्थान ने व्यापक डिजिटल अवसंरचना विकसित की है। केंद्र 5,000 से अधिक निकनेट नोड का प्रबंधन करता है, जो राज्य सचिवालय, जिला कलेक्टर कार्यालयों, विभिन्न सरकारी कार्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थानों को जोड़ते हैं।

राज्य सचिवालय, उच्च न्यायालय की पीठों, जिला कलेक्टर कार्यालयों तथा जिला न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिससे विभिन्न स्तरों पर प्रभावी संवाद एवं समन्वय सुनिश्चित होता है।

एनआईसी राजस्थान 3,000 से अधिक आधिकारिक ई-मेल खातों का प्रबंधन करता है, 100 से अधिक सरकारी पोर्टलों एवं अनुप्रयोगों का संचालन एवं अनुरक्षण करता है तथा बढ़ती संगणन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मिनी क्लाउड का संचालन करता है।

इसके अतिरिक्त, लगभग 300 लीज़्ड लाइन कनेक्शनों के माध्यम से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) जोधपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) उदयपुर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.एन.आई.टी) जयपुर, राजस्थान राज्य डेटा केंद्र (आर.एस.डी.सी) तथा राजस्थान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (आर.एस.डब्ल्यू.ए.एन) सहित प्रमुख संस्थानों को उच्च गति कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गई है।

सम्मान एवं उपलब्धियाँ

ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार, प्रभाव तथा नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के लिए एनआईसी राजस्थान की विभिन्न डिजिटल पहलों को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर व्यापक मान्यता प्राप्त हुई है।

- गर्भावस्था, शिशु ट्रैकिंग एवं स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन प्रणाली (पी.सी.टी.एस), गंग नहर विनियमन प्रणाली तथा आशासॉफ्ट को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।
- पी.सी.टी.एस, प्राइस स्टैटिस्टिक्स पोर्टल, पहचान (सिविल पंजीकरण प्रणाली), संस्था आधार, ज्ञानसंकल्प तथा एकीकृत शालादर्पण को सीएसआई-निहिलेंट पुरस्कार से सम्मानित किया।
- वित्तीय क्षेत्र में ई-गवर्नेंस उत्कृष्टता के लिए जेम्स ऑफ डिजिटल इंडिया पुरस्कार प्रदान किया गया है।
- एनआईसी राजस्थान की विभिन्न परियोजनाओं को स्कॉच पुरस्कार, टेक्नोलॉजी सभा पुरस्कार तथा ई-गव राजस्थान पुरस्कार सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से भी सम्मानित।

ये सम्मान सुशासन, सेवा वितरण तथा नागरिक सहभागिता को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुदृढ़ बनाने की दिशा में एनआईसी राजस्थान के निरंतर प्रयासों एवं उत्कृष्ट योगदान का प्रमाण हैं।

अग्रिम राह

एनआईसी राजस्थान नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न एप्लीकेशन आर्किटेक्चर को अपनाकर अगली पीढ़ी के डिजिटल गवर्नेंस इनिशिएटिव पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। फाइनेंस, हेल्थकेयर और एजुकेशन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए एआई-इनेबल्ड सॉल्यूशन विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम से काम की जानकारी प्राप्त करने के लिए एडवांस्ड डेटा एनालिटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। सेंटर नागरिकों पर केंद्रित मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से एम-गवर्नेंस का विस्तार भी कर रहा है और माइक्रोसर्विसेज-आधारित आर्किटेक्चर में बदलाव करके प्रमुख ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म को आधुनिक बना रहा है, जिससे स्केलेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी और सर्विस रेजिलिएंस में सुधार हो रहा है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी राजस्थान
8318, एनडब्ल्यू ब्लॉक, सचिवालय
जयपुर – 302005, राजस्थान
ईमेल: sioraj@nic.in, फ़ोन: 0141-2227992

त्रिपुरा

एकीकृत डिजिटल सुशासन पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

संपादित : **लाल बहादुर सिंह**

भौगोलिक दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा राज्य होने के बावजूद त्रिपुरा ने वित्त, भूमि प्रशासन, परिवहन, न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनकल्याण सेवाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक सुदृढ़ डिजिटल सुशासन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है। एनआईसी त्रिपुरा राज्य केंद्र ने राज्य सरकार के साथ साझेदारी में ऐसे अनेक डिजिटल मंच विकसित एवं कार्यान्वित किए हैं, जिन्होंने सुशासन को सुव्यवस्थित बनाया है तथा सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया है।

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पहलों के क्रियान्वयन के साथ-साथ एनआईसी त्रिपुरा ने राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक राज्य-विशिष्ट अनुप्रयोग भी विकसित किए हैं। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), भूमि अभिलेख, पेपरलेस कार्यालय, डिजिटल खरीद, परिवहन सेवाओं तथा एकीकृत न्याय प्रणाली जैसे क्षेत्रों में विकसित इन मंचों ने एक परस्पर जुड़ा हुआ सुशासन पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया है, जो निर्बाध सूचना आदान-प्रदान तथा सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।

यह लेख प्रमुख क्षेत्रों में एनआईसी त्रिपुरा द्वारा कार्यान्वित प्रमुख आईसीटी पहलों तथा इन सेवाओं को समर्थ बनाने वाली डिजिटल अवसंरचना का परिचय प्रस्तुत करता है।

वित्त

लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली

लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, त्रिपुरा द्वारा विकसित एक प्रमुख डिजिटल मंच है, जो एकीकृत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पारितंत्र के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाने का कार्य करता है। मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकी पर आधारित यह क्लाउड-सक्षम मंच नागरिक पंजीकरण, योजना में नामांकन, पात्रता निर्धारण, लाभ वितरण तथा वितरण उपरांत निगरानी तक संपूर्ण लाभार्थी जीवनचक्र के लिए एक समग्र और कागजरहित सेवा वितरण व्यवस्था उपलब्ध कराता है। परिवार-आधारित मानचित्रण तथा डुप्लीकेट अभिलेखों की पहचान की तकनीक के माध्यम से यह प्रणाली लाभार्थियों की सटीक पहचान सुनिश्चित करती है, दोहराव को रोकती है तथा जनकल्याण योजनाओं के वितरण में पारदर्शिता बढ़ाती है।

यह प्रणाली लचीले और विस्तार योग्य स्वरूप में विकसित की गई है। इसमें ऑनलाइन लाभार्थी पंजीकरण, योजनाओं का समावेशन, पात्रता एवं अधिकार निर्धारण, आवेदन प्रसंस्करण तथा वास्तविक समय आधारित डैशबोर्ड जैसी सभी सुविधाएँ एकीकृत रूप से उपलब्ध हैं। यह राज्य कोषागार, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, डिजिलॉकर, उमंग, मेरी पहचान तथा अन्य डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचनाओं के साथ एकीकृत है। इसके माध्यम से आधार, बैंक खाते तथा ई-रुपी आधारित सुरक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण संभव हुआ है। इसके अतिरिक्त यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैंक खाते का सत्यापन, आधार वॉल्ट आधारित टोकनीकरण, वस्तु के रूप में लाभ वितरण तथा पुराने आँकड़ों के स्थानांतरण जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराती है, जिससे विभाग अपनी पूर्ववर्ती योजनाओं को भी आसानी से इस मंच पर जोड़ सकते हैं।

वर्तमान में यह प्रणाली राज्य के 30 सरकारी विभागों की 73 जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है और लगभग 40 लाख नागरिकों को लाभान्वित कर चुकी है। इसके माध्यम से 37.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लेनदेन संपन्न किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 656 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों तक पहुँचाई गई है। इस प्रणाली ने जनकल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही को उल्लेखनीय रूप से सुदृढ़ किया है। डिजिटल सुशासन में इसके उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे वर्ष 2021-22 का मुख्यमंत्री सिविल सेवा पुरस्कार, वर्ष 2024 का 15वाँ राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार तथा वर्ष 2025 का ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

नेक्स्टजेन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली

नेक्स्टजेन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, त्रिपुरा द्वारा विकसित एक व्यापक, क्लाउड-सक्षम डिजिटल प्रणाली है, जो सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति से लेकर सेवानिवृत्ति तक संपूर्ण सेवा जीवनचक्र का डिजिटलीकरण करती

> एक पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य, त्रिपुरा ने एनआईसी राज्य केंद्र के तहत एक व्यापक डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम विकसित किया है। वित्त, परिवहन, राजस्व, न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के वितरण तक फैले बीएमएस, ई-ग्रास, आर.सी.एम.एस, ई-डिस्ट्रिक्ट और ई-कोर्ट जैसे प्लेटफॉर्मों ने पारदर्शिता, दक्षता और नागरिकों की पहुंच को मजबूत किया है। एनकेएन, टीस्वान और मिनी क्लाउड जैसे मजबूत नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इस इकोसिस्टम को एक ठोस आधार प्रदान करते हैं। पुरस्कार विजेता प्रणालियां और मजबूत अंतर-विभागीय एकीकरण, एक कनेक्टेड और प्रौद्योगिकी-सक्षम गवर्नेंस मॉडल की दिशा में त्रिपुरा के बढ़ते कदम को दर्शाते हैं।

अचिन्त्य कुमार दे
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
ak.de@nic.in

पिनाकी आचार्य
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एएसआईओ
pinaki.a@nic.in

है। यह एकीकृत मंच सरकारी विभागों को कर्मचारी अभिलेख, सेवा पुस्तिका, वेतन, अवकाश, स्थानांतरण, पदोन्नति, पेंशन तथा अन्य कार्मिक संबंधी कार्यों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। इससे प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता और सेवा वितरण में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

यह प्रणाली कर्मचारियों की ऑनलाइन नियुक्ति, डिजिटल सेवा पुस्तिका, अवकाश एवं उपस्थिति प्रबंधन, वेतन और अन्य सेवा लाभों का प्रबंधन, स्थानांतरण एवं पदोन्नति, पेंशन प्रसंस्करण तथा कर्मचारी स्व-सेवा पोर्टल जैसी सुविधाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध कराती है। विन्यास योग्य कार्यप्रवाह, डिजिटल अनुमोदन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर तथा वास्तविक समय के डैशबोर्ड के माध्यम से यह प्रणाली कागजरहित कार्यप्रणाली को बढ़ावा देती है, निर्णय प्रक्रिया को तेज बनाती है तथा मानव संसाधन नियोजन को अधिक प्रभावी बनाती है। साथ ही कर्मचारी अपनी सेवा से संबंधित जानकारी का ऑनलाइन अवलोकन एवं प्रबंधन भी कर सकते हैं।

वर्तमान में राज्य के 68 सरकारी विभाग इस प्रणाली से जुड़े हैं, जिनके लगभग 88,740 कर्मचारियों की डिजिटल सेवा पुस्तिकाएँ इसमें उपलब्ध हैं। इस प्रणाली के माध्यम से अब तक 3.54 लाख से अधिक मासिक वेतन बिल तैयार किए जा चुके हैं, 1.36 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए गए हैं तथा 2,000 से अधिक कार्यालय आदेशों का डिजिटल प्रसंस्करण किया जा चुका है। यह उपलब्धियाँ सार्वजनिक क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबंधन के आधुनिकीकरण में इसकी व्यापक उपयोगिता और प्रभावशीलता को दर्शाती हैं।

इस प्रणाली की एक विशेषता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विसंगति एवं धोखाधड़ी पहचान तंत्र है, जो बुद्धिमान नियमों तथा व्यवहार विश्लेषण के माध्यम से संदिग्ध लेनदेन, दोहराए गए भुगतान, अपात्र दावों, काल्पनिक कर्मचारियों तथा नीतिगत अनियमितताओं की पहचान करता है। वास्तविक समय के अलर्ट और विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड की सहायता से यह सुविधा सुशासन को सुदृढ़ करती है, वित्तीय जवाबदेही बढ़ाती है तथा विभागों को सार्वजनिक धन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने से पहले ही अनियमितताओं की रोकथाम में सहायता प्रदान करती है।

राज्य प्राप्ति पोर्टल

राज्य प्राप्ति पोर्टल, त्रिपुरा सरकार के कोषागार तथा 32 गैर-कोषागार प्राप्ति खातों के लिए विकसित एक एकीकृत ऑनलाइन राजस्व प्राप्ति मंच है। यह विभिन्न डिजिटल भुगतान माध्यमों का समर्थन करता है तथा परिवहन, न्यायपालिका, राजस्व और अन्य सरकारी विभागों की अनेक डिजिटल प्रणालियों के साथ एकीकृत है। जुलाई 2025 तक इस पोर्टल के माध्यम से 10.83 लाख से अधिक लेनदेन संपन्न किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से 28 एकीकृत अनुप्रयोगों के जरिए 5,786 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व संग्रह किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर प्रबंधन विश्लेषण प्रणाली

वस्तु एवं सेवा कर प्रबंधन विश्लेषण प्रणाली एक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड है, जो राज्य के कर प्रशासकों को अपने अधिकार क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह तथा अनुपालन की प्रभावी निगरानी करने में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ कार्यरत वस्तु एवं सेवा कर लेखांकन सूचना एवं द्वि-पक्षीय समाधान प्रणाली, वित्त विभाग तथा महालेखाकार, त्रिपुरा को वस्तु एवं सेवा कर के लेखांकन एवं मिलान संबंधी कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। ये दोनों प्रणालियाँ आँकड़ा-आधारित निगरानी और प्रभावी वित्तीय समन्वय के माध्यम से कर प्रशासन को अधिक सुदृढ़ बनाती हैं।

▲ चित्र 3.1 : तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, त्रिपुरा श्री जिष्णु देव वर्मा ने 6 अक्टूबर 2022 को त्रिपुरा सरकार के वित्त विभाग के आबकारी संगठन हेतु एनआईसी द्वारा विकसित 'ई-आबकारी' पोर्टल का उद्घाटन किया

ई-प्रापण

सरकारी ई-प्रापण प्रणाली को केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के अंतर्गत लागू किया गया है, जिसके माध्यम से निविदा प्रकाशन, संशोधन, ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना तथा अनुबंध प्रदान करने जैसी संपूर्ण प्रक्रियाएँ डिजिटल रूप से संचालित की जाती हैं। वर्ष 2013 से अब तक राज्य ई-प्रापण पोर्टल पर 53,634 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 62,688 निविदाएँ प्रकाशित की जा चुकी हैं। वर्ष 2020 से राज्य को राष्ट्रीय ई-नीलामी पोर्टल से भी जोड़ा गया है, जिसका उपयोग राज्य वन विभाग तथा संस्थागत वित्त निदेशालय द्वारा अग्रिम और विपरीत नीलामी के संचालन के लिए किया जा रहा है।

ई-आबकारी

ई-आबकारी, आबकारी विभाग के लिए विकसित एक समग्र डिजिटल प्रणाली है, जो ऑनलाइन लाइसेंस जारी करने, आयात परमिट, लेबल पंजीकरण, भंडार प्रबंधन तथा मासिक विवरणियों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण जैसी सुविधाएँ प्रदान करती है। इस प्रणाली के माध्यम से अब तक 22.81 करोड़ से अधिक लेनदेन संपन्न किए जा चुके हैं। इसके परिणामस्वरूप आबकारी प्रशासन में कार्यकुशलता, पारदर्शिता तथा नियामकीय अनुपालन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

स्वास्थ्य

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, डिजिटल इंडिया की एक प्रमुख पहल है, जो नागरिकों को सरकारी अस्पतालों की बाह्य रोगी सेवाओं तक पहुँच के लिए एकीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराती है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के मानकों के अनुरूप विकसित यह प्रणाली ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, प्रयोगशाला जाँच रिपोर्ट एवं ई-प्रिस्क्रिप्शन की उपलब्धता, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता एकीकरण, अनुवर्ती परामर्श प्रबंधन तथा दूरस्थ चिकित्सकीय परामर्श जैसी सुविधाएँ प्रदान करती है। यह प्रणाली भारत के डिजिटल स्वास्थ्य पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है और देशभर के हजारों सरकारी अस्पतालों को जोड़ते हुए नागरिक-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं की सहज उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

▼ चित्र 3.2 : ई-ग्रास वेबसाइट होम पेज

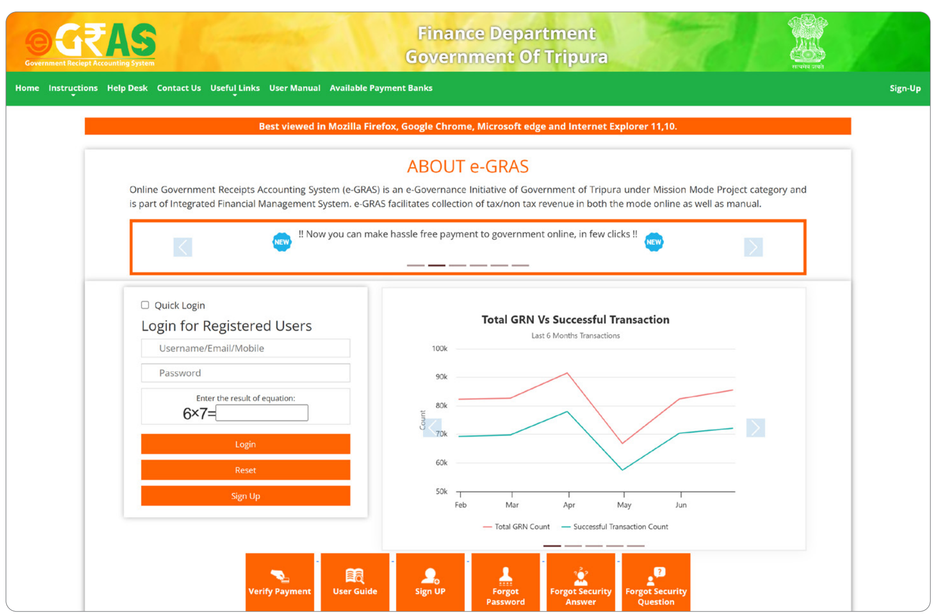

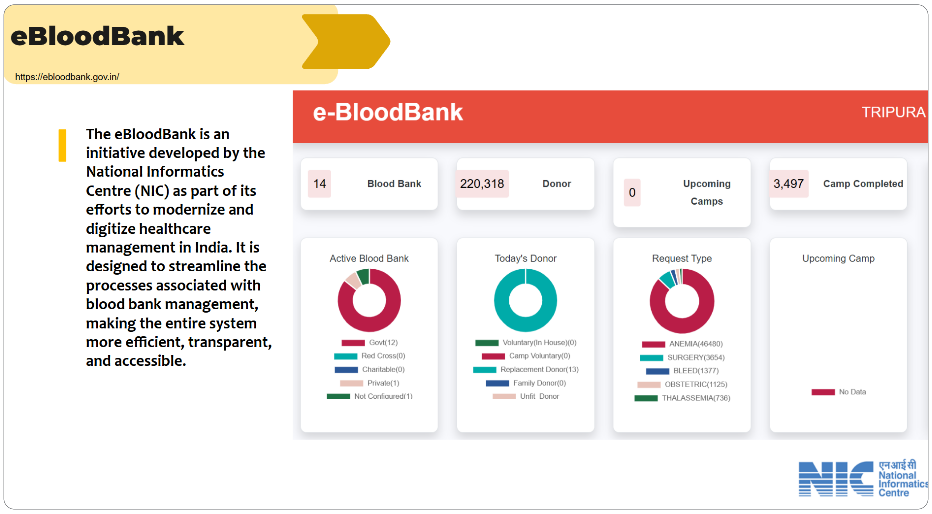

▲ चित्र 3.3 : ई-ब्लडबैंक वेबसाइट का डैशबोर्ड

ई-अस्पताल

ई-अस्पताल एक व्यापक अस्पताल सूचना प्रबंधन प्रणाली है, जो स्वास्थ्य संस्थानों में चिकित्सकीय, नैदानिक, प्रशासनिक तथा रोगी सेवाओं से जुड़ी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करती है। त्रिपुरा में इसके सफल क्रियान्वयन के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, त्रिपुरा राज्य केंद्र ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में ई-अस्पताल के स्थानीय संस्करण के विकास एवं संचालन में भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय योगदान दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत पूर्णतः डिजिटल बनने वाला यह देश का पहला सार्वजनिक अस्पताल है। यह प्रणाली देश के सबसे व्यस्त स्वास्थ्य संस्थानों में से एक का संचालन समर्थ बनाती है, जहाँ प्रतिदिन 10,000 से अधिक रोगियों का पंजीकरण, 15,000 से अधिक बाह्य रोगी अपॉइंटमेंट तथा लगभग एक लाख प्रयोगशाला जाँचें संपन्न होती हैं। यह इसकी व्यापक क्षमता, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता का प्रमाण है।

ई-रक्त बैंक

ई-रक्त बैंक प्रणाली रक्त बैंकों की कार्यप्रणाली को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाने के लिए विकसित की गई है। यह रक्तदाता पंजीकरण, रक्त संग्रह, भंडार प्रबंधन, परीक्षण तथा रक्त इकाइयों के निर्गमन जैसी संपूर्ण प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करती है। इसके माध्यम से रक्त सेवाओं की उपलब्धता, पारदर्शिता और कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों को रक्त भंडार का बेहतर प्रबंधन करने तथा आवश्यकता के समय रोगियों को शीघ्र सहायता उपलब्ध कराने में सुविधा मिली है।

परिवहन

एनआईसी त्रिपुरा ने वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण निगरानी, यातायात प्रवर्तन तथा नागरिक सेवाओं को शामिल करते हुए प्रमुख डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों के कार्यान्वयन के माध्यम से परिवहन प्रशासन का आधुनिकीकरण किया है। राज्य के सभी जिला परिवहन कार्यालयों में संचालित वाहन एवं सारथी प्लेटफ़ॉर्म ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट तथा फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाते हैं। अगस्त 2025 तक इन प्लेटफ़ॉर्मों के माध्यम से 8.47 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण तथा 6.08 लाख से अधिक ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं। पी.यू.सी.सी प्रणाली 189 केंद्रों के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पी.यू.सी.सी) के निर्गमन एवं निगरानी का डिजिटलीकरण करती है, जिसके अंतर्गत 18.59 लाख से अधिक प्रमाण-पत्र जारी किए जा चुके हैं। ई-चालान, जो वर्चुअल कोर्ट के साथ एकीकृत है, इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी करने तथा यातायात उल्लंघनों के ऑनलाइन निस्तारण के माध्यम से यातायात कानूनों के प्रभावी प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाता है। इसके अंतर्गत 22.22 लाख से अधिक चालान जारी किए जा चुके हैं। नागरिक एम-परिवहन मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न परिवहन सेवाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी पहलों ने सेवा वितरण को सरल बनाया है, नियामकीय अनुपालन को सुदृढ़ किया है तथा राज्यभर में परिवहन सेवाओं को अधिक सुलभ बनाया है।

कार्यालय उत्पादकता

ई-राजपत्र

ई-राजपत्र मंच त्रिपुरा सरकार के राजपत्रों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों, शासनादेशों, राजपत्र अधिसूचनाओं, परिपत्रों तथा अन्य वैधानिक दस्तावेजों का एक केंद्रीकृत डिजिटल भंडार है। यह नागरिकों, सरकारी अधिकारियों तथा अन्य हितधारकों को एक ही मंच पर प्रमाणित सरकारी प्रकाशनों तक सरल और सुविधाजनक पहुँच उपलब्ध कराता है। यह पहल केंद्रीय मंत्रिमंडल सचिवालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुपालन सरलीकरण एवं विनियमन-उन्मूलन पहल (द्वितीय चरण) के अनुरूप है तथा पारदर्शिता, सुगमता और कागजरहित प्रशासन को बढ़ावा देती है। इस मंच में सरकारी दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण, परीक्षण, अनुमोदन तथा प्रकाशन के लिए सुरक्षित कार्यप्रवाह की व्यवस्था है, जिससे केवल प्रमाणित दस्तावेज ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाते हैं। इसकी एक प्रमुख विशेषता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सहायक है, जो उपयोगकर्ताओं को पारंपरिक कुंजीशब्द आधारित खोज के स्थान पर स्वाभाविक भाषा में प्रश्न पूछकर सरकारी प्रकाशनों में आवश्यक जानकारी खोजने की सुविधा प्रदान करता है। यह सहायक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, अर्थ-आधारित खोज तथा रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन तकनीकों का उपयोग करते हुए स्कैन किए गए तथा डिजिटल दोनों प्रकार के दस्तावेजों से प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे विधिक एवं प्रशासनिक सूचनाओं तक पहुँच पहले की तुलना में कहीं अधिक सरल और प्रभावी हो गई है।

स्थिर सरकारी प्रकाशनों को एक बुद्धिमान और खोजयोग्य ज्ञान भंडार में परिवर्तित कर यह मंच प्रमाणिक सूचनाओं तक सार्वजनिक पहुँच को सुदृढ़ करता है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाता है तथा राज्य के डिजिटल सुशासन पारितंत्र को और अधिक मजबूत बनाता है।

ई-ऑफिस त्रिपुरा

ई-ऑफिस त्रिपुरा ने अपने कार्यप्रवाह-आधारित ई-फाइल सिस्टम के माध्यम से सरकारी फाइल प्रबंधन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया है, जिससे ग्राम पंचायतों एवं ग्राम समितियों सहित 2,536 सरकारी कार्यालयों और निदेशालयों में पेपरलेस कार्यप्रणाली को बढ़ावा मिला है। वर्ष 2017 में इसके कार्यान्वयन के बाद से यह प्लेटफ़ॉर्म 17,700 से अधिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान कर चुका है, जिससे आधिकारिक पत्राचार की गति एवं दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। स्पैरो प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली को लगभग 850 त्रिपुरा सिविल सेवा अधिकारियों के लिए भी लागू किया गया है, जबकि स्पैरो (आईपीआर) के अंतर्गत अन्य राज्य संवर्ग सेवाओं के 5,500 से अधिक अधिकारी शामिल हैं।

ई-मंत्रिमंडल

कागजरहित शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से त्रिपुरा सरकार ने सितंबर 2023 में मंत्रिमंडल बैठकों के डिजिटल प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ई-मंत्रिमंडल प्रणाली को अपनाया। यह मंच मंत्रिमंडल संबंधी ज्ञापनों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, परीक्षण तथा अनुमोदन की सुविधा

▼ चित्र 3.4 : माननीय मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा द्वारा 27 सितम्बर, 2023 को अगरतला में एनआईसी के ई-कैबिनेट समाधान का शुभारंभ किया गया

प्रदान करता है और पारंपरिक कागजी प्रक्रिया का स्थान सुरक्षित डिजिटल कार्यप्रवाह से लेता है। इसके कार्यान्वयन के साथ त्रिपुरा इस प्रणाली को अपनाने वाला देश का चौथा तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र का दूसरा राज्य बन गया। यह पहल राज्य में ई-कार्यालय के व्यापक उपयोग को सुदृढ़ करते हुए पारदर्शी, दक्ष और पर्यावरण-अनुकूल शासन व्यवस्था को बढ़ावा देती है।

त्रिपुरा दर्पण

वर्ष 2017 में प्रारंभ किया गया त्रिपुरा दर्पण मुख्यमंत्री तथा जिला मजिस्ट्रेटों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक समय पर निगरानी के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध कराता है। जिला मजिस्ट्रेट डैशबोर्ड राज्य के सभी आठ जिलों में लागू किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 19 प्रमुख सरकारी योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की निगरानी के लिए एकीकृत विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड उपलब्ध हैं, जो तथ्य-आधारित और प्रभावी निर्णय-निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं।

स्वागतम्

स्वागतम् एक ऑनलाइन आगंतुक प्रबंधन प्रणाली है, जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए ऑनलाइन समय निर्धारित कर सकते हैं। वर्तमान में यह सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा सचिवालय प्रशासन विभाग में लागू है और लगभग 200 अधिकारियों को इससे जोड़ा जा चुका है। इस पहल के पूरक के रूप में आधार-सक्षम बायोमीट्रिक उपस्थिति प्रणाली राज्य के 82 सरकारी कार्यालयों में लागू की गई है, जिसके अंतर्गत लगभग 14,300 अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हैं।

कार्यपालक सेवा अभिलेख

कार्यपालक सेवा अभिलेख प्रणाली त्रिपुरा सिविल सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा तथा अन्य 23 राज्य संवर्गीय सेवाओं के अधिकारियों के सेवा अभिलेखों का डिजिटल भंडार है। वर्तमान में इस प्रणाली में 5,800 से अधिक अधिकारियों के अभिलेख सुरक्षित हैं। साथ ही, सेवा संबंधी विवरणों के समय पर अद्यतन के लिए संदेश और ई-मेल आधारित सूचना सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रवेशद्वार

त्रिपुरा का इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रवेशद्वार उन्नत संगणन विकास केंद्र की इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर सेवा के साथ एकीकृत है। इसके माध्यम से ई-कार्यालय, स्पैरो, लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली, ई-जमी तथा ई-जिला सहित अनेक प्रमुख ई-शासन अनुप्रयोगों में सुरक्षित डिजिटल हस्ताक्षर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके कार्यान्वयन के बाद से 12.20 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए जा चुके हैं, जिससे कागजरहित प्रशासन और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन को उल्लेखनीय बल मिला है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली

राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली राज्य में राशन कार्डों के प्रबंधन के लिए आधारभूत डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करती है। यह परिवार के सदस्यों को जोड़ने, हटाने, विभाजित करने, स्थानांतरित करने तथा अभिलेखों के अद्यतन जैसी सभी सेवाएँ एक ही मंच पर उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली तथा आधार-सक्षम इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रणाली के साथ एकीकृत है,

▲ चित्र 3.5 : फीस्ट वेबसाइट का होम पेज

जिससे लाभार्थियों की सटीक पहचान सुनिश्चित होती है और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है। वर्तमान में इसमें 9.90 लाख से अधिक राशन कार्ड परिवारों तथा 37.08 लाख से अधिक सदस्यों का विवरण उपलब्ध है। परिवार के सभी मुखियाओं का आधार से शत-प्रतिशत सत्यापन भी सुनिश्चित किया जा चुका है।

खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली

खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम के गोदामों तथा अन्य खरीद केंद्रों से उचित मूल्य की दुकानों तक खाद्यान्न की आपूर्ति का डिजिटलीकरण करती है, जिससे संपूर्ण सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक समय पर निगरानी संभव हो पाती है। इसके साथ कार्यरत उचित मूल्य दुकान स्वचालन प्रणाली आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बिक्री केंद्र उपकरणों का उपयोग करते हुए लाभार्थियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करती है। इन प्रणालियों के लागू होने के बाद से 7.81 लाख से अधिक आपूर्ति चालान एवं प्राप्ति रसीदों का प्रसंस्करण किया जा चुका है तथा 2,070 से अधिक उचित मूल्य की दुकानों पर 99.2 प्रतिशत आधार-प्रमाणित वितरण सुनिश्चित किया गया है। इससे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

धान खरीद प्रणाली

धान खरीद प्रणाली किसानों के सत्यापन के लिए राशन कार्ड और भू-अभिलेखों का एकीकरण करती है। यह प्रणाली देय राशि की स्वचालित गणना करती है तथा लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए भुगतान सुनिश्चित करती है। वर्ष 2021 के खरीफ विपणन सत्र से अब तक इस प्रणाली में 1.17 लाख से अधिक किसानों का पंजीकरण किया जा चुका है। इसके माध्यम से 2.25 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की गई है तथा 446 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है।

राजस्व

ई-जिला त्रिपुरा

सेवाप्लस मंच पर विकसित ई-जिला त्रिपुरा नागरिकों को एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाएँ उपलब्ध कराता है। इस मंच पर 16 प्रकार के प्रमाण-पत्रों एवं लाइसेंसों के साथ-साथ विधिक मापविज्ञान, गृह (अग्निशमन), उद्योग, वन तथा भू-अभिलेख जैसे विभागों से संबंधित 21 अतिरिक्त लाइसेंस एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाते हैं। यह प्रणाली राज्य प्राप्ति पोर्टल, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, डिजिलॉकर,

▼ चित्र 3.6 : एआई असिस्टेंट सहित त्रिपुरा ई-गज़ट वेबसाइट का होम पेज

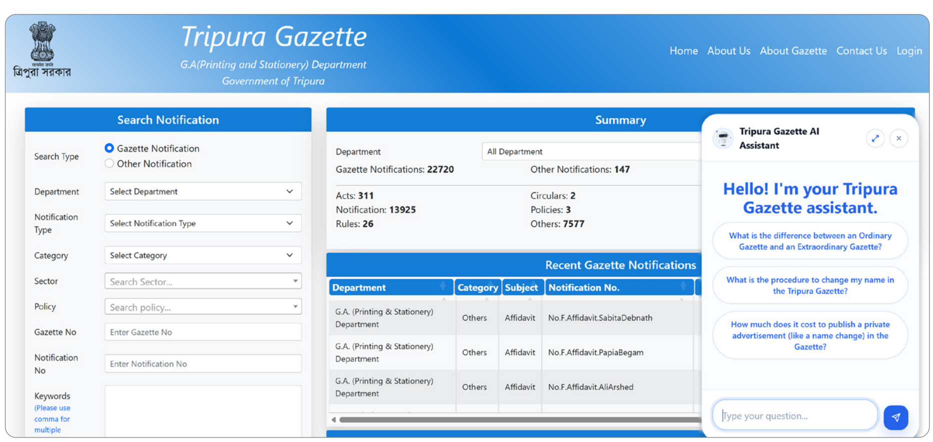

साझा सेवा केंद्र तथा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत है। साथ ही, यह गृह मंत्रालय के सहयोग से ब्रू प्रवासियों के पुनर्वास संबंधी भुगतान का भी प्रबंधन करती है। वर्ष 2015 में प्रारंभ होने के बाद से इस पोर्टल पर 8.20 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 8.12 लाख से अधिक आवेदनों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया जा चुका है।

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, त्रिपुरा ने भू-प्रशासन के लिए एक समेकित डिजिटल पारितंत्र विकसित किया है। इसमें ई-जमी के माध्यम से भू-अभिलेख, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली तथा वेब-आधारित भू-मानचित्रण प्रणाली को एकीकृत किया गया है। इन प्रणालियों ने भूमि पंजीकरण और नामांतरण की प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाया है। अब तक 4.13 लाख से अधिक दस्तावेजों का ऑनलाइन पंजीकरण, 8.12 लाख से अधिक नामांतरण मामलों का निस्तारण, 13.67 लाख से अधिक अधिकार अभिलेख प्रतियों तथा 2.21 लाख से अधिक प्रमाणित भू-मानचित्रों का निर्गमन किया जा चुका है।

इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प भंडार

इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प भंडार, इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प पत्रों के सत्यापन, उपयोग तथा मिलान के लिए विकसित एक सुरक्षित डिजिटल मंच है। यह राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, पंजीकरण पोर्टल तथा राज्य प्राप्ति पोर्टल के साथ एकीकृत है, जिससे स्टाम्प शुल्क और इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प से संबंधित लेनदेन का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित होता है। वर्ष 2019 से अब तक इस प्रणाली के माध्यम से 36 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्प का प्रसंस्करण किया जा चुका है तथा 436 करोड़ रुपये से अधिक का स्टाम्प शुल्क संग्रहित किया गया है। इससे स्टाम्प प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है।

भू-प्रशासन

ई-जमी

ई-जमी डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्व विभाग, त्रिपुरा सरकार के लिए विकसित एक वेब-आधारित एकल-खिड़की प्रणाली है। यह राज्य की आधिकारिक डिजिटल भू-अभिलेख प्रणाली के रूप में कार्य करती है और पारंपरिक हस्तलिखित अभिलेखों के स्थान पर सुरक्षित डिजिटल कार्यप्रवाह उपलब्ध कराती है। इसके माध्यम से नागरिकों को डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अधिकार अभिलेख की प्रतियाँ, ऑनलाइन नामांतरण की स्थिति, भू-मानचित्र का अवलोकन, भूखंड के इतिहास का सत्यापन तथा भूमि मापन इकाइयों के रूपांतरण जैसी सुविधाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर एकीकरण

ई-जामी को राजस्व प्रशासन से आगे बढ़कर प्रमाणीकृत भूमि अभिलेखों के उपयोग का विस्तार करने के लिए अनेक राष्ट्रीय डिजिटल पहलों के साथ एकीकृत किया गया है।

- **एग्रीस्टैक**: डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए फार्मप्लॉट आईडी सृजन, यूनिफाइड लैंड एपीआई इंटीग्रेशन तथा भू-स्थानिक डेटा का आदान-प्रदान।
- **पीएम गति शक्ति:** अवसंरचना नियोजन को समर्थन देने के लिए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तथा भू-स्थानिक डेटा का एकीकरण।
- **आरबीआईएच यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस**: डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के लिए भूखंड एवं स्वामित्व का स्वचालित सत्यापन, साथ ही दोहरे वित्तपोषण को रोकने के लिए फ्लैग-मार्किंग की सुविधा।
- **सीएलयू पोर्टल:** भूमि डायवर्जन (यूएस-20) अनुरोधों का ऑनलाइन प्रसंस्करण।

सरकारी प्रणालियों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी

विभिन्न विभागों के बीच निर्बाध सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई-जामी अनेक सरकारी प्लेटफ़ॉर्मों के साथ डेटा का आदान-प्रदान करता है।

- **उन्नति पोर्टल:** भूखंड स्वामित्व सत्यापन, नामांतरण सेवाएँ, राजस्व न्यायालय मामलों का पंजीकरण, वाद की स्थिति की ट्रैकिंग तथा विलेख संबंधी जानकारी।
- **नक्शा:** शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए भूमि अभिलेख एवं भू-स्थानिक डेटा का साझा उपयोग।
- **विभागीय एपीआई:** शहरी विकास, डीडब्ल्यूएस, टीएसईसीएल, सिविल न्यायालय, ई-डिस्ट्रिक्ट, स्वागतम, सीएससी, जनजातीय कल्याण विभाग तथा राजस्व न्यायालयों के साथ एकीकरण, जिससे बिज़नेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (BRAP) के अंतर्गत विभिन्न पहलों को समर्थन प्राप्त होता है।

वन अधिकार प्रबंधन

एनआईसी त्रिपुरा ने वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समर्पित अनुप्रयोग भी विकसित किए हैं।

- **फॉरेस्ट राइट्स:** यह मंच वन अधिकार पट्टों का आधिकारिक डेटाबेस संधारित करता है, जिसमें भूमि का विवरण, पट्टा निर्गमन तथा प्रमाण-पत्र जनरेशन से संबंधित जानकारी शामिल होती है।
- **मायपट्टा:** यह मंच वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अस्वीकृत दावों का आधिकारिक रिपॉजिटरी है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप वैधानिक रिपोर्टिंग, न्यायिक एवं प्रशासनिक अनुपालन, निगरानी तथा ऐतिहासिक अभिलेखों के पुनर्प्राप्ति कार्य में सहायता प्रदान करता है।

गृह एवं न्याय

ई-न्यायालय

ई-न्यायालय प्रकरण सूचना प्रणाली ने त्रिपुरा के सभी न्यायालयों में न्यायिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण किया है। इसके माध्यम से वादों की स्थिति, वाद सूची, न्यायालय के आदेश, निर्णय तथा स्वचालित सूचनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैं। यह प्रणाली राज्य के सभी आठ जिलों के 16 न्यायालय परिसरों में स्थित 82 न्यायालयों में संचालित है। इसके साथ राष्ट्रीय सेवा एवं प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग प्रणाली, ई-फाइलिंग, ई-भुगतान तथा आभासी न्यायालय जैसी सेवाएँ भी एकीकृत हैं, जिनसे नागरिकों और वादकारियों को न्यायिक सेवाएँ अधिक सरलता और सुविधा के साथ उपलब्ध हो रही हैं। अगस्त 2025 तक इस प्रणाली में 1.94 लाख से अधिक वाद पंजीकृत किए जा चुके थे, जिनमें से 1.51 लाख से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है।

ई-अभियोजन

ई-अभियोजन प्रणाली पुलिस और अभियोजन विभाग के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाती है। इसके माध्यम से आरोप-पत्रों की इलेक्ट्रॉनिक जाँच, विधिक अभिमत तथा प्रकरणों की प्रगति का डिजिटल प्रबंधन किया जाता है। अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली तथा ई-न्यायालय के साथ एकीकृत यह प्रणाली राज्य के सभी आठ जिलों में संचालित है। डिजिटल कार्यप्रवाह और वास्तविक समय में सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से इसने अभियोजन प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया है।

ई-विधि विज्ञान

ई-विधि विज्ञान प्रणाली राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला के कार्यों का डिजिटलीकरण करती है। इसके माध्यम से प्रकरणों का पंजीकरण, वैज्ञानिक परीक्षण की प्रक्रियाएँ तथा परीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने का कार्य ऑनलाइन संचालित किया जाता है। अगस्त 2025 तक इस प्रणाली में 12,200 से अधिक विधि विज्ञान संबंधी प्रकरण पंजीकृत किए जा चुके थे, जिससे उनकी प्रभावी निगरानी और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हुआ है।

ई-कारागार

ई-कारागार एक क्लाउड-आधारित कारागार प्रबंधन प्रणाली है, जिसे राज्य की सभी 13 जेलों में लागू किया गया है। यह प्रणाली बंदियों के प्रबंधन, आगंतुकों के अनुरोध, शिकायत निवारण तथा आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े विभिन्न संस्थानों के बीच सूचना के आदान-प्रदान को डिजिटल माध्यम से संचालित करती है। इससे कारागार प्रशासन अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और दक्ष बना है।

अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली

अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली, ई-न्यायालय, ई-कारागार, ई-विधि विज्ञान तथा ई-अभियोजन जैसी विभिन्न प्रणालियों को "एक डेटा, एक प्रविष्टि" के सिद्धांत पर एकीकृत करती है। यह विभिन्न न्यायिक एवं कानून प्रवर्तन संस्थाओं के बीच सुरक्षित सूचना आदान-प्रदान सुनिश्चित करती है, जिससे दोहराव समाप्त होता है, विभागीय समन्वय बेहतर होता है तथा संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रक्रिया में तथ्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

आव्रजन, वीज़ा एवं विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग प्रणाली

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, त्रिपुरा राज्य केंद्र, गृह मंत्रालय की महत्त्वपूर्ण मिशन मोड परियोजना आव्रजन, वीज़ा एवं विदेशी पंजीकरण एवं ट्रैकिंग प्रणाली के संचालन में भी सहयोग प्रदान

▼ चित्र 3.7 : क्षेत्रीय टेक सक्षम कार्यशाला के दौरान त्रिपुरा के मुख्य सचिव द्वारा मुख्य वक्तव्य दिया गया

करता है। इस प्रणाली के माध्यम से विदेशी नागरिकों का ऑनलाइन पंजीकरण, विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय की सेवाएँ, संस्थागत एस-फॉर्म एवं सी-फॉर्म, ऑनलाइन नागरिकता आवेदन, राष्ट्रीयता सत्यापन, वीज़ा सुरक्षा अनुमति तथा श्री करतारपुर साहिब तीर्थयात्रा पंजीकरण जैसी अनेक सेवाएँ डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

शिक्षा

ई-परामर्श

ई-परामर्श प्रणाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों, संयुक्त प्रवेश परीक्षाओं, नर्सिंग तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एकीकृत ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली अभ्यर्थी पंजीकरण, शुल्क भुगतान, मेरिट सूची तैयार करने, परामर्श प्रक्रिया तथा सीट आवंटन सहित संपूर्ण प्रवेश प्रक्रिया का डिजिटल प्रबंधन करती है। इसके माध्यम से अब तक लगभग 5,000 संस्थानों में 1.10 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के प्रवेश सफलतापूर्वक संपन्न किए जा चुके हैं।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र प्रायोजित तथा राज्य सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक समग्र डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है। यह आवेदन प्राप्त करने, सत्यापन, अनुमोदन तथा छात्रवृत्ति वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल बनाता है। साथ ही, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से योजनाओं की प्रभावी निगरानी भी सुनिश्चित करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान इस पोर्टल पर 1.36 लाख से अधिक छात्रवृत्ति आवेदनों का प्रसंस्करण किया गया तथा 61.52 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई।

ई-ग्रंथालय

ई-ग्रंथालय एक क्लाउड-आधारित समेकित पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली है, जो सूचीकरण, पुस्तक निर्गमन एवं वापसी, डिजिटल पुस्तकालय सेवाओं तथा ऑनलाइन सार्वजनिक अभिगम सूची जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली त्रिपुरा के 70 से अधिक पुस्तकालयों में लागू की जा चुकी है, जिससे पुस्तकालय संसाधनों और डिजिटल ज्ञान सामग्री तक नागरिकों की पहुँच अधिक सरल और प्रभावी हुई है।

नेटवर्क एवं अवसंरचना सेवाएँ

एनआईसी त्रिपुरा राज्य केंद्र ने एक सुदृढ़, सुरक्षित और विश्वसनीय डिजिटल अवसंरचना विकसित की है, जो राज्य के डिजिटल सुशासन पारितंत्र की आधारशिला है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, त्रिपुरा राज्य व्यापक क्षेत्र नेटवर्क तथा अगरतला नगर क्षेत्र नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों, शैक्षणिक संस्थानों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थानों को निर्बाध नेटवर्क संपर्क उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्तमान में यह नेटवर्क लगभग 250 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, 6,000 राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क उपयोगकर्ताओं, 8,000 त्रिपुरा राज्य व्यापक क्षेत्र नेटवर्क उपयोगकर्ताओं तथा 4,100 से अधिक अगरतला नगर क्षेत्र नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को सेवाएँ प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, त्रिपुरा सचिवालय, उच्च न्यायालय, विधानसभा, राजभवन तथा अन्य प्रमुख सरकारी कार्यालयों को भी समर्पित नेटवर्क संपर्क उपलब्ध कराया गया है।

▲ चित्र 3.8 : क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह

राज्य के सभी आठ जिलों को एक गीगाबिट प्रति सेकंड क्षमता वाले प्राथमिक नेटवर्क तथा अलग इंटरनेट सेवा प्रदाता के माध्यम से समान क्षमता वाले वैकल्पिक नेटवर्क से जोड़ा गया है, जिससे सेवाओं की निरंतर उपलब्धता और व्यवधान की स्थिति में भी निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, त्रिपुरा राज्य केंद्र मिनी डाटा सेंटर, राज्य डाटा सेंटर, कंटेनर डाटा सेंटर तथा राष्ट्रीय डाटा सेंटर के माध्यम से 42 महत्त्वपूर्ण वेब अनुप्रयोगों की सुरक्षित और विश्वसनीय होस्टिंग भी उपलब्ध कराता है। साइबर सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए एंडपॉइंट सूचीकरण तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल पता प्रबंधन को राष्ट्रीय इंटरनेट प्रोटोकॉल पता प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का व्यापक नेटवर्क भी संचालित किया जा रहा है, जिसमें राज्य मुख्यालय तथा सभी जिला मुख्यालयों सहित 36 पंजीकृत स्टूडियो शामिल हैं। इस नेटवर्क के माध्यम से प्रतिवर्ष लगभग 1,600 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों, शासन, प्रशिक्षण तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

विकासाधीन अनुप्रयोग

त्रिपुरा के डिजिटल गवर्नेंस इकोसिस्टम को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित पहलें वर्तमान में विकासाधीन हैं:

- वामिस और ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के बीच द्वि-दिशात्मक इंटीग्रेशन, ताकि टेंडर बीओक्यू विवरण एवं चयनित बोलीदाता की दरों का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।
- **ई-वेंडर पोर्टल** – ठेकेदारों के संपूर्ण जीवनचक्र के एंड-टू-एंड प्रबंधन के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म, जिसमें निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध हैं:
  - पैन, जीएसटी-आईआरपी तथा बैंक अकाउंट एपीआई इंटीग्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन ठेकेदार पंजीकरण एवं सत्यापन
  - सुरक्षित एवं पेपरलेस बैंक गारंटी प्रोसेसिंग के लिए एन.ई.एस.एल इंटीग्रेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी का निर्माण
  - ऑनलाइन साइनिंग एवं सुरक्षित अभिलेखीकरण के साथ डिजिटल एग्रीमेंट प्रबंधन
  - कार्य एवं आपूर्ति आदेश प्रबंधन के लिए जेपनिक के साथ इंटीग्रेशन, जिससे ठेकेदार अपने आवंटित आदेश ऑनलाइन देख सकें
  - ऑनलाइन इनवॉइस जनरेशन, बिल सबमिशन तथा बिल की स्थिति की रियल-टाइम ट्रैकिंग
  - टेंडर आमंत्रित करने वाले प्राधिकरणों द्वारा लेटर ऑफ इंटेंट तैयार करने एवं एग्रीमेंट प्रबंधन के लिए विभागीय वर्कफ़्लो

उपलब्धियाँ

लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली को डिजिटल सुशासन तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है। इस प्रणाली को वर्ष 2021-22 का मुख्यमंत्री सिविल सेवा पुरस्कार, वर्ष 2024 का 15वाँ राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार तथा वर्ष 2025 का ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। ये सम्मान जनकल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी, दक्ष और व्यापक क्रियान्वयन में इस प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं।

अग्रिम राह

एनआईसी त्रिपुरा ने परस्पर कार्यक्षम (इंटरऑपरेबल) प्लेटफ़ॉर्म तथा सुदृढ़ आईसीटी अवसंरचना के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों को आपस में जोड़कर एकीकृत डिजिटल गवर्नेंस की मजबूत नींव तैयार की है। इस आधार को और सशक्त बनाते हुए अब डेटा-संचालित गवर्नेंस को बढ़ावा देने, नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने तथा विभिन्न सरकारी प्रणालियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को और सुदृढ़ करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सुरक्षित डिजिटल अवसंरचना, पेपरलेस प्रशासन तथा उभरती प्रौद्योगिकियों पर निरंतर बल देते हुए एनआईसी त्रिपुरा राज्य सरकार को पारदर्शी, दक्ष एवं सुलभ सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराने में अपना सहयोग जारी रखेगा तथा डिजिटल इंडिया के विज़न को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी त्रिपुरा राज्य केंद्र
ब्लॉक–4, तृतीय तल, नया सचिवालय भवन, न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स
खेजुरबागान, अगरतला, त्रिपुरा – 799010
ईमेल: sio-trpr@nic.in, फ़ोन: 0381-2414053

चित्तूर, आंध्र प्रदेश

नवोन्मेषी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समाधानों के माध्यम से डिजिटल सुशासन को गति

संपादित : **जॉयस आर. अमृतराज**

आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित चित्तूर एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं तीर्थस्थल जिला है, जिसकी सीमाएँ तमिलनाडु एवं कर्नाटक से लगती हैं। एनआईसी चित्तूर ई-शासन मंचों के कार्यान्वयन, नवाचारी डिजिटल समाधानों के विकास तथा प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं की उपलब्धता के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सहायता प्रदान करता है। इसकी विभिन्न पहलों ने चित्तूर एवं तिरुपति जिलों में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता एवं नागरिक-केंद्रित शासन को सशक्त बनाया है।है।

जिले में आईसीटी पहलें

तिरुमला नागरिक सत्यापन एवं निगरानी प्रणाली (टी.सी.वी.एस.एस)

https://tcvss.ap.gov.in

तिरुमला में सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एनआईसी चित्तूर ने पुलिस विभाग के लिए तिरुमला नागरिक सत्यापन एवं निगरानी प्रणाली (टी.सी.वी.एस.एस) विकसित की है। यह मंच तिरुमला में निवास करने अथवा कार्यरत व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों, जैसे होटल, मठ, दुकानें, सेवा प्रदाता, श्रमिक तथा स्थानीय निवासियों का सत्यापित डेटाबेस संधारित करता है।

टी.सी.वी.एस.एस एक केंद्रीकृत एवं प्रमाणीकरण-आधारित सूचना भंडार के माध्यम से वास्तविक समय में सत्यापन, निगरानी एवं पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है। इसके एकीकृत डैशबोर्ड निवारक पुलिसिंग, भीड़ प्रबंधन, विशिष्ट अतिविशिष्ट व्यक्ति (वी.वी.आई.पी) सुरक्षा तथा अन्य कानून-प्रवर्तन गतिविधियों के लिए उपयोगी विश्लेषणात्मक जानकारी उपलब्ध कराते हैं, जिससे बेहतर निर्णय-निर्माण संभव हो पाता है।

इस मंच ने सत्यापन प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाया है, सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ किया है तथा व्यक्तियों की त्वरित पहचान एवं सत्यापन के माध्यम से परिस्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाया है।

प्रभाव

- तिरुमला के प्रतिष्ठानों, श्रमिकों एवं निवासियों का सत्यापित डेटाबेस

> एनआईसी चित्तूर, तिरुमला नागरिक सत्यापन एवं निगरानी प्रणाली (टी.सी.वी.एस.एस) तथा फाइल लंबितता निगरानी प्रणाली (एफ.पी.एम.एस) जैसे नवाचारी समाधानों के माध्यम से डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ कर रहा है। साथ ही, यह ई-ऑफिस, आईरैड/ईडार, ई-हॉस्पिटल, आर.टी.आई.एम.आई.एस तथा वेबलैंड जैसी प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय ई-शासन पहलों के कार्यान्वयन में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। इन प्रौद्योगिकी-आधारित हस्तक्षेपों ने चित्तूर एवं तिरुपति जिलों में प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता तथा नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है।

- वास्तविक समय में सत्यापन एवं निगरानी
- निगरानी एवं निवारक पुलिसिंग को मजबूती
- वीवीआईपी सुरक्षा प्रबंधन में बेहतर सहयोग
- डैशबोर्ड एवं प्रतिवेदनों के माध्यम से डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण
- व्यक्तियों की त्वरित पहचान एवं सत्यापन

फाइल लंबितता निगरानी प्रणाली (एफ.पी.एम.एस)

एनआईसी चित्तूर द्वारा विकसित एफ.पी.एम.एस विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित फाइलों तथा प्रशासनिक मुद्दों की ऑनलाइन निगरानी एवं अनुश्रवण की सुविधा प्रदान करती है। यह मंच इलेक्ट्रॉनिक फाइल संचलन, वास्तविक समय स्थिति अद्यतन तथा एकीकृत डैशबोर्ड के माध्यम से केंद्रीकृत निगरानी सुनिश्चित करता है।

प्रशासनिक स्तरों पर लंबित मामलों की स्पष्ट दृश्यता उपलब्ध कराकर एफपीएमएस ने पारदर्शिता, जवाबदेही एवं निर्णय-निर्माण को बेहतर बनाया है। इस अनुप्रयोग की सफलता के परिणामस्वरूप इसे ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम (जी.वी.एम.सी), विशाखापत्तनम तथा कृष्णा जिले सहित अन्य क्षेत्रों में भी अपनाया गया है।

> "मुझे यह दर्ज करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एनआईसी चित्तूर जिला केंद्र द्वारा जिला प्रशासन को उत्कृष्ट आईसीटी सहायता सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं। जिला आधिकारिक पोर्टल के विकास एवं अनुरक्षण, स्थानीय एवं आम चुनावों में निरंतर सहयोग, विभिन्न केन्द्रीय एवं राष्ट्रीय परियोजनाओं तथा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में जिला एनआईसी टीम का योगदान सराहनीय है। जिले में ई-शासन पहलों को सफल बनाने में एनआईसी चित्तूर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।"
>
> **श्री सुमित कुमार,** आईएएस
> जिलाधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, चित्तूर

प्रभाव

- लंबित फाइलों एवं प्रशासनिक मामलों की ऑनलाइन निगरानी
- पारदर्शिता एवं जवाबदेही में वृद्धि
- वास्तविक समय स्थिति अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन
- प्रशासनिक समीक्षा हेतु केंद्रीकृत डैशबोर्ड
- शिकायतों एवं विभागीय गतिविधियों की बेहतर निगरानी

वेंकटेश्वर राव नक्का
वैज्ञानिक-डी एवं डीआईओ
venkat.rao@nic.in

- अन्य जिलों एवं स्थानीय निकायों में सफल पुनरावृत्ति

जिला वेबसाइटें एवं डिजिटल मंच

एनआईसी चित्तूर, चित्तूर एवं तिरुपति जिलों, जिला पुलिस विभागों तथा विस्तार प्रशिक्षण केंद्र (ईटीसी), श्रीकालहस्ती की आधिकारिक वेबसाइटों का प्रबंधन करता है। ये मंच सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक सूचनाओं, नागरिक सेवाओं, प्रशिक्षण संसाधनों तथा विभागीय अद्यतनों तक सहज पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे पारदर्शिता, डिजिटल पहुँच एवं नागरिक सहभागिता को बढ़ावा मिलता है।

जिले की अन्य प्रमुख पहलें

आईरैड/ ईडार

एनआईसी चित्तूर हितधारकों के प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहायता के माध्यम से आईरैड तथा ईडार प्रणालियों के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करता है। ये प्रणालियाँ सड़क दुर्घटनाओं की डिजिटल रिपोर्टिंग, विश्लेषण एवं सड़क सुरक्षा प्रबंधन को सुदृढ़ करती हैं।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल को चित्तूर एवं तिरुपति जिलों के प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में लागू किया गया है। यह प्रणाली रोगी पंजीकरण, चिकित्सीय सेवाओं तथा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेखों के डिजिटल प्रबंधन को सक्षम बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करती है।

वेबलैंड

एनआईसी चित्तूर, आंध्र प्रदेश की डिजिटल भू-अभिलेख प्रबंधन प्रणाली वेबलैंड के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह राजस्व कार्यालयों में पारदर्शी एवं दक्ष भूमि प्रशासन सुनिश्चित करने में सहायक है।

आर.टी.आई.एम.आई.एस

एनआईसी चित्तूर, सूचना का अधिकार (आरटीआई) आवेदनों, अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण तथा निस्तारण हेतु आर.टी.आई.एम.आई.एस के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता एवं नागरिकों की सूचना तक पहुँच में सुधार हुआ है।

ई-ऑफिस

एनआईसी चित्तूर ने 153 राज्य एवं केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस लागू किया है, जिसके माध्यम से 4.47 लाख से अधिक ई-फाइलें तथा 5.69 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक रसीदें संसाधित की जा चुकी हैं। इस मंच ने कार्यप्रवाह को सुव्यवस्थित किया है, कागजरहित प्रशासन को बढ़ावा दिया है तथा प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि की है।

नेटवर्क एवं ई-मेल सेवाएँ

एनआईसी चित्तूर सरकारी विभागों को नेटवर्क, ई-मेल एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जिससे विश्वसनीय डिजिटल संचार तथा निर्बाध आईसीटी संचालन सुनिश्चित होता है।

महत्वपूर्ण आयोजन एवं जन-जागरूकता गतिविधियाँ

एनआईसी चित्तूर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं जन-जागरूकता अभियानों के माध्यम से साइबर सुरक्षा जागरूकता एवं डिजिटल साक्षरता को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में सुरक्षित इंटरनेट उपयोग, साइबर स्वच्छता, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग पर विशेष बल दिया गया।

▲ चित्र 4.1 : आईरैड/ ईडार और पीएम राहत योजना पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया

जिला केंद्र राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्तरीय आयोजनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना उपलब्ध कराकर तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। एनआईसी चित्तूर नियमित रूप से प्रशासनिक बैठकों, सम्मेलनों एवं उच्च स्तरीय दौरों में सहयोग देता है, जिससे विभिन्न सरकारी विभागों के बीच निर्बाध डिजिटल समन्वय सुनिश्चित होता है।

सम्मान एवं उपलब्धियाँ

एनआईसी चित्तूर द्वारा प्रदान की जा रही आईसीटी सहायता सेवाओं को जिला प्रशासन एवं विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है। डिजिटल सुशासन एवं ई-शासन पहलों के सफल कार्यान्वयन में योगदान के लिए जिला केंद्र तथा उसके अधिकारियों को राज्य एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों में प्रशस्ति-पत्र एवं सम्मान प्रदान किए गए हैं।

आगे की राह

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), चित्तूर, अभिनव स्थानीय आईसीटी समाधानों के विकास तथा राज्य एवं केंद्र सरकार के विद्यमान डिजिटल प्लेटफ़ॉर्मों को निरंतर तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य में, प्रचलित विधिक एवं गोपनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन टी.सी.वी.एस.एस को सी.सी.टी.एन.एस के माध्यम से आपराधिक अभिलेख सत्यापन, आई.सी.जे.एस के माध्यम से न्यायालयीन प्रकरणों की जानकारी, वाहन एवं चालक संबंधी विवरण हेतु वाहन एवं सारथी तथा अन्य अधिकृत सरकारी डेटाबेसों के साथ एकीकृत कर और अधिक सक्षम बनाया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, प्रणाली में नागरिक सत्यापन, आगंतुक प्रबंधन तथा तिरुमला के पवित्र नगर में कार्यरत, सेवाएँ प्रदान करने वाले अथवा निवास करने वाले व्यक्तियों की सार्वजनिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मोबाइल अनुप्रयोग भी शामिल किए जाएंगे।

> तिरुमला में 'तिरुमला नागरिक सत्यापन प्रणाली (टी.सी.वी.एस)' के विकास एवं अनुरक्षण में एनआईसी चित्तूर जिला केंद्र द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य सहयोग की हम हृदय से सराहना करते हैं। इस अनुप्रयोग ने तिरुमला के निवासियों, श्रमिकों एवं दुकानदारों के सत्यापन एवं निगरानी को अत्यधिक सुदृढ़ बनाया है। साथ ही अपराधियों, फरार आरोपियों एवं लापता व्यक्तियों की पहचान में भी यह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। श्रीवारी ब्रह्मोत्सवम् एवं वैकुण्ठ एकादशी जैसे प्रमुख आयोजनों के दौरान एनआईसी टीम द्वारा प्रदान की गई निरंतर तकनीकी सहायता विशेष रूप से प्रशंसनीय है। तिरुमला में सुरक्षा एवं ई-शासन को सुदृढ़ करने में उनके योगदान के लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।
>
> **श्री एल. सुब्बारायुडु, आईपीएस**
> पुलिस अधीक्षक, तिरुपति जिला

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी चित्तूर जिला केंद्र
द्वितीय तल, न्यू कलेक्टरेट
चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश – 517001
ई-मेल: dio-chi@nic.in, फ़ोन: 08572-242666

जिला से

केंद्रपाड़ा, ओडिशा

आईसीटी के माध्यम से जमीनी स्तर के सुशासन को सशक्त बनाना

संपादित : **लाल बहादुर सिंह**

केंद्रपाड़ा जिला सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) को रणनीतिक रूप से अपनाकर अपने डिजिटल प्रशासनिक तंत्र को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है। इस परिवर्तन के केंद्र में एनआईसी जिला केंद्र, केंद्रपाड़ा है, जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों के कार्यान्वयन, आईसीटी अवसंरचना को मजबूत करने, साइबर सुरक्षा संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करने तथा विभिन्न सरकारी विभागों में डिजिटल प्रौद्योगिकियों के प्रभावी उपयोग को सक्षम बनाकर जिले की तकनीकी रीढ़ के रूप में कार्य कर रहा है।

आधार-सक्षम उपस्थिति प्रणालियों और जीआईएस-आधारित निर्णय-सहायक उपकरणों से लेकर मोबाइल अनुप्रयोगों, डिजिटल सेवा वितरण प्लेटफॉर्मों और रीयल-टाइम निगरानी समाधानों तक, एनआईसी केंद्रपाड़ा प्रशासन में प्रौद्योगिकी-आधारित नवाचार को बढ़ावा दे रहा है। निरंतर तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण और नागरिक-केंद्रित डिजिटल समाधानों के विकास के माध्यम से जिला केंद्र ने पारदर्शिता, परिचालन दक्षता, डेटा-आधारित निर्णय-निर्माण तथा सेवा वितरण में सुधार करने में सहायता की है, जिससे अधिक उत्तरदायी और प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रशासन को बढ़ावा मिला है।

जिले में आईसीटी पहलें

आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, केंद्रपाड़ा के मार्गदर्शन में, एनआईसी केंद्रपाड़ा ने जनवरी 2026 में सभी तहसीलों और ब्लॉकों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (ए.ई.बी.ए.एस) लागू की। वर्तमान में यह प्रणाली 32 प्रशासनिक इकाइयों के अंतर्गत 714 कार्यालयों को कवर करती है, जिनमें तहसीलें, ब्लॉक, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आपातकालीन संचालन केंद्र शामिल हैं।

ए.ई.बी.ए.एस रीयल-टाइम उपस्थिति निगरानी, बायोमेट्रिक एवं मोबाइल-आधारित उपस्थिति अंकन, जियो-टैग्ड भ्रमण प्रबंधन, डैशबोर्ड तथा केंद्रीकृत रिपोर्टिंग जैसी सुविधाएँ प्रदान करता है।

शुभेंदु शेखर साहू
वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहायक - ए
kk.sahoo@nic.in

> एनआईसी केंद्रपाड़ा की आईसीटी पहलों ने ए.ई.बी.ए.एस, ई-काउंसलिंग और ई-डार जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण को सुदृढ़ किया है। क्षमता निर्माण, तकनीकी परामर्श सेवाओं और जिला-स्तरीय नवाचारों के साथ मिलकर इन प्रयासों ने जिला प्रशासन की तकनीकी रीढ़ के रूप में इसकी भूमिका को और मजबूत किया है।

2,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के साथ इस प्लेटफॉर्म ने अप्रैल–मई 2026 के दौरान 80 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति अनुपालन दर्ज किया, जिससे सरकारी कार्यप्रणाली में जवाबदेही, समयपालन और पारदर्शिता को बल मिला।

जनगणना एवं कृषि जनगणना सहायता

एनआईसी केंद्रपाड़ा ने जनसंख्या एवं गृह जनगणना तथा कृषि जनगणना गतिविधियों के लिए तकनीकी और समन्वयात्मक सहायता प्रदान की। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने मास्टर ट्रेनर-कम-अतिरिक्त जिला जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और डिजिटल प्रक्रियाओं के संचालन का नेतृत्व किया। तकनीकी सहायता, क्षेत्रीय स्तर पर सहयोग तथा गणनाकारों और पर्यवेक्षकों की समस्याओं के समाधान के माध्यम से एनआईसी ने सटीक डेटा संग्रह, बेहतर समन्वय और जनगणना कार्यों के समयबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करने में योगदान दिया।

स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु ई-काउंसलिंग प्रणाली

एनआईसी केंद्रपाड़ा ने कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की प्रक्रिया को डिजिटाइज करने के लिए ई-काउंसलिंग पोर्टल विकसित किया। यह प्लेटफॉर्म रिक्तियों के प्रबंधन, वरीयता प्रस्तुतिकरण, आवंटन तथा पदस्थापन आदेशों के सृजन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध निर्णय-निर्माण को बढ़ावा मिलता है। अब तक 150 से अधिक स्थानांतरण एवं पदस्थापन मामलों का निपटान इस पोर्टल के माध्यम से किया जा चुका है।

ई-डार और पीएम राहत

एनआईसी केंद्रपाड़ा इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (ई-डार) प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करता है, जिससे सड़क दुर्घटना मामलों की डिजिटल प्रोसेसिंग और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है। जिला केंद्र पीएम राहत के लिए भी तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे दुर्घटना-संबंधी सहायता और दस्तावेजीकरण अधिक प्रभावी ढंग से संचालित हो सके।

निर्वाचन आईसीटी सहायता

एनआईसी केंद्रपाड़ा निर्वाचन के दौरान एंड-टू-एंड आईसीटी सहायता प्रदान करता है, जिसमें अनुप्रयोग प्रबंधन, डेटा तैयारी, कार्मिक एवं ईवीएम रैंडमाइजेशन, तकनीकी प्रशिक्षण और संचार सहायता शामिल हैं। ये सेवाएँ पारदर्शी, प्रौद्योगिकी-संचालित और दक्ष निर्वाचन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करती हैं।

राजस्व, भूमि, आपदा प्रबंधन एवं नागरिक सेवाएँ

एनआईसी केंद्रपाड़ा भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशासन, प्रमाण-पत्र, शिकायत निवारण, आपदा सहायता तथा नागरिक सेवा वितरण से संबंधित प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्मों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। जिला केंद्र डी.ए.एम.पी.एस तथा ई-कोर्ट सेवाओं जैसे अनुप्रयोगों के लिए तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और समस्या निवारण भी उपलब्ध कराता है, जिससे उनका प्रभावी उपयोग और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण सुनिश्चित होता है।

खुदरा मदिरा दुकानों हेतु ई-लॉटरी

आबकारी वर्ष 2026–27 के लिए आई.एम.एफ.एल "ऑफ" दुकानों तथा देशी मदिरा दुकानों के निपटान हेतु ई-लॉटरी का आयोजन जिला परिषद, केंद्रपाड़ा के सम्मेलन कक्ष में किया गया।

एनआईसी केंद्रपाड़ा के जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ने जांच समिति और लॉटरी समिति दोनों के सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आवेदन एवं दस्तावेजों के सत्यापन, आईसीटी अवसंरचना व्यवस्था, लॉटरी विजेताओं की कंप्यूटरीकृत प्रविष्टि, अस्थायी विजेता प्रमाण-पत्रों के सृजन तथा प्रक्रिया के सभी तकनीकी पहलुओं में सहयोग प्रदान किया।

आई.एम.एफ.एल 'ऑफ' दुकानों के लिए 634 आवेदकों से कुल 919 आवेदन प्राप्त हुए, जबकि देशी मदिरा दुकानों के लिए 122 आवेदकों से 173 आवेदन प्राप्त हुए। कुल मिलाकर 756 आवेदकों से प्राप्त 1,092 आवेदनों को 64 दुकानों के विरुद्ध संसाधित किया गया और लॉटरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और दक्ष तरीके से सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई, जिसने डिजिटल प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता को प्रदर्शित किया।

जिला जियो-पोर्टल

भारत मैप्स फ्रेमवर्क पर निर्मित केंद्रपाड़ा जिला जियो-पोर्टल योजना निर्माण, निगरानी और निर्णय-निर्माण के लिए एक एकीकृत जीआईएस प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। प्रशासनिक, अवसंरचनात्मक और संसाधन-संबंधी डेटासेटों को एकीकृत करके यह अधिकारियों को भू-स्थानिक सूचनाओं का विश्लेषण करने, बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा साक्ष्य-आधारित प्रशासन को बढ़ावा देने में सक्षम बनाता है।

जिला मोबाइल अनुप्रयोग विकास

एनआईसी केंद्रपाड़ा आवश्यकता-आधारित मोबाइल अनुप्रयोग विकसित करता है ताकि पहुँच, क्षेत्रीय स्तर पर समन्वय, सूचना प्रसार और डिजिटल निगरानी को बेहतर बनाया जा सके। ये समाधान तेज निर्णय-निर्माण, बेहतर क्षेत्रीय रिपोर्टिंग तथा डिजिटल प्रशासनिक उपकरणों के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

आईसीटी अवसंरचना, नेटवर्क और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सहायता

एनआईसी केंद्रपाड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी, इनडोर एवं आउटडोर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाएँ, आधिकारिक ईमेल सेवाएँ, साइबर सुरक्षा मार्गदर्शन तथा अनुप्रयोग सहायता सहित महत्वपूर्ण आईसीटी अवसंरचना सहयोग प्रदान करता है।

जिला केंद्र समीक्षा बैठकों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वी.वी.आई.पी दौरों और अन्य उच्च-प्राथमिकता प्रशासनिक गतिविधियों में निर्बाध कनेक्टिविटी, डिजिटल प्रस्तुतीकरण सहायता, रीयल-टाइम तकनीकी समन्वय और विश्वसनीय आईसीटी सेवाएँ सुनिश्चित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मार्गदर्शन एवं क्षमता निर्माण

एनआईसी केंद्रपाड़ा स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्र प्रशिक्षुओं को मार्गदर्शन प्रदान करके क्षमता निर्माण में सक्रिय योगदान देता है तथा उन्हें ई-गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, आईसीटी अवसंरचना और डिजिटल सेवा वितरण के व्यावहारिक पहलुओं से परिचित कराता है।

जिला केंद्र सरकारी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों और छात्रों के लिए साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रशासन, ऑनलाइन सेवाओं और उभरती प्रौद्योगिकियों पर जागरूकता सत्र तथा तकनीकी कार्यशालाएँ भी आयोजित करता है।

तकनीकी समितियाँ एवं आईसीटी परामर्श सहायता

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी विभिन्न आईसीटी-संबंधित समितियों में सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, जिनका संबंध राष्ट्रीय परीक्षाओं, जीईएम खरीद, प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, आईसीटी अवसंरचना योजना और डिजिटल परियोजना कार्यान्वयन से है। एनआईसी केंद्रपाड़ा प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, खरीद प्रक्रिया तथा अनुप्रयोग परिनियोजन पर तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और जिले में कंप्यूटर-आधारित भर्ती परीक्षाओं, कौशल परीक्षणों तथा विभागीय मूल्यांकनों को भी सहयोग देता है।

पुरस्कार एवं सम्मान

एनआईसी केंद्रपाड़ा और उसके अधिकारियों के योगदान को जिला एवं राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न मान्यताएँ प्राप्त हुई हैं:

- रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जनरेशन (आरएजी) आधारित चैटबॉट समाधान के साथ उन्नत लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) विकसित करने के लिए जेनएआई अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2024।
- मई 2026 में उत्कृष्ट आईसीटी सहायता एवं तकनीकी योगदान के लिए पुलिस अधीक्षक, केंद्रपाड़ा द्वारा प्रशंसा-पत्र।
- आम निर्वाचन 2024 के सफल संचालन हेतु आईसीटी सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ), ओडिशा द्वारा प्रशंसा-पत्र।
- 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु आईसीटी सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव, ओडिशा द्वारा प्रशंसा।
- भूमि अभिलेखों और संबंधित सेवाओं के सफल डिजिटलीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए केंद्रपाड़ा जिले को प्राप्त भूमि सम्मान पुरस्कार।

▼ चित्र 5.1 : डीआईओ, केंद्रपाड़ा, ओडिशा सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा संसदीय कार्य मंत्री से 'जनरेटिव कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता पुरस्कार 2024' प्राप्त करते हुए

> जिला प्रशासन, केंद्रपाड़ा शासन में पारदर्शिता, दक्षता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर आईसीटी-सक्षम समाधानों को अपनाता रहा है। आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, ई-डार, ई-काउंसलिंग, ई-डिस्ट्रिक्ट, राजस्व एवं भूमि सेवाओं तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी पहलों ने विभागों के बीच निगरानी, सेवा वितरण एवं समन्वय को बेहतर बनाया है। इन ई-गवर्नेंस पहलों के कार्यान्वयन, तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण तथा महत्वपूर्ण प्रशासनिक गतिविधियों के दौरान विश्वसनीय आईसीटी सहयोग प्रदान करने में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र केंद्रपाड़ा द्वारा दिए गए मूल्यवान समर्थन की मैं सराहना करता हूँ। उनके प्रयासों ने प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, डेटा-आधारित एवं नागरिक-केंद्रित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
>
> मैं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र केंद्रपाड़ा को जिला स्तर पर डिजिटल शासन को सशक्त बनाने तथा डिजिटल इंडिया के विज़न को आगे बढ़ाने में उसकी निरंतर भूमिका के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

श्री रघुराम आर. अय्यर, आईएएस
कलेक्टर और ज़िला मजिस्ट्रेट, केंद्रपाड़ा

- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं और सम्मेलन कार्यवाहियों में चार शोध-पत्र प्रकाशित किए गए हैं।

आगे की राह

एनआईसी केंद्रपाड़ा उन्नत आईसीटी अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, एआई-संचालित समाधानों और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवाओं के माध्यम से डिजिटल प्रशासन को और सुदृढ़ करता रहेगा। एनआईसी और जिला प्रशासन के बीच निरंतर सहयोग के साथ केंद्रपाड़ा एक अधिक पारदर्शी, दक्ष और प्रौद्योगिकी-सक्षम प्रशासनिक तंत्र की दिशा में निरंतर अग्रसर है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी केंद्रपाड़ा जिला केंद्र
कलेक्ट्रेट बिल्डिंग, केंद्रपाड़ा, ओडिशा - 754211
ई-मेल: dio-knd@nic.in, फ़ोन: 06727-232816

मोरीगांव, असम

विरासत में रचा-बसा, प्रौद्योगिकी से प्रेरित

संपादित : **लाल बहादुर सिंह**

असम के मध्य भाग में स्थित मोरीगांव जिला अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तथा प्रसिद्ध पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के लिए जाना जाता है, जो भारतीय एक-सींग वाले गैंडे का प्रमुख आवास है। अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखते हुए जिले ने शासन और जनसेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों को निरंतर अपनाया है।

इस परिवर्तन यात्रा में सहयोगी के रूप में एनआईसी मोरीगांव ने सेवा सेतु, बसुंधरा, धरित्री, ई-ऑफिस तथा आईआरएडी जैसी प्रमुख ई-शासन पहलों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिला केंद्र ने सर्वेक्षण एवं संरचित डेटा संकलन हेतु सर्वेहब तथा सड़क परियोजनाओं की निगरानी के लिए सड़क प्रगति जैसे अभिनव डिजिटल समाधान भी विकसित किए हैं। ई-प्रस्तुति 2.0 पर आधारित जिला वेबसाइट पारितंत्र के साथ मिलकर इन पहलों ने मोरीगांव में पारदर्शिता, दक्षता और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को सुदृढ़ किया है।

जिले में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहलें

सर्वेहब – डिजिटल प्रपत्र, सर्वेक्षण एवं डेटा संकलन मंच

सर्वेहब एक डिजिटल मंच है, जिसे विभिन्न विभागों में प्रपत्र निर्माण, सर्वेक्षण संचालन तथा संरचित डेटा संकलन को सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। यह मंच उपयोगकर्ताओं को केंद्रीकृत इंटरफेस के माध्यम से डिजिटल प्रपत्रों का डिज़ाइन, प्रकाशन और प्रबंधन करने की सुविधा प्रदान करता है।

रीयल-टाइम डैशबोर्ड तथा विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन सुविधाओं से युक्त सर्वेहब प्रभावी निगरानी, डेटा की शुद्धता में सुधार तथा सूचित निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाता है। यह मंच दर्शाता है कि विस्तार योग्य डिजिटल उपकरण शासन एवं प्रशासन की विविध आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं।

बिष्णु छेत्रीहू
वैज्ञानिक अधिकारी - एसबी व डीआईओ
bisnu.chetri95@nic.in

एनआईसी मोरीगांव सेवा सेतु, बसुंधरा, ई-ऑफिस और आईआरएडी जैसी प्रमुख ई-शासन पहलों के माध्यम से जिले में डिजिटल शासन को सशक्त बना रहा है। साथ ही, सर्वेहब और सड़क प्रगति जैसे नवाचारी समाधानों का विकास कर प्रशासनिक दक्षता, पारदर्शिता तथा नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को नई गति प्रदान कर रहा है।

सड़क प्रगति – सड़क परियोजना निगरानी प्रणाली

जिला प्रशासन के सहयोग से विकसित सड़क प्रगति, जिले में सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक डिजिटल मंच है। यह प्रणाली परियोजना-वार प्रगति अनुश्रवण, क्षेत्रीय निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अवसंरचना कार्यों की केंद्रीकृत निगरानी की सुविधा प्रदान करती है।

समयबद्ध अद्यतन और परियोजना क्रियान्वयन की बेहतर दृश्यता उपलब्ध कराकर यह मंच प्रशासकों को प्रगति की समीक्षा, बाधाओं की पहचान तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायता करता है। सड़क प्रगति साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण को सुदृढ़ करते हुए जिले में अवसंरचना विकास गतिविधियों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करती है।

ई-प्रस्तुति 2.0 पर मोरीगांव जिला वेबसाइट

एनआईसी मोरीगांव ने मोरीगांव जिला वेबसाइट को सफलतापूर्वक ई-प्रस्तुति 2.0 ढांचे पर स्थानांतरित किया, जिससे एक आधुनिक, सुलभ और नागरिक-केंद्रित डिजिटल सूचना मंच स्थापित हुआ। इस वेबसाइट पारितंत्र में 24 से अधिक विभागों और कार्यालयों को एकीकृत किया गया है।

विकेंद्रीकृत सामग्री प्रबंधन को सक्षम बनाने हेतु विभागीय सामग्री प्रबंधकों को स्वतंत्र रूप से वेबसाइट सामग्री अद्यतन और अनुरक्षित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। जिला केंद्र वेबसाइट के प्रभावी संचालन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन और सहयोग निरंतर प्रदान कर रहा है।

जिले की अन्य प्रमुख पहलें

एनआईसी मोरीगांव विभिन्न ई-शासन परियोजनाओं के क्रियान्वयन एवं संचालन में सहयोग देकर जिला और राज्य प्रशासन का एक प्रमुख प्रौद्योगिकी साझेदार बना हुआ है।

एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (आई.एल.आर.एम.एस)

एकीकृत भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली (आई.एल.आर.एम.एस) ने बसुंधरा, धरित्री, भूनक्शा, ई-खजाना, एनजीडीआरएस तथा सर्वे/पुनःसर्वेक्षण जैसे अनुप्रयोगों के एकीकरण के माध्यम से भूमि-संबंधी सेवाओं के वितरण में उल्लेखनीय सुधार किया है।

एनआईसी मोरीगांव क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और तकनीकी मार्गदर्शन के माध्यम से इस प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करता है।

सेवा सेतु

एनआईसी असम द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित सेवा सेतु, असम सरकार का प्रमुख नागरिक सेवा वितरण मंच है। यह पोर्टल नागरिकों को पंजीकरण, लाइसेंस, प्रमाणपत्र तथा कल्याणकारी योजनाओं सहित 815 से अधिक सेवाओं तक डिजिटल पहुँच प्रदान करता है।

एनआईसी मोरीगांव उपयोगकर्ता प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से इसके प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करता है।

बसुंधरा

मिशन बसुंधरा असम सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य भूमि राजस्व सेवाओं को पारदर्शी एवं दक्ष तरीके से नागरिकों तक पहुँचाना है। यह कार्यक्रम सरल डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से भूमि-संबंधी सेवाओं की व्यापक श्रृंखला उपलब्ध कराता है।

एनआईसी मोरीगांव प्रशिक्षण, समस्या-निवारण सहायता तथा राजस्व अधिकारियों के साथ समन्वय के माध्यम से इसके प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग करता है।

ई-ऑफिस

एनआईसी मोरीगांव ने जिला आयुक्त कार्यालय तथा सह-जिला आयुक्त कार्यालयों में ई-ऑफिस के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे कागजरहित प्रशासन और सुव्यवस्थित

डिजिटल कार्यप्रवाह को बढ़ावा मिला है।

निरंतर क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग के माध्यम से मंच के सुचारु संचालन एवं उपयोग को सुनिश्चित किया जा रहा है।

आई.आर.ए.डी

एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस (आई.आर.ए.डी) के क्रियान्वयन में एनआईसी मोरीगांव सक्रिय सहयोग प्रदान कर रहा है, जिससे सड़क सुरक्षा संबंधी डेटा प्रबंधन और दुर्घटना प्रतिवेदन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा सके।

हितधारक विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जिला केंद्र प्रधानमंत्री राहत योजना के एकीकरण में भी सहयोग प्रदान कर रहा है, जिससे पात्र लाभार्थियों के प्रकरणों का कुशलतापूर्वक निस्तारण सुनिश्चित हो सके।

निर्वाचन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग

एनआईसी मोरीगांव लोकसभा, विधानसभा, पंचायत तथा स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान जिला प्रशासन को व्यापक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग प्रदान करता है।

जिला केंद्र एनआईसी असम द्वारा विकसित मतदान कार्मिक प्रबंधन प्रणाली (पी.पी.एम.एस) के क्रियान्वयन में सहयोग करता है तथा भारत निर्वाचन आयोग के विभिन्न डिजिटल मंचों के उपयोग हेतु क्षमता निर्माण गतिविधियाँ संचालित करता है।

> एनआईसी मोरीगांव जिले की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक अमूल्य साझेदार रहा है। नवीन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी समाधानों तथा समर्पित तकनीकी सहयोग के माध्यम से इसने जिला प्रशासन को निरंतर समर्थन प्रदान किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेवाओं के सुचारु संचालन, ई-ऑफिस एवं अन्य ई-शासन पहलों के क्रियान्वयन तथा चुनावों के दौरान तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सड़क परियोजनाओं की निगरानी हेतु विकसित की जा रही सड़क प्रगति प्रणाली प्रभावी शासन और सूचित निर्णय-निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के प्रति एनआईसी मोरीगांव की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। मैं एनआईसी मोरीगांव टीम के प्रयासों की सराहना करती हूँ और जिले में नागरिक-केंद्रित डिजिटल शासन को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शुभकामनाएँ देती हूँ।
>
> **श्रीमती अनामिका तिवारी, एसीएस**
> ज़िला आयुक्त, मोरीगाँव

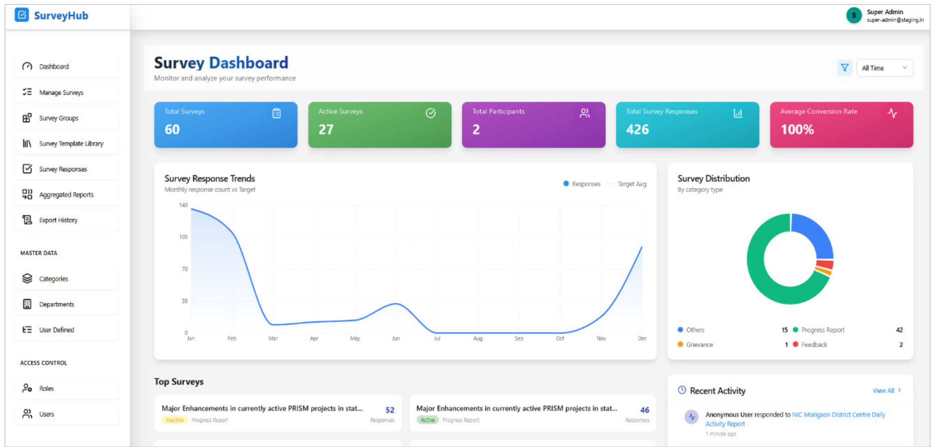

चित्र 6.1 : सर्वेहब डैशबोर्ड

चित्र 6.2 : एनआईसी मोरीगांव द्वारा निर्वाचन हेतु सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहयोग

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं एनआईसीनेट सेवाएँ

एनआईसी मोरीगांव एनआईसीनेट, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनकेएन), वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा वेबकास्टिंग जैसी महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना सेवाओं का संचालन करता है।

ये सेवाएँ प्रशासनिक संवाद और समन्वय की आधारशिला हैं। जिला केंद्र चौबीसों घंटे तकनीकी सहयोग प्रदान कर विश्वसनीय संपर्क और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करता है।

आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2026

साइबर जागरूकता और डिजिटल प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एनआईसी मोरीगांव ने सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2026 के अवसर पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया।

विभिन्न विभागों के लगभग 70 सरकारी अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में साइबर स्वच्छता, पासवर्ड सुरक्षा, सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार तथा उभरते साइबर खतरों से सुरक्षा जैसे विषयों पर विशेष चर्चा की गई। कार्यशाला ने डिजिटल शासन व्यवस्था में साइबर सुरक्षा के महत्व को रेखांकित किया।

आगे की राह

आगामी समय में एनआईसी मोरीगांव सड़क प्रगति मंच की क्षमताओं को और सुदृढ़ करने तथा सर्वेहब के उपयोग का विभिन्न विभागों में विस्तार करने पर विशेष ध्यान देगा। डिजिटल सेवा वितरण को मजबूत बनाने, साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने तथा डेटा-आधारित शासन को प्रोत्साहित करने के प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।

जिला प्रशासन के एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में एनआईसी मोरीगांव कुशल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित शासन के लिए डिजिटल नवाचारों के उपयोग हेतु प्रतिबद्ध है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी जिला केंद्र, मोरीगांव
जिला आयुक्त कार्यालय
मोरीगांव, असम - 782105
ई-मेल: dio-mgn@nic.in, फ़ोन: 03678-240225

उज्जैन, मध्य प्रदेश

आईसीटी नवाचारों के माध्यम से डिजिटल सुशासन को नई दिशा

संपादित : **स्वरूप दत्ता**

मालवा क्षेत्र में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन भारत के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं विरासत स्थलों में से एक है। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाकाल लोक, वेधशाला तथा विश्वविख्यात सिंहस्थ कुम्भ मेले के कारण यह जिला राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान रखता है। ऐतिहासिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से इसका महत्वपूर्ण स्थान है।

जिले की बढ़ती प्रशासनिक एवं विकासात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एनआईसी उज्जैन सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण को बेहतर बनाने, प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने तथा डिजिटल परिवर्तन को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ई-गवर्नेंस परियोजनाओं एवं डिजिटल अवसंरचना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से केन्द्र जिले में सुशासन को नई दिशा प्रदान कर रहा है।

जिले में आईसीटी पहलें

एनआईसी उज्जैन जिला केन्द्र ने जिले में विभिन्न मिशन मोड ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी तथा तकनीकी सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ई-ऑफिस

जिला केन्द्र ने संभागीय, जिला, अनुविभागीय तथा तहसील स्तर के कार्यालयों में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन एवं संचालन में सहयोग प्रदान किया। इस पहल से कागज-आधारित प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय कमी आई है, फाइलों की ट्रैकिंग अधिक प्रभावी हुई है, पारदर्शिता बढ़ी है तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आई है।

ई-उपार्जन

कृषि उपज की खरीद के लिए ई-उपार्जन प्रणाली के सफल संचालन में जिला केन्द्र ने तकनीकी सहयोग एवं समन्वय प्रदान किया। इस प्लेटफॉर्म ने खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया है, लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित की है तथा किसानों को समय पर भुगतान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

एनआईसी उज्जैन ई-ऑफिस, ई-उपार्जन, नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल तथा पीएम राहत जैसी प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ बना रहा है। केन्द्र ने 850 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं वेबकास्ट का सफल संचालन किया, अनेक महत्वपूर्ण प्रशासनिक, विकासात्मक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजनों को तकनीकी सहयोग प्रदान किया तथा सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के लिए स्वचालित भूमि अधिग्रहण निगरानी एवं अधिसूचना प्रणाली विकसित की। आईसीटी सहायता, क्षमता निर्माण तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से एनआईसी उज्जैन नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को और अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बना रहा है।

जनगणना 2027 संचालन

एनआईसी उज्जैन ने जनगणना गतिविधियों के लिए जिला आईटी नोडल एजेंसी के रूप में कार्य किया। केन्द्र ने जनगणना संबंधी आईटी गतिविधियों के प्रथम चरण के समन्वय एवं निगरानी की जिम्मेदारी निभाई। मई 2026 में संचालित गृह-सूचीकरण गतिविधियों के दौरान तकनीकी मार्गदर्शन, अवसंरचना सहायता तथा विभिन्न हितधारकों के बीच समन्वय सुनिश्चित किया गया, जिससे कार्यों का सुचारु संचालन संभव हुआ।

जनआकांक्षा पोर्टल एवं टीएल मॉनिटरिंग

एनआईसी उज्जैन जनआकांक्षा पोर्टल को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है, जिसका उपयोग कलेक्टर, उज्जैन द्वारा साप्ताहिक समय-सीमा (टीएल) बैठकों में जन शिकायतों की निगरानी हेतु व्यापक रूप से किया जाता है। यह पोर्टल शिकायतों की स्थिति, विभागीय अनुपालन, लंबित मामलों तथा समयबद्ध निस्तारण की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करता है। जन शिकायतों के समाधान में यह एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे जवाबदेही एवं सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।

एनडीएएल शस्त्र लाइसेंस प्रणाली

एनआईसी उज्जैन राष्ट्रीय शस्त्र लाइसेंस डेटाबेस (एन.डी.ए.एल) के लिए तकनीकी सहायता एवं सॉफ्टवेयर प्रबंधन सेवाएँ प्रदान करता है। इससे जिले में शस्त्र लाइसेंस संबंधी सेवाओं का डिजिटल प्रसंस्करण एवं कुशल प्रबंधन सुनिश्चित हुआ है।

नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल

जिला चिकित्सालय, उज्जैन को पुराने ई-हॉस्पिटल प्लेटफॉर्म से उन्नत कर नेक्स्टजेन ई-हॉस्पिटल प्रणाली पर स्थानांतरित किया गया। इस उन्नत प्लेटफॉर्म ने अस्पताल प्रशासन, मरीज पंजीकरण, अपॉइंटमेंट प्रबंधन तथा चिकित्सीय कार्यप्रवाह को अधिक प्रभावी बनाया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

ई-डीएआर के माध्यम से पीएम राहत

जिला प्रशासन एवं एनआईसी के सहयोग से प्रधानमंत्री राहत (सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल उपचार एवं सुनिश्चित सहायता) योजना का सफल क्रियान्वयन किया गया। योजना के प्रभावी संचालन के लिए पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि ई-डीएआर (इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट) पोर्टल का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा सके तथा दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके।

एनआईसी, जिला प्रशासन, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभागों के समन्वित प्रयासों से जिले में ई-डीएआर एवं टीएमएस 2.0 पारिस्थितिकी तंत्र का सफल एकीकरण सुनिश्चित हुआ है। एनआईसी द्वारा निरंतर तकनीकी सहायता एवं वास्तविक समय में प्रदान किए गए मार्गदर्शन के परिणामस्वरूप 68 सड़क दुर्घटना पीड़ित इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं।

स्वचालित भूमि अधिग्रहण निगरानी एवं अधिसूचना प्रणाली

सिंहस्थ-2028 के लिए प्रस्तावित व्यापक विकास एवं

विवेक महावर
वैज्ञानिक - सी व डीआईओ
mahawar.vivek@nic.in

अवसंरचना परियोजनाओं के समर्थन हेतु एनआईसी उज्जैन स्वचालित भूमि अधिग्रहण अनुभाग निगरानी एवं अधिसूचना प्रणाली विकसित कर रहा है। यह समाधान भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामलों की विभिन्न वैधानिक अवस्थाओं की व्यवस्थित निगरानी करता है तथा अधिग्रहण प्रक्रिया के विभिन्न प्रावधानों एवं समय-सीमाओं पर नजर रखता है।

यह प्रणाली आगामी कार्यवाहियों के लिए स्वचालित सूचनाएँ एवं अनुस्मारक, रियल-टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तथा विलंबित मामलों के लिए एस्केलेशन अलर्ट प्रदान करती है। पारदर्शिता, जवाबदेही एवं विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करते हुए यह प्लेटफॉर्म भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूरा करने तथा विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता कर रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं वेबकास्टिंग सेवाएँ

एनआईसी उज्जैन शासन, विकासात्मक गतिविधियों, जन-जागरूकता कार्यक्रमों तथा विशेष आयोजनों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबकास्टिंग एवं आईसीटी सहायता सेवाएँ प्रदान कर रहा है।

मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का गृह जिला होने तथा प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक एवं विकासात्मक गतिविधियों का केन्द्र होने के कारण उज्जैन में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के दौरे एवं उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन नियमित रूप से होता है। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के साथ तकनीक-आधारित समन्वय, निगरानी एवं हितधारकों की सहभागिता की आवश्यकता भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।

गत वर्ष के दौरान एनआईसी उज्जैन ने 850 से अधिक वीडियो कॉन्फ्रेंस एवं वेबकास्ट का सफल संचालन किया, जिससे राज्य सरकार, जिला प्रशासन, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं नागरिकों के बीच निर्बाध संवाद एवं समन्वय सुनिश्चित हुआ।

केन्द्र ने राष्ट्रीय खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा सम्मेलन, कालिदास समारोह, विक्रम महोत्सव, यूनाइटेड कॉन्शसनेस कॉन्क्लेव, ग्लोबल स्पिरिचुअल टूरिज्म कॉन्क्लेव तथा विभिन्न विरासत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आईसीटी सहायता उपलब्ध कराई।

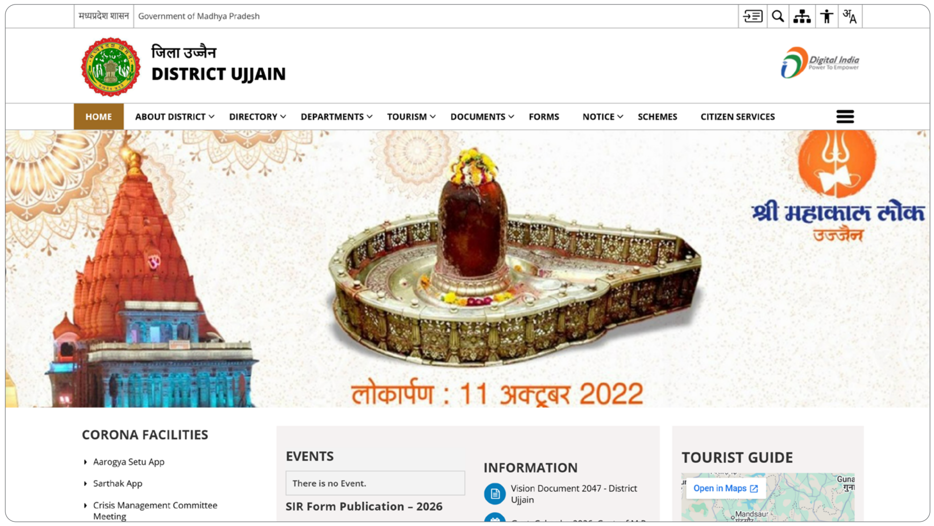

▲ चित्र 7.2 : ज़िला उज्जैन वेबसाइट का होम पेज

एनआईसी उज्जैन ने माननीय मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिवों, संभागायुक्त, कलेक्टर तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आयोजित आभासी बैठकों एवं समीक्षा कार्यक्रमों के संचालन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनमें समाधान ऑनलाइन, कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस, कानून एवं व्यवस्था समीक्षा बैठकें, सिविल डिफेन्स तैयारी बैठकें, निर्वाचन संबंधी समीक्षा बैठकें तथा सिंहस्थ-2028 की योजना एवं निगरानी से जुड़ी बैठकें शामिल थीं।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र ने लाड़ली बहना योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह सम्मेलन, संबल योजना, किसान कल्याण योजना अंतर्गत निधि अंतरण कार्यक्रमों, उपार्जन समीक्षा बैठकों तथा विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

क्षमता निर्माण एवं डिजिटल सुशासन

एनआईसी उज्जैन विभिन्न विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हुए डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए निरंतर कार्यरत है। केन्द्र नियमित रूप से ई-ऑफिस प्रशिक्षण कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा जागरूकता सत्र तथा आईसीटी क्षमता निर्माण गतिविधियों का आयोजन करता है, जिससे सरकारी अधिकारियों की डिजिटल दक्षताओं में वृद्धि हो रही है।

इन प्रयासों से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्मों के उपयोग में वृद्धि हुई है, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता मजबूत हुई है तथा जिले में सार्वजनिक सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार आया है।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस का आयोजन

डिजिटल प्रौद्योगिकियों के सुरक्षित एवं जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत एनआईसी उज्जैन ने विद्यार्थियों एवं सरकारी हितधारकों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए।

सुरक्षित इंटरनेट दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों के लिए आयोजित साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण सत्र में व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, मजबूत पासवर्ड का उपयोग, द्वि-कारक प्रमाणीकरण, फिशिंग हमलों की पहचान तथा सार्वजनिक वाई-फाई नेटवर्क के सुरक्षित उपयोग जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। ये पहलें डिजिटल रूप से जागरूक एवं साइबर-सुरक्षित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

अग्रिम राह

एनआईसी उज्जैन नवोन्मेषी आईसीटी समाधानों, क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा मिशन मोड परियोजनाओं को निर्बाध तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए डिजिटल सुशासन को नई ऊँचाइयों तक ले जा रहा है। सिंहस्थ-2028 एवं अन्य महत्वपूर्ण विकासात्मक पहलों की तैयारियों के बीच केन्द्र तकनीक-संचालित, पारदर्शी, कुशल एवं नागरिक-केंद्रित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

▼ चित्र 7.1 **ई-उपार्जन प्रक्रिया का प्रवाह**

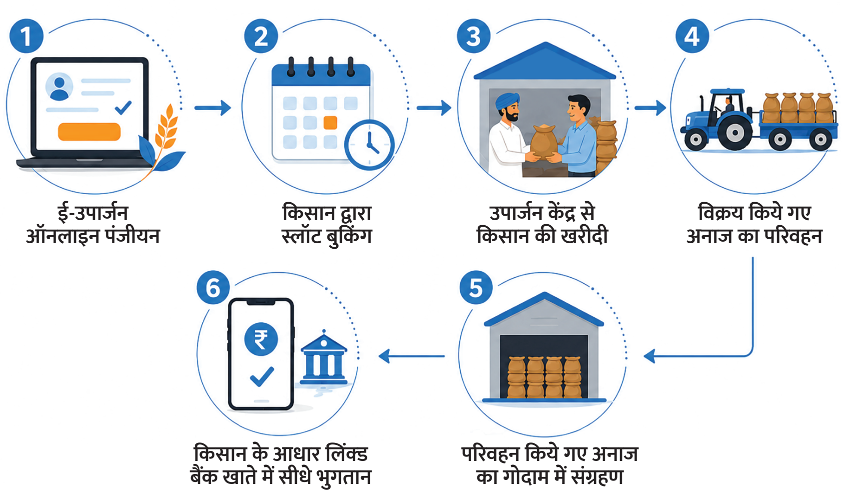

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

जिला सूचना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी उज्जैन जिला केंद्र
भूतल, कलेक्ट्रेट भवन, सम्राट विक्रमादित्य प्रशासनिक संकुल
कोठी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश – 456010
ई-मेल: dio-ujj@nic.in, फ़ोन: 07652-240883

पेंशनर सेवा पोर्टल पंजाब

पेंशनभोगियों की सुविधा की दिशा में एक डिजिटल पहल

संपादित : **विनोद कुमार गर्ग**

पेंशनर सेवा पोर्टल (पीएसपी) पंजाब पंजाब सरकार की एक प्रमुख डिजिटल सुशासन पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पारदर्शी, दक्ष एवं नागरिक-केंद्रित पेंशन सेवाएँ उपलब्ध कराना है। यह पोर्टल एक सुरक्षित एवं एकीकृत डिजिटल मंच प्रदान करता है, जिसके माध्यम से पेंशनभोगी कहीं भी और कभी भी पेंशन संबंधी सेवाओं एवं सूचनाओं तक पहुँच सकते हैं। साथ ही, यह फर्जी एवं दोहरी पेंशन भुगतान पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

पंजाब सरकार के वित्त विभाग (कोषागार एवं लेखा) द्वारा संचालित यह पोर्टल पेंशन प्रक्रिया के संपूर्ण कार्यप्रवाह का डिजिटलीकरण एवं सरलीकरण करता है। इससे मैनुअल हस्तक्षेप में कमी आती है, कार्यालयों के चक्कर घटते हैं तथा पेंशनभोगियों एवं संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है।

1 नवंबर, 2025 को प्रारंभ किए गए इस पोर्टल में पेंशनर सेवाएँ, ई-स्क्रॉल तथा अन्य कार्यात्मक मॉड्यूल शामिल हैं, जो परिचालन दक्षता, वित्तीय पारदर्शिता एवं सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाते हैं।

विवेक वर्मा
उप महानिदेशक व एसआईओ
vivek.verma@nic.in

अनूप जल्लाली
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एचओडी
anoop.jalali@nic.in

नरेंद्र सिंह
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
narinder.singh@nic.in

अनिल कटियार
वैज्ञानिक - डी
katiyar.anil@nic.in

उन्नत स्वचालन एवं डेटा इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क से संचालित पीएसपी पंजाब ने सरकारी व्यय में 8% की कमी लाने के साथ-साथ धोखाधड़ी की पहचान, डुप्लिकेट पेंशनधारकों की पहचान तथा पेंशन लाभों के सत्यापन को सक्षम बनाया है। बुद्धिमान डेटा निष्कर्षण एवं प्रसंस्करण के माध्यम से 3.5 लाख पेंशनभोगियों का एक केंद्रीकृत डिजिटल रिपॉजिटरी तैयार किया गया है, जिसमें 235 से अधिक संरचित डेटा विशेषताओं तथा पीपीओ अभिलेख सम्मिलित हैं। यह परिवर्तन बिना मैनुअल डेटा प्रविष्टि, उपयोगकर्ता द्वारा पीडीएफ अपलोड अथवा बार-बार दस्तावेज़ स्कैन किए बिना संभव हुआ है, जिससे सुव्यवस्थित पेंशन सेवाओं, भौतिक रूप से कार्यालय जाने की आवश्यकता में कमी तथा विभिन्न हितधारकों के मध्य निर्बाध संवाद के लिए एक स्केलेबल डिजिटल आधार तैयार हुआ है।

स्वचालित सत्यापन एवं प्रमाणीकरण तंत्र के माध्यम से इस प्रणाली ने जवाबदेही बढ़ाने तथा सार्वजनिक संसाधनों के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

प्रमुख विशेषताएँ

घटक एकीकरण

- आधार/बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण मॉड्यूल
- कॉमन सर्विस प्लेटफॉर्म एकीकरण
- बैंकिंग संस्थाओं के साथ एकीकरण
- कार्यप्रवाह एकीकरण

पेंशनर सेवाएँ

- ईकेवाईसी, एलटीसी मॉड्यूल, पेंशन स्लिप और फ़ॉर्म 16
- सेल्फ़-वेरिफ़िकेशन मॉड्यूल
- पेंशन संशोधन मॉड्यूल
- मेडिकल रीइम्बर्समेंट मॉड्यूल
- चेंज मैनेजमेंट और सक्सेशन एप्लीकेशन

प्रक्रिया स्वचालन

- ई-स्क्रॉल मॉड्यूल
- पेंशन उत्तराधिकार/ पारिवारिक पेंशन मॉड्यूल
- वसूली मॉड्यूल
- पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी मॉड्यूल
- पेंशन प्रसंस्करण मॉड्यूल
- जीवन प्रमाणन मॉड्यूल
- वित्त मॉड्यूल
- लीगेसी डेटा शुद्धीकरण एवं प्रसंस्करण मॉड्यूल

अपनाए गए नवाचार

ई-केवाईसी एवं जीवन प्रमाण-पत्र का एकीकृत प्रमाणीकरण

ओटीपी आधारित ई-केवाईसी और जीवन प्रमाण-पत्र (जेपीपी) के एकीकरण के माध्यम से दोहरे स्तर का प्रमाणीकरण सुनिश्चित किया गया है। यह प्रणाली जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण एवं जीवंतता सत्यापन के साथ पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) अभिलेखों का स्वतः मिलान कर फर्जी अथवा दोहरे पेंशन मामलों की पहचान करती है।

शून्य-स्पर्श डिजिटल पेंशन डेटा रूपांतरण

इंटेलिजेंट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके 3.5 लाख पेंशनभोगियों का एक सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस बनाया गया। इसमें 235 से ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड डेटा एट्रिब्यूट्स और पीपीओ रिकॉर्ड्स शामिल थे, और इसे बनाने के लिए मैनुअल डेटा एंट्री, यूज़र अपलोड या बार-बार स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी।

दस्तावेज़ प्रकार का स्वचालित सत्यापन

प्रणाली दस्तावेज़ के प्रकार तथा लाभार्थी से उसकी प्रासंगिकता की स्वतः पहचान करती है और अमान्य दस्तावेज़ों को बिना मैनुअल हस्तक्षेप के अस्वीकार कर देती है। इससे दस्तावेज़ अस्वीकृति से संबंधित कार्यभार में 70 प्रतिशत की कमी आई है तथा प्रसंस्करण प्रक्रिया 10 गुना तेज हुई है।

उच्च-परिमाण प्रारंभिक परिनियोजन (टॉप-हेवी मॉडल)

प्लेटफॉर्म को आरंभ से ही उत्पादन-स्तर के ऐतिहासिक डेटा, दस्तावेज़ अभिलेखों तथा लेनदेन संबंधी रिकॉर्ड के साथ परिनियोजित किया गया है, जिससे यह वास्तविक कार्यभार को संभालने के लिए प्रारंभ से ही तैयार है।

स्तरीय डेटा प्रबंधन एवं व्यक्तिगत जानकारी के सुरक्षित संचालन हेतु डेटा टनल संरचना

डुअल-डेटाबेस डिज़ाइन सुरक्षित पीआईआई गवर्नेंस, डेटा को अलग-अलग करने, लाइफ़साइकल मैनेजमेंट और डेटा के इंजेक्शन से लेकर स्ट्रक्चर्ड स्टोरेज तक नियंत्रित मूवमेंट को संभव बनाता है, जिससे स्केलेबिलिटी और नियमों का पालन सुनिश्चित होता है।

पूर्व-सक्षम बुद्धिमान लेखा-परीक्षण एवं सत्यापन ढाँचा

प्रसंस्करण कार्यप्रवाह में स्वचालित सत्यापन प्रक्रियाएँ समाहित की गई हैं, जो स्वयं लेखा-परीक्षण, बिना मैनुअल हस्तक्षेप के अनुपालन तथा न्यूनतम लेखा-परीक्षण प्रयास सुनिश्चित करती हैं।

आधार पारिस्थितिकी तंत्र का एकीकरण एवं व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षा ढाँचा

प्रणाली में मास्किंग, डेटा अस्पष्टीकरण तथा सुरक्षित डेटा प्रबंधन जैसी अंतर्निहित व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं, जो आधार से संबद्ध सूचनाओं के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई) के दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

डेटा-संचालित डेटाबेस संरचना

दस्तावेज़-उन्मुख एवं स्कीमा-रहित डेटाबेस संरचना के माध्यम से बड़ी मात्रा में असंरचित एवं अर्द्ध-संरचित डेटा का कुशल भंडारण एवं त्वरित पुनर्प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। इससे प्रणाली की मापनीयता, प्रदर्शन एवं डेटा प्रबंधन क्षमता में वृद्धि होती है।

मानक प्रतिवेदन

सभी रिपोर्ट एक केंद्रीकृत टेम्पलेट ढांचे का पालन करती हैं और इसमें डीडीपीए और यूआईडीएआई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मेटाडेटा, डिजिटल वॉटरमार्क और अनुपालन घोषणाएं शामिल हैं।

इस्तेमाल की गई तकनीकें

घटक	प्रयुक्त प्रौद्योगिकी/ उपकरण
एप्लिकेशन/बिजनेस लेयर	.NET Core (MVC)
डेटाबेस लेयर	PostgreSQL एवं MongoDB
निगरानी एवं ऑब्जर्वेबिलिटी	Zabbix (ओपन सोर्स)
पहचान एवं अभिगम प्रबंधन	Keycloak (ओपन सोर्स)
पीआईएम/ पीएएम	PAM 360
लोड बैलेंसिंग एवं उच्च उपलब्धता	HAProxy
डेवऑप्स एवं सीआई/सीडी स्वचालन	Jenkins / GitLab
सॉफ्टवेयर परीक्षण एवं गुणवत्ता आश्वासन	JMeter / Postman
भेद्यता एवं सुरक्षा परीक्षण	ZAP एवं Burp Suite Professional
लॉग निगरानी एवं धोखाधड़ी पहचान	इन-हाउस विकसित उपकरण

लाभ

आधार-सक्षम डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र में परिवर्तन

पीएसपी लागू होने के बाद वर्ष 2026 में डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) को अपनाने की दर 6 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत हो गई। आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से लगभग 20,000 से 25,000 फर्जी अथवा अपात्र पेंशन अभिलेखों की पहचान कर उन्हें प्रणाली से हटाने में सहायता मिली।

वास्तविक समय में पेंशन बंद करने की कार्यप्रवाह प्रणाली

मृत्यु, विवाह अथवा आय सीमा से संबंधित निर्धारित शर्तों के सत्यापित होने पर, बाहरी रजिस्ट्रियों के साथ एकीकरण के माध्यम से पेंशन भुगतान स्वतः बंद कर दिया जाता है। प्रणाली अतिरिक्त भुगतान की भी पहचान करती है तथा आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करती है।

डिजिटल पेंशन फॉरेंसिक एवं इंटेलिजेंस इंजन

30 से 40 वर्ष पूर्व जारी किए गए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) अभिलेखों का उपयोग करते हुए यह प्रणाली पेंशन अधिकारों का सटीक पुनर्निर्माण एवं सत्यापन करती है। साथ ही वेतन आयोगों के अनुसार पेंशन संशोधन, महँगाई राहत (डीए) के बकाया तथा अन्य वित्तीय गणनाओं को स्वचालित करती है। यह अतिरिक्त भुगतान की पहचान, बैंक ई-स्क्रॉल के माध्यम से वसूली के सत्यापन तथा संपूर्ण डिजिटल लेखा-परीक्षण अभिलेख के रखरखाव की सुविधा भी प्रदान करती है।

लेखा-परीक्षण एवं अनुरेखण ढाँचा

यह प्रणाली सेवानिवृत्ति से लेकर पारिवारिक पेंशन तक संपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया का एंड-टू-एंड लेखा-परीक्षण सुनिश्चित करती है। इसके माध्यम से महालेखाकार (एजी) कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) तथा अन्य संबंधित संस्थाओं के लिए आवश्यक वैधानिक प्रतिवेदन, लेखे एवं दस्तावेज़ बिना किसी मैनुअल डेटा प्रविष्टि के स्वतः तैयार किए जाते हैं।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड

यह डैशबोर्ड वास्तविक समय के विश्लेषण, पूर्वानुमान आधारित आँकड़ों तथा बुद्धिमान निर्णय-सहायता सुविधाओं के माध्यम से पेंशन प्रशासन को अधिक सक्रिय, प्रभावी एवं वित्तीय प्रबंधन को अधिक सक्षम बनाता है।

आगे की राह

पी.एस.पी. पंजाब की भावी कार्ययोजना के अंतर्गत फेस ऑथेंटिकेशन-सक्षम मोबाइल अनुप्रयोग के माध्यम से सुरक्षित एक-क्लिक ईकेवाईसी तथा डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे मैनुअल प्रक्रियाओं में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा पेंशनभोगियों के लिए सेवाएँ अधिक सुविधाजनक बनेंगी।

डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा मशीन लर्निंग का उपयोग करते हुए इस प्लेटफ़ॉर्म को एआई-संचालित पेंशन सहायक के साथ और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, जो स्वाभाविक संवाद के माध्यम से सूचनाओं एवं सेवाओं तक सहज पहुँच प्रदान करेगा। इन पहलों के माध्यम से पी.एस.पी. पंजाब एक बुद्धिमान एवं नागरिक-केंद्रित डिजिटल सुशासन मंच के रूप में विकसित होगा, जो त्वरित सेवा वितरण, शीघ्र शिकायत निवारण तथा पेंशनभोगियों की संतुष्टि में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करेगा।

> वर्ष 2025 में प्रारंभ किया गया पेंशनर सेवा पोर्टल (पीएसपी) पंजाब, पंजाब सरकार की एक प्रमुख डिजिटल सुशासन पहल है, जिसका उद्देश्य पारदर्शी, दक्ष एवं पेपरलेस पेंशन प्रसंस्करण तथा सेवाएँ उपलब्ध कराना है। यह पहल प्रत्येक पेंशनभोगी को सम्मानपूर्वक सेवाएँ प्रदान करने, उन्हें निरंतर जोड़े रखने तथा आवश्यक सूचनाएँ उपलब्ध कराने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
>
> एल्गोरिद्म एवं डेटा विश्लेषण आधारित इस प्लेटफॉर्म ने पेंशन प्रक्रिया के संपूर्ण जीवनचक्र—प्रारंभ से लेकर भुगतान तक—को एक सुरक्षित, पेपरलेस एवं एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित कर दिया है। मैनुअल प्रणाली से पूर्णतः डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर यह परिवर्तन रिकॉर्ड समय में संपन्न हुआ, जिससे कार्यकुशलता एवं पारदर्शिता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा फर्जी पेंशन भुगतान पर प्रभावी रोक लगी।
>
> मैं एनआईसी टीम को उनके उत्कृष्ट समर्पण, नवाचारी सोच तथा प्रभावी क्रियान्वयन के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। उनके निरंतर प्रयासों और प्रतिबद्धता ने इस डिजिटल परिवर्तन को सफलतापूर्वक साकार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
>
> **श्री एम. के. अरविंद,** आईएएस
> ट्रेज़री और अकाउंट्स के निदेशक

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी पंजाब राज्य केंद्र
कमरा नं 31, पंजाब सिविल सचिवालय
सेक्टर-1, चंडीगढ़ - 160001
ईमेल: sio-punjab@nic.in, फ़ोन: 0172-2747357

ई-एस.सी.एम.एस

मणिपुर में मदिरा वितरण की निगरानी एवं प्रबंधन हेतु एक डिजिटल मंच

संपादित : **लाल बहादुर सिंह**

मणिपुर सरकार का आबकारी विभाग राज्य में मदिरा के निर्माण, आयात, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं बिक्री का विनियमन करता है। पारदर्शिता, अनुपालन तथा आपूर्ति श्रृंखला निगरानी को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभाग ने ई-सप्लाई चेन प्रबंधन प्रणाली (ई-एस.सी.एम.एस) को लागू किया है।

ई-एस.सी.एम.एस एक एकीकृत डिजिटल मंच है, जो बॉटलिंग से लेकर खुदरा बिक्री तक मदिरा की आवाजाही का पता लगाता है। यह आपूर्तिकर्ताओं, बॉटलरों, बंधित गोदामों, थोक विक्रेताओं तथा खुदरा विक्रेताओं सहित सभी हितधारकों को ई-अबकारी ढांचे से एकीकृत एक केंद्रीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ता है।

यह प्रणाली आबकारी आसंजक लेबल (ईएएल), क्यूआर कोड, सीरियल शिपिंग कंटेनर कोड (एस.एस.सी.सी), ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर (जी.टी.आई.एन), एक्सएमएल आधारित डेटा विनिमय तथा हैंडहेल्ड स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग कर बोतल-स्तरीय अनुरेखण, स्टॉक निगरानी, अवैध विचलन की रोकथाम तथा प्रभावी नियामकीय नियंत्रण सुनिश्चित करती है।

उद्देश्य

ई-एस.सी.एम.एस के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- मदिरा वितरण की एंड-टू-एंड डिजिटल ट्रैकिंग स्थापित करना।
- स्टॉक की आवाजाही में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- अवैध विचलन, प्रतिरूपण तथा अनधिकृत बिक्री को रोकना।

एन. बिनोद सिंह
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
binod@nic.in

एन. बिनोद सिंह
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
binod@nic.in

एस. रमेश सिंह
वैज्ञानिक - सी
ramesh.s@nic.in

ई-सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (ई-एस.सी.एम.एस) एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है जिसे मणिपुर सरकार के आबकारी विभाग के लिए शराब वितरण प्रक्रिया पर नज़र रखने के लिए बनाया गया है। ई-आबकारी सिस्टम से जुड़ा प्लेटफ़ॉर्म, आबकारी एडहेसिव लेबल (ईएएल), क्यूआर कोड वेरिफिकेशन और रियल-टाइम इन्वेंट्री ट्रैकिंग के ज़रिए बोतलों को ट्रैक करता है। बॉटलिंग से रिटेल बिक्री तक सप्लाई चेन के कामों को डिजिटल बनाकर, ई-एस.सी.एम.एस पारदर्शिता बढ़ाता है, नकली उत्पादों की हेराफेरी और बिक्री रोकता है, रेगुलेटरी निगरानी मज़बूत करता है, रेवेन्यू की सुरक्षा बेहतर करता है, डेटा-आधारित फ़ैसले लेने में मदद करता है, नियमों के पालन की निगरानी आसान बनाता है और सप्लाई चेन में असरदार तरीके से नियम लागू करने में मदद करता है।

- ईएएल के माध्यम से बोतल-स्तरीय अनुरेखण सुनिश्चित करना।
- इन्वेंटरी एवं लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को सुव्यवस्थित बनाना।
- क्यूआर कोड स्कैनिंग के माध्यम से वास्तविक समय सत्यापन सक्षम करना।
- सप्लाई चेन ऑपरेशन्स को ई-आबकारी के साथ इंटीग्रेट करें
- परिचालन दक्षता एवं इन्वेंटरी नियंत्रण में सुधार करना।

शामिल हितधारक

यह सिस्टम इन चीज़ों को जोड़ता है:

- आबकारी विभाग, मणिपुर सरकार
- आसवनियां/आपूर्तिकर्ता
- बॉटलर
- बंधित गोदाम
- थोक विक्रेता
- खुदरा विक्रेता

सभी हितधारकों का पंजीकरण ई-अबकारी मणिपुर प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

आबकारी विभाग की भूमिका

ई-एस.सी.एम.एस में आबकारी विभाग नियामकीय प्राधिकरण एवं प्रशासक की भूमिका निभाता है।

विभाग की प्रमुख जिम्मेदारियाँ हैं:

- हितधारकों का पंजीकरण एवं प्रबंधन।
- आपूर्तिकर्ताओं, बॉटलरों, ब्रांडों, लेबलों, गोदामों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तथा मूल्य निर्धारण से संबंधित मास्टर डेटा का रखरखाव।
- हितधारकों के उपयोगकर्ता खाते बनाना।
- ईएएल मांगों का प्रबंधन एवं अनुमोदन।
- संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में स्टॉक की आवाजाही की निगरानी।

प्रणाली संरचना का अवलोकन

ई-एस.सी.एम.एस एक केंद्रीकृत वेब-आधारित मंच है, जिसे हैंडहेल्ड एंड्रॉयड स्कैनिंग उपकरणों के साथ एकीकृत किया गया है।

यह प्रणाली केस एवं बोतल दोनों स्तरों पर मदिरा की ट्रैकिंग हेतु मानकीकृत पहचान तंत्र का उपयोग करती है। प्रत्येक केस को एस.एस.सी.सी आधारित विशिष्ट पहचान प्रदान की जाती है, जबकि प्रत्येक बोतल को एक विशिष्ट ईएएल संख्या से जोड़ा जाता है।

आबकारी आसंजक लेबल (ईएएल) प्रबंधन

ईएएल बोतल-स्तरीय अनुरेखण का मुख्य आधार है।

- **ईएएल मांग:** आसवनियां अथवा आपूर्तिकर्ता आबकारी विभाग को ईएएल की मांग प्रस्तुत करते हैं।
- **अनुमोदन प्रक्रिया:** स्वीकृत ईएएल संबंधित आसवनी को आबकारी विभाग द्वारा जारी किए जाते हैं।
- **बॉटलरों को वितरण:** बॉटलिंग कार्य हेतु आसवनियां ईएएल बॉटलरों को वितरित करती हैं।

बॉटलिंग एवं एक्सएमएल अपलोड प्रक्रिया

बॉटलर बोतलों पर ईएएल चिपकाते हैं तथा उत्पादन एवं पैकेजिंग संबंधी जानकारी एक्सएमएल फ़ाइलों के माध्यम से अपलोड करते हैं। एक्सएमएल फ़ाइल में निम्नलिखित विवरण

शामिल होते हैं:

- आयात अनुज्ञा संख्या
- एस.एस.सी.सी
- बोतल जी.टी.आई.एन
- केस जी.टी.आई.एन
- पैक आकार
- बोतलों की संख्या
- समाप्ति तिथि
- ईएएल संख्याएँ

सत्यापन के उपरांत आयात अनुज्ञा शिपमेंट प्रक्रिया के लिए उपलब्ध हो जाती है।

शिपमेंट एवं परिवहन प्रक्रिया

प्रणाली में दर्ज शिपमेंट विवरण में शामिल हैं:

- आयात अनुज्ञा संख्या
- चालान संख्या एवं तिथि
- परिवहनकर्ता का विवरण
- वाहन संबंधी जानकारी
- गंतव्य गोदाम

प्रेषित प्रत्येक केस पर उसके एस.एस.सी.सी से संबद्ध क्यूआर कोड अंकित होता है, जिससे उसकी ट्रैकिंग एवं सत्यापन संभव होता है।

बंधित गोदाम में प्राप्ति

बॉन्डेड वेयरहाउस में हैंडहेल्ड स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके कंसाइनमेंट लिए जाते हैं।

क्यूआर कोड वेरिफिकेशन

- केस पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करता है
- अपलोड किए गए रिकॉर्ड से शिपमेंट डेटा को वेरिफ़ाई करता है
- वेयरहाउस डेस्टिनेशन और शिपमेंट की असलियत की पुष्टि करता है

स्टॉक अपडेट

- सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन होने पर:
- वेयरहाउस की इन्वेंट्री अपने आप अपडेट हो जाती है
- स्टॉक आगे के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपलब्ध हो जाता है।

थोक विक्रेता हेतु क्रय आदेश एवं प्रेषण

मणिपुर में थोक विक्रेता की भूमिका मणिपुर स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एम.एस.बी.सी.एल) द्वारा निभाई जाती है।

1. क्रय आदेश प्रस्तुत करना

- क्रय आदेश प्रणाली के माध्यम से तैयार एवं प्रस्तुत किए जाते हैं।

2. बंधित गोदाम से प्रेषण

प्रेषण के दौरान:

- केसों का स्कैन एवं सत्यापन किया जाता है।
- आवाजाही अभिलेख तैयार किए जाते हैं।
- स्टॉक स्तर स्वतः अद्यतन हो जाते हैं।

थोक विक्रेता द्वारा प्राप्ति

थोक विक्रेता हैंडहेल्ड स्कैनर का उपयोग करके खेपों की पुष्टि करते हैं। यह सिस्टम निम्नलिखित की पुष्टि करता है:

- शिपमेंट की प्रामाणिकता
- खरीद ऑर्डर मैपिंग
- केस विवरण
- गंतव्य जानकारी

सत्यापित स्टॉक स्वचालित रूप से थोक विक्रेता की इन्वेंट्री में जुड़ जाता है।

खुदरा विक्रेता मांग एवं आपूर्ति प्रक्रिया

रिटेलर सिस्टम के ज़रिए स्टॉक इंडेंट जमा करते हैं

थोक विक्रेता द्वारा स्टॉक निगरानी

स्थिति 1: स्टॉक उपलब्ध है

- आदेशों का तत्काल प्रसंस्करण किया जाता है।
- केसों को स्कैन कर प्रेषित किया जाता है।

स्थिति 2: स्टॉक उपलब्ध नहीं है

- बंधित गोदामों को पुनःपूर्ति आदेश भेजे जाते हैं।

खुदरा विक्रेता को प्रेषण एवं प्राप्ति

प्रेषण से पूर्व तथा प्राप्ति के समय केसों को स्कैन किया जाता है।

प्राप्ति सत्यापन

प्रणाली निम्नलिखित का सत्यापन करती है:

- खेप की प्रामाणिकता
- खुदरा विक्रेता मैपिंग
- शिपमेंट विवरण
- उत्पाद संबंधी जानकारी

सत्यापन के बाद खुदरा विक्रेता की इन्वेंटरी स्वतः अद्यतन हो जाती है।

बोतल-स्तरीय बिक्री एवं अनुरेखण

ई-एस.सी.एम.एस ईएएल अथवा बारकोड स्कैनिंग के माध्यम से बोतल-स्तरीय बिक्री सत्यापन सक्षम बनाता है।

बिक्री से पूर्व प्रत्येक बोतल का स्वामित्व एवं स्टॉक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए स्कैनिंग प्रणाली द्वारा प्रमाणीकरण किया जाता है। सत्यापन के बाद बिक्री का प्रसंस्करण पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) प्रणाली के माध्यम से किया जाता है, जो बिलिंग, भुगतान संग्रह, चालान निर्माण तथा रेजरपे एकीकृत डिजिटल भुगतान सुविधाएँ प्रदान करती है। वास्तविक समय बिक्री रिकॉर्डिंग के साथ इन्वेंटरी स्वतः अद्यतन हो जाती है।

खुदरा सत्यापन

प्रणाली सुनिश्चित करती है कि:

- केवल आवंटित बोतलों की बिक्री ही की जा सके।
- अलग-अलग रिटेलर्स के बीच बिक्री पर रोक है।
- अवैध विचलन को रोका जा सके।

बोतल-स्तरीय अनुरेखण के लाभ

- एंड-टू-एंड अनुरेखण
- नकली उत्पादों की रोकथाम
- विचलन नियंत्रण
- बिक्री की सटीक निगरानी
- बेहतर नियामकीय अनुपालन

प्रमुख विशेषताएँ

- केंद्रीकृत आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन
- वास्तविक समय स्टॉक ट्रैकिंग
- क्यूआर कोड आधारित सत्यापन
- बोतल-स्तरीय अनुरेखण
- एक्सएमएल आधारित डेटा एकीकरण
- स्वचालित इन्वेंटरी अद्यतन
- भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण
- हैंडहेल्ड उपकरण एकीकरण
- ई-अबकारी एकीकरण
- विचलन की रोकथाम
- ऑडिट ट्रेल एवं निगरानी

प्रमुख लाभ

प्रशासनिक लाभ

- बेहतर नियामकीय निगरानी
- अधिक पारदर्शिता एवं जवाबदेही
- सुदृढ़ अनुपालन निगरानी
- बेहतर ऑडिट प्रबंधन

परिचालन लाभ

- तेज एवं कुशल स्टॉक प्रबंधन
- मैनुअल प्रक्रियाओं में कमी
- प्रभावी इन्वेंटरी प्रबंधन
- वास्तविक समय स्टॉक दृश्यता

सुरक्षा लाभ

- अनधिकृत आवाजाही की रोकथाम
- विचलन एवं नकली उत्पादों की पहचान
- सुरक्षित बोतल-स्तरीय प्रमाणीकरण

वित्तीय लाभ

- बेहतर राजस्व संरक्षण
- राजस्व रिसाव में कमी
- कर एवं शुल्क निगरानी में सुधार

भावी संभावनाएँ

ई-एस.सी.एम.एस को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है। इसमें क्षतिग्रस्त स्टॉक प्रबंधन, स्टॉक स्थानांतरण एवं वापसी, सामंजस्य एवं समायोजन मॉड्यूल, उन्नत विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड, मोबाइल आधारित निगरानी अनुप्रयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विसंगति पहचान जैसी सुविधाएँ जोड़ी जा सकती हैं, जिससे आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता एवं नियामकीय निगरानी और अधिक सुदृढ़ होगी।

निष्कर्ष

ई-एस.सी.एम.एस मणिपुर में मदिरा वितरण की निगरानी हेतु एक व्यापक डिजिटल ढांचा प्रदान करता है। ईएएल आधारित बोतल-स्तरीय अनुरेखण, क्यूआर कोड सत्यापन तथा वास्तविक समय इन्वेंटरी प्रबंधन के माध्यम से सभी हितधारकों को एक मंच पर एकीकृत करते हुए यह प्रणाली नियामकीय नियंत्रण को सुदृढ़ बनाती है, परिचालन दक्षता बढ़ाती है, अवैध विचलन को रोकती है तथा राजस्व संरक्षण सुनिश्चित करती है।

ई-अबकारी प्रणाली के साथ इसका एकीकरण राज्य भर में प्रभावी सुशासन एवं सुव्यवस्थित आबकारी प्रशासन को और

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी मणिपुर राज्य केंद्र
एनकेएन ब्लॉक, नया सचिवालय
इम्फाल, मणिपुर - 795001
ईमेल: sio-man@nic.in, फ़ोन: 0385-2225206

यू.एम.पी.एस

उत्तराखंड पर्वतारोहण गतिविधियों के लिए एकल खिड़की प्रणाली

संपादित : **विनोद कुमार गर्ग**

उत्तराखंड, हिमालय की अनेक प्रमुख पर्वत चोटियों एवं ट्रेकिंग मार्गों का केंद्र है, जहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्वतारोही और साहसिक पर्यटन के उत्साही आते हैं। किंतु दुर्गम एवं पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में पर्वतारोहण अभियानों के प्रबंधन की पारंपरिक व्यवस्था लंबी मैनुअल प्रक्रियाओं, विभिन्न विभागों से अनुमतियाँ प्राप्त करने की आवश्यकता तथा अभियानों की सीमित निगरानी जैसी चुनौतियों से जुड़ी थी।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए उत्तराखंड सरकार ने 26 सितंबर, 2021 को उत्तराखंड एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान उत्तराखंड पर्वतारोहण अनुमति प्रणाली (यू.एम.पी.एस) का शुभारंभ किया। यह पोर्टल पर्वतारोहण अनुमति एवं संबंधित सेवाओं के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच उपलब्ध कराता है। इसके साथ उत्तराखंड पर्वतारोहण प्रशासन का व्यापक डिजिटलीकरण करने वाले भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है।

पहल की आवश्यकता

साहसिक पर्यटन की बढ़ती लोकप्रियता ने ऐसी पारदर्शी, दक्ष एवं प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया, जो—

- परमिट अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाना
- विभागों के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करना
- पर्वतारोहियों की सुरक्षा एवं निगरानी को बेहतर बनाना
- पर्यावरणीय अनुपालन को सुदृढ़ करना
- आपातकालीन प्रतिक्रिया को अधिक त्वरित बनाना
- डेटा-आधारित योजना निर्माण एवं नीतिगत निर्णयों को समर्थन प्रदान करना

यू.एम.पी.एस की परिकल्पना विखंडित प्रक्रियाओं को समाप्त कर साहसिक पर्यटन प्रबंधन के लिए एक निर्बाध डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी।

अरुण शर्मा
तकनीकी निदेशक
sharma.arun@nic.in

शक्ति प्रसाद रतूड़ी
वैज्ञानिक - डी
shakti.raturi@nic.in

> यू.एम.पी.एस एक एकल खिड़की डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो उत्तराखंड में पर्वतारोहण अभियानों एवं ट्रेकिंग गतिविधियों के नियमन, सुविधा एवं निगरानी को सुव्यवस्थित बनाता है। अनुमति प्रक्रिया के डिजिटलीकरण तथा सभी हितधारकों को एकीकृत मंच पर जोड़कर यह प्रणाली प्रशासनिक दक्षता, पर्यटकों की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं सतत पर्यटन को सुदृढ़ बनाती है। साथ ही, यह साहसिक पर्यटन क्षेत्र में डेटा-आधारित सुशासन को भी बढ़ावा देती है।

पोर्टल का अवलोकन

यू.एम.पी.एस पर्वतारोहण गतिविधियों से जुड़े सभी प्रमुख हितधारकों, जैसे पर्वतारोही, अभियान दल, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन (आईएमएफ), वन विभाग, पर्यटन विभाग तथा जिला प्रशासन, को एक ही मंच पर एकीकृत करता है।

पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता—

- पहचान की गई 83 चोटियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें
- अभियान की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करें
- ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करें
- डिजिटल पेमेंट करें
- आवेदन की स्थिति को रियल-टाइम में ट्रैक करें
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचनाएं और मंज़ूरी प्राप्त करें

पारंपरिक व्यवस्था की चुनौतियाँ

यू.एम.पी.एस के लागू होने से पहले अभियान आयोजकों को अनुमति प्राप्त करने के लिए लंबी एवं जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था।

प्रमुख चुनौतियाँ

- सरकारी दफ़्तरों के कई बार चक्कर लगाना
- अलग-अलग अधिकारियों को एक जैसे दस्तावेज़ जमा करना
- मैन्युअल रूप से जांच और वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं
- काम की मौजूदा स्थिति का तुरंत पता न चल पाना
- अलग-अलग विभागों के बीच बातचीत में देरी
- चल रहे अभियानों की जानकारी ठीक से न मिल पाना
- अभियानों के पुराने रिकॉर्ड को बनाए रखने में मुश्किल
- प्लानिंग और एनालिसिस के लिए सेंट्रलाइज़्ड डेटा का न होना

इन चुनौतियों की वजह से अक्सर अभियान आयोजित करने वाले लोग हतोत्साहित होते थे और सरकारी एजेंसियों पर प्रशासनिक बोझ बढ़ जाता था।

प्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ

ऑनलाइन पंजीकरण एवं उपयोगकर्ता प्रबंधन

पोर्टल विभिन्न श्रेणियों के उपयोगकर्ताओं के लिए भूमिका-आधारित अभिगम उपलब्ध कराता है, जिससे अभियान आयोजक, अधिकारी तथा प्रशासक सुरक्षित एवं नियंत्रित वातावरण में अपनी-अपनी भूमिका के अनुरूप प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।

डिजिटल अनुमति प्रबंधन

एक पूरी तरह से स्वचालित परमिट प्रबंधन ढांचा मानवीय हस्तक्षेप के बिना आवेदन प्रसंस्करण, सत्यापन, अनुमोदन और जारी करने की सुविधा प्रदान करता है।

पर्वत चोटियों का सूचना भंडार

पोर्टल में एक केंद्रीकृत डेटाबेस उपलब्ध है, जिसमें अधिसूचित पर्वत चोटियों, पर्वतारोहण के उपयुक्त मौसम, मार्गों, नियमों तथा दिशा-निर्देशों से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई है।

अभियान निगरानी प्रणाली

अधिकारी अभियान की गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं और अपडेटेड रिकॉर्ड बनाए रख सकते हैं, जिससे सुरक्षा प्रबंधन और ऑपरेशनल देखरेख बेहतर होती है।

एकीकृत डिजिटल भुगतान प्रणाली

पोर्टल के माध्यम से अभियान शुल्क, अनुमति शुल्क तथा अन्य लागू करों का सुरक्षित ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है, जिससे भुगतान प्रक्रिया अधिक सरल एवं पारदर्शी बनती है।

स्वचालित सूचनाएँ

आवेदकों को आवेदन की स्थिति, मंज़ूरी, कमियों और परमिट जारी होने के बारे में अलर्ट और अपडेट मिलते हैं।

प्रशासनिक डैशबोर्ड

व्यापक प्रशासनिक डैशबोर्ड के माध्यम से अधिकारी—

- आवेदनों की समीक्षा कर सकते हैं।
- पर्वतारोहण अभियानों की निगरानी कर सकते हैं।
- विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं।
- पर्वत चोटियों के उपयोग का विश्लेषण कर सकते हैं।
- पर्यटन संबंधी प्रवृत्तियों का अध्ययन कर सकते हैं।
- नीति-निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

केंद्रीकृत डेटा प्रबंधन

पोर्टल पर्वतारोहण अभियानों से संबंधित सभी सूचनाओं के लिए एकल एवं केंद्रीकृत डेटा भंडार के रूप में कार्य करता है, जिससे आँकड़ों की शुद्धता, एकरूपता तथा उपलब्धता सुनिश्चित होती है।

प्रौद्योगिकी संरचना

बढ़ती उपयोगकर्ता संख्या तथा भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यू.एम.पी.एस को मापनीय एवं सुदृढ़ प्रौद्योगिकी संरचना पर विकसित किया गया है।

एप्लिकेशन संरचना

- वेब-आधारित केंद्रीकृत प्लेटफ़ॉर्म।
- मॉड्यूलर एवं मापनीय डिज़ाइन।
- सेवा-उन्मुख कार्यप्रवाह संरचना।
- विभिन्न उपकरणों के लिए रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफ़ेस

प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ

फ्रंट एंड

- एएसपी.नेट
- एजैक्स
- जेक्वेरी
- बूटस्ट्रैप

बैक एंड

- पोस्टग्रीएसक्यूएल डेटाबेस

क्लाउड अवसंरचना

- राज्य डेटा केंद्र के क्लाउड पर होस्ट।
- उच्च उपलब्धता वाली संरचना।
- बैकअप एवं आपदा पुनर्प्राप्ति व्यवस्था।
- सुरक्षित होस्टिंग वातावरण।
- केंद्रीकृत निगरानी एवं अनुरक्षण।

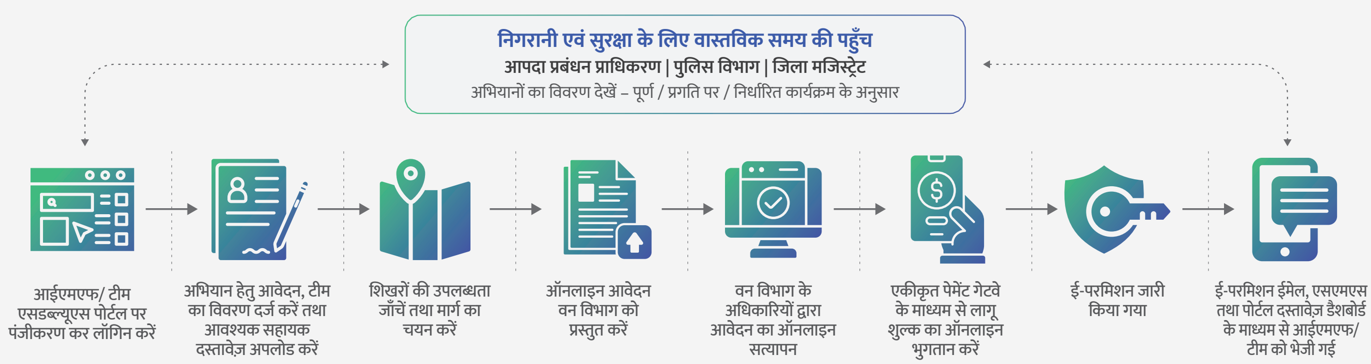

▲ चित्र 8.1 **यू.एम.पी.एस (एसडब्ल्यूएस) के ज़रिए डिजिटल वर्क फ़्लो**

दृष्टि एवं उद्देश्य

इस पहल का मकसद उत्तराखंड को टेक्नोलॉजी-आधारित एडवेंचर टूरिज्म गवर्नेंस के लिए एक मॉडल राज्य के तौर पर स्थापित करने का दीर्घकालिक विज़न है।

- **यूनिफाइड डिजिटल इकोसिस्टम:** एडवेंचर टूरिज्म की पूरी प्रक्रिया के लिए एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म देना।
- **ऑपरेशनल एक्सीलेंस:** ऑटोमेशन के ज़रिए पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करना।
- **बेहतर सुरक्षा:** अभियान की ट्रैकिंग को बेहतर बनाना और आपातकालीन स्थिति में प्रतिक्रिया देने की क्षमता को मज़बूत करना।
- **सस्टेनेबल टूरिज्म:** पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देना और हिमालय के नाज़ुक इकोसिस्टम को बचाना।
- **डेटा-आधारित गवर्नेंस:** सही फ़ैसले लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर और पॉलिसी बनाने वालों को रियल-टाइम जानकारी और एनालिटिकल जानकारी उपलब्ध कराना।

हितधारकों को लाभ

पर्वतारोहियों के लिए

- तेज़ी से मंज़ूरी
- आसान प्रक्रियाएँ
- कम कागज़ी काम
- जानकारी तक ऑनलाइन पहुँच
- ज़्यादा पारदर्शिता

सरकारी विभागों के लिए

- बेहतर तालमेल
- मानक कार्य-प्रक्रियाएँ
- बेहतर निगरानी क्षमताएँ
- प्रशासनिक बोझ में कमी
- बेहतर रिकॉर्ड मैनेजमेंट

स्थानीय समुदायों के लिए

- पर्यटन के ज़्यादा अवसर
- एडवेंचर टूरिज़्म से आर्थिक विकास
- स्थानीय सेवाओं और सहायता प्रणालियों की बेहतर दृश्यता

नीति-निर्माताओं के लिए

- सटीक और रियल-टाइम डेटा तक पहुँच
- बेहतर योजना और संसाधनों का आवंटन
- बेहतर पर्यावरण और पर्यटन प्रबंधन

प्रभाव एवं उपलब्धियाँ

वर्ष 2021 में लॉन्च होने के बाद से, इस पोर्टल ने उत्तराखंड में पर्वतारोहण गतिविधियों के मैनेजमेंट में काफी सुधार किया है।

मुख्य नतीजे

- अभियान की मंज़ूरी के लिए स्टैंडर्ड प्रोसेस
- अलग-अलग मंज़ूरी प्रक्रियाओं का खात्मा
- बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही
- पर्यटकों की सुरक्षा और अभियान की ट्रैकिंग में सुधार
- पर्वतारोहण की जानकारी का सेंट्रलाइज़्ड डेटाबेस
- विभागों के बीच बेहतर कामकाज की क्षमता
- पर्यावरण की निगरानी और नियमों का पालन मज़बूत हुआ

सफलता के पैमाने

- 2021 से सफलतापूर्वक चल रहा है
- 100 से ज़्यादा अभियान परमिट जारी किए गए
- 500 से ज़्यादा पर्वतारोहियों को सुविधा दी गई
- 83 चिन्हित पर्वतारोहण चोटियां पूरी तरह से कवर की गयी।

निष्कर्ष

यू.एम.पी.एस एक नई तरह की ई-गवर्नेंस पहल है, जिसने एक पारदर्शी, कुशल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए पर्वतारोहण के मैनेजमेंट को आसान और बेहतर बनाया है। परमिट से जुड़े कामों को डिजिटल बनाकर और सभी संबंधित लोगों को जोड़कर, यह ऑपरेशन की क्षमता, पर्यटकों की सुरक्षा, नियमों की निगरानी और टिकाऊ पर्यटन को बेहतर बनाता है। इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल करने के हिसाब से बनाया गया है; इस प्लेटफ़ॉर्म को एडवांस्ड ट्रैकिंग और एनालिटिक्स क्षमताओं के साथ और बेहतर बनाया जा सकता है और इसे हिमालयी राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इस तरह, यह भारत में टेक्नोलॉजी पर आधारित एडवेंचर टूरिज़्म गवर्नेंस के लिए एक मॉडल बन गया है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी
एनआईसी उत्तराखंड राज्य केंद्र
सचिवालय परिसर, सुभाष रोड राजपुर रोड
देहरादून, उत्तराखंड – 248001
ईमेल: sio-ua@nic.in, फ़ोन: 0135-2713739

वेदिका

सुशासन के लिए सुरक्षित, खोजयोग्य एवं सतत डिजिटल अभिलेख सुनिश्चित करना

संपादित : **अमित अग्रवाल**

सरकार द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक नीति, अधिसूचना, प्रतिवेदन, संसदीय बहस तथा प्रशासनिक अभिलेख राष्ट्र की संस्थागत स्मृति का हिस्सा होता है। इन अभिलेखों का संरक्षण तथा उन्हें सरलतापूर्वक खोजे और उपयोग किए जाने योग्य बनाना प्रभावी शासन, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है।

दशकों से सरकारी संगठन सूचना प्रबंधन के लिए भौतिक फाइलों और विभिन्न स्थानों पर स्थित दस्तावेज रिपॉजिटरियों पर निर्भर रहे हैं। यद्यपि इन व्यवस्थाओं ने अपने समय में उपयोगी भूमिका निभाई, किन्तु अभिलेखों की निरंतर बढ़ती मात्रा ने उनके भंडारण, पुनर्प्राप्ति और संरक्षण को अधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया है। फाइलों का पता लगाना कठिन हो सकता है, भौतिक अभिलेख समय के साथ क्षतिग्रस्त हो सकते हैं तथा विभिन्न प्रणालियों में संग्रहीत सूचनाओं तक पहुंच प्राप्त करना जटिल हो सकता है।

डिजिटल अभिलेखीकरण इन चुनौतियों का समाधान एक ऐसे संरचित डिजिटल वातावरण के माध्यम से करता है, जिसमें अभिलेखों का संरक्षण, संगठन और उपयोग संभव हो सके। यह सुनिश्चित करता है कि सूचनाएं भविष्य में संदर्भ हेतु उपलब्ध रहें तथा उनकी खोज क्षमता और परिचालन दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो।

आशीष विक्रम अस्थाना
उप महानिदेशक व एचओजी
avasthana@nic.in

ब्रिजेश कृष्ण शर्मा
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
brijesh@nic.in

मो० इफ्तेखार खान
वैज्ञानिक - सी
md.iftekar@nic.in

निवेदिता अग्रवाल
वैज्ञानिक - सी
nivedita.aggarwal@nic.in

> वेदिका, एनआईसी द्वारा विकसित एक डिजिटल अभिलेखीकरण एवं दस्तावेज प्रबंधन मंच है, जिसे मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों को उनके अभिलेखों के सम्पूर्ण जीवनचक्र में संरक्षित, व्यवस्थित और प्रबंधित करने में सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से अपनाए गए मुक्त-स्रोत रिपॉजिटरी मंच डी-स्पेस पर आधारित तथा सरकारी संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित, वेदिका बिखरे हुए दस्तावेज संग्रहों को संरचित, खोजयोग्य और दीर्घकालिक डिजिटल रिपॉजिटरियों में परिवर्तित करती है।

दस्तावेज भंडारण से ज्ञान संरक्षण तक

डिजिटल आर्काइविंग का मतलब सिर्फ़ कागज़ी रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइलों में बदलना नहीं है। इसकी असली अहमियत ऐसे सिस्टम बनाने में है जहाँ जानकारी को व्यवस्थित तरीके से रखा व खोजा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसे वापस पाया जा सके।

यहीं पर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (डीएमएस) एक अहम भूमिका निभाता है। डीएमएस व्यवस्थित स्टोरेज, खोजने की सुविधा, वर्शन ट्रैकिंग, एक्सेस कंट्रोल, ऑडिट की सुविधा और वर्कफ़्लो सपोर्ट देता है, जिससे यह पक्का होता है कि आर्काइव किए गए रिकॉर्ड बनने के लंबे समय बाद भी काम के बने रहें।

वेदिका (वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ अनुक्रमण और ज्ञान संग्रह) इन सभी सुविधाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर लाता है, जिससे संस्थाएँ अपनी जानकारी को सुरक्षित रख पाती हैं और सही समय पर सही यूज़र्स तक जानकारी पहुँचा पाती हैं।

वेदिका मंच

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित वेदिका, सरकारी संगठनों के लिए एक विन्यासयोग्य डिजिटल अभिलेखीकरण एवं दस्तावेज प्रबंधन मंच उपलब्ध कराती है।

इसका मूल आधार डी-स्पेस है, जो विश्व के सर्वाधिक प्रचलित मुक्त-स्रोत रिपॉजिटरी मंचों में से एक है। मैसाचुसेट्स प्रौद्योगिकी संस्थान (एमआईटी) पुस्तकालयों तथा हेवलेट-पैकार्ड प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित डी-स्पेस का उपयोग विश्वभर के हजारों संस्थान दीर्घकालिक डिजिटल संरक्षण और रिपॉजिटरी प्रबंधन के लिए करते हैं।

एनआईसी इस सिद्ध एवं विश्वसनीय आधारभूत मंच का उपयोग करते हुए इसे मंत्रालयों, विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करता है। परिणामस्वरूप एक ऐसा मंच उपलब्ध होता है जो अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और सरकारी आवश्यकताओं पर आधारित अनुकूलन का समन्वय प्रस्तुत करता है।

संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप

प्रत्येक संगठन अपनी सूचनाओं का प्रबंधन अलग-अलग तरीके से करता है। उदाहरण के लिए, किसी विधायी रिपॉजिटरी में अधिनियमों, नियमों और अधिसूचनाओं के लिए विशेष वर्गीकरण की आवश्यकता हो सकती है, जबकि किसी संसदीय रिपॉजिटरी में सामग्री को सत्रों, बहसों और सदस्यों के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है।

वेदिका इन विविध आवश्यकताओं को विन्यासयोग्य रिपॉजिटरी संरचनाओं, मेटाडेटा स्कीमाओं, संग्रह पदानुक्रमों, कार्यप्रवाहों तथा भूमिका-आधारित अभिगम नीतियों के माध्यम से पूरा करती है। संगठन अपने दस्तावेज वर्गीकरण, मेटाडेटा आवश्यकताओं तथा अभिगम नियमों को परिभाषित करते हैं, जबकि एनआईसी मंच को इन आवश्यकताओं के अनुरूप विन्यस्त करता है। आवश्यकता पड़ने पर विशेष प्रयोजन हेतु अनुकूलित इंटरफेस तथा समर्पित पोर्टलों का विकास भी किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ

वेदिका दस्तावेज प्रबंधन व डिजिटल अभिलेखीकरण से संबंधित

अनेक महत्वपूर्ण सुविधाएँ प्रदान करती है, जिनमें शामिल हैं-

- विन्यासयोग्य रिपॉजिटरी पदानुक्रमों के माध्यम से दस्तावेजों का संरचित संगठन।
- मेटाडेटा तथा पूर्ण-पाठ अनुक्रमण पर आधारित उन्नत खोज सुविधा।
- उपयोगकर्ता भूमिकाओं और संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप नियंत्रित अभिगम।
- दस्तावेज गतिविधियों का संस्करण अनुश्रवण एवं लेखापरीक्षणीयता।
- प्रस्तुतीकरण, समीक्षा एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं के लिए कार्यप्रवाह समर्थन।
- डिजिटल अभिलेखों का दीर्घकालिक संरक्षण।

इन सभी क्षमताओं के माध्यम से संगठन साधारण दस्तावेज भंडारण से आगे बढ़कर स्थायी डिजिटल ज्ञान रिपॉजिटरियों की स्थापना कर सकते हैं।

कार्यान्वयन दृष्टिकोण

वेदिका का कार्यान्वयन एक संरचित तथा सहयोगात्मक प्रक्रिया का अनुसरण करता है।

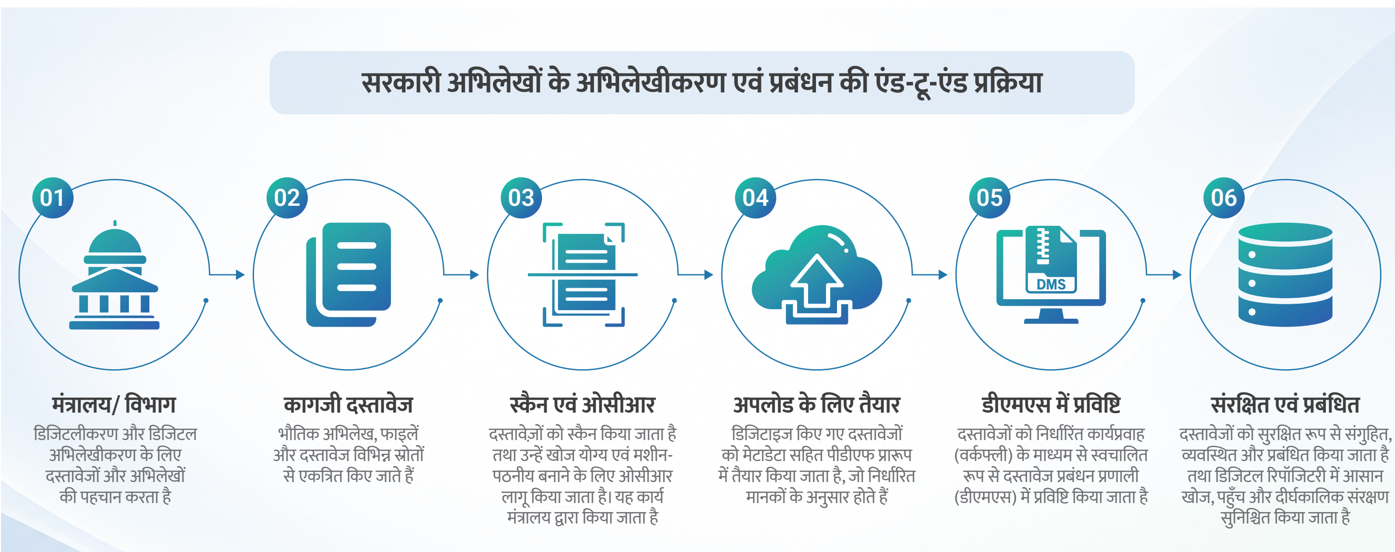

▲ चित्र 9.1 **वेदिका डिजिटल रिपॉज़िटरी कार्यान्वयन ढांचा**

प्रक्रिया की शुरुआत अभिलेखीकरण एवं डिजिटलीकरण हेतु अभिलेखों की पहचान से होती है। भौतिक दस्तावेजों को स्कैन कर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) तकनीकों की सहायता से संसाधित किया जा सकता है, जबकि डिजिटल अभिलेखों को सीधे रिपॉजिटरी में सम्मिलित किया जा सकता है। इसके पश्चात संगठन दस्तावेज वर्गीकरण, मेटाडेटा संरचना, उपयोगकर्ता भूमिकाएँ तथा अभिगम नीतियाँ निर्धारित करते हैं।

इन जानकारियों के आधार पर एनआईसी रिपॉजिटरी का विन्यास करता है, संग्रह संरचनाएँ और कार्यप्रवाह स्थापित करता है, परीक्षण एवं सत्यापन सम्पन्न करता है तथा समाधान को एनआईसी की क्लाउड अवसंरचना पर परिनियोजित करता है। परिनियोजन के बाद उपयोगकर्ताओं का ऑनबोर्डिंग तथा परिचालन सहायता भी प्रदान की जाती है।

व्यवहार में वेदिका

वेदिका का सफलतापूर्वक उपयोग अनेक महत्वपूर्ण सरकारी रिपॉजिटरियों में किया जा रहा है, जो सार्वजनिक अभिगम वाले अभिलेखागारों और आंतरिक उपयोग हेतु सुरक्षित रिपॉजिटरियों—दोनों प्रकार के वातावरणों में इसकी बहुमुखी उपयोगिता को प्रदर्शित करता है।

संसद डिजिटल पुस्तकालय

संसद डिजिटल पुस्तकालय संसदीय अभिलेखों की एकीकृत रिपॉजिटरी उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता संसदीय बहसों, समिति प्रतिवेदनों, बजट भाषणों तथा अन्य संसदीय दस्तावेजों को एक ही मंच पर खोज सकते हैं। यह रिपॉजिटरी सूचना की उपलब्धता को सुदृढ़ करते हुए पारदर्शिता और जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है।

इंडिया कोड

इंडिया कोड एक केंद्रीकृत विधायी रिपॉजिटरी है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित अधिनियम, नियम, विनियम तथा अधिसूचनाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रमाणीकृत प्रकाशन कार्यप्रवाह के माध्यम से यह रिपॉजिटरी उपयोगकर्ताओं को सत्यापित एवं अद्यतन विधायी जानकारी तक विश्वसनीय पहुँच सुनिश्चित करती है।

राज्यसभा डिजिटल रिपॉजिटरी

राज्यसभा डिजिटल रिपॉजिटरी वर्ष 1952 से अब तक की संसदीय बहसों और कार्यवाहियों का संरक्षण करती है। इसकी उन्नत खोज सुविधाएँ उपयोगकर्ताओं को विभिन्न खोज मानदंडों के आधार पर संसदीय इतिहास के दशकों पुराने अभिलेखों तक पहुँच प्रदान करती हैं।

राज्यसभा सचिवालय आंतरिक रिपॉजिटरी

यही मंच सुरक्षित आंतरिक रिपॉजिटरियों का भी समर्थन करता है, जहाँ संगठनात्मक आवश्यकताओं के अनुसार अभिगम को नियंत्रित किया जाता है। यह कार्यान्वयन दर्शाता है कि विन्यास-आधारित अभिगम प्रबंधन के माध्यम से वेदिका सार्वजनिक अभिलेखागारों तथा गोपनीय संस्थागत रिपॉजिटरियों—दोनों का प्रभावी समर्थन कर सकती है।

प्रभाव

अभिलेखों के व्यवस्थित संरक्षण तथा त्वरित पुनर्प्राप्ति को सक्षम बनाकर वेदिका सरकारी संगठनों की भौतिक भंडारण पर निर्भरता कम करने, सूचनाओं तक पहुँच बेहतर बनाने तथा भावी पीढ़ियों के लिए संस्थागत स्मृति के संरक्षण में सहायता प्रदान करती है।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वेदिका स्थिर अभिलेखों को ऐसे सुलभ ज्ञान-संसाधनों में परिवर्तित करती है जो सुशासन, अनुसंधान, पारदर्शिता तथा सूचित निर्णय-निर्माण को सशक्त बनाते हैं।

निष्कर्ष

जैसे-जैसे सरकारें डिजिटल-प्रथम प्रशासन को अपनाती जा रही हैं, सूचनाओं का प्रभावी संरक्षण और प्रबंधन एक रणनीतिक आवश्यकता बन गया है। वेदिका एक संरचित, अनुकूलनीय और सिद्ध डिजिटल अभिलेखीकरण एवं दस्तावेज प्रबंधन मंच प्रदान करती है, जो संगठनों को ऐसे रिपॉजिटरी विकसित करने में सहायता करता है जो ज्ञान का संरक्षण करें, खोजयोग्यता बढ़ाएँ और सुशासन को सुदृढ़ बनाएं।

वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय रिपॉजिटरी आधार पर निर्मित तथा सरकारी संस्थाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित, वेदिका दस्तावेज भंडारण से दीर्घकालिक डिजिटल ज्ञान संरक्षण की दिशा में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रही है।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

आशीष विक्रम अस्थाना
उप महानिदेशक और एचओजी
एनआईसी मुख्यालय, ए-ब्लॉक, लोधी रोड
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, दिल्ली – 110003
ईमेल: avasthana@nic.in, फ़ोन: 011-24305887

प्रोद्योगिकी अद्यतन

जॉग फ्रेमवर्क

एसएसएच रहित अनुप्रयोग परिनियोजन एवं प्रबंधन की एक सुरक्षित व्यवस्था

संपादित : **सी. जे. एंटनी**

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र देशभर के विभिन्न सरकारी विभागों के लिए डिजिटल सार्वजनिक सेवाओं और ई-गवर्नेंस अनुप्रयोगों के विकास एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन अनुप्रयोगों का संचालन करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक होता है कि संबंधित विभाग अपने डेटा पर पूर्ण स्वामित्व एवं नियंत्रण बनाए रखें।

परंपरागत रूप से अनुप्रयोगों के परिनियोजन और रखरखाव के लिए विकास दल को उत्पादन सर्वरों तक प्रत्यक्ष पहुँच प्रदान की जाती रही है। यद्यपि यह व्यवस्था सुविधाजनक थी, किंतु इससे डेटा अखंडता, परिचालन पारदर्शिता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ उत्पन्न हो सकती थीं। दूसरी ओर, प्रत्यक्ष सर्वर पहुँच के बिना अनुप्रयोगों का सुरक्षित और प्रभावी परिनियोजन भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, एनआईसी केरल ने जॉग (जेनकिंस, ओपनसर्च और गिटिया) फ्रेमवर्क बनाया है। यह एक सुरक्षित डिप्लॉयमेंट और एप्लीकेशन मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, जो डेवलपर्स को प्रोडक्शन सर्वर का सीधा एक्सेस दिए बिना एंड-टू-एंड सॉफ़्टवेयर डिलीवरी की सुविधा देता है। जेनकिंस, ओपनसर्च और गिटिया जैसी ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया यह फ्रेमवर्क ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, सेंट्रलाइज़्ड ऑब्ज़र्वेबिलिटी और कंट्रोल्ड ऑपरेशनल वर्कफ़्लो को सपोर्ट करता है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा पर डिपार्टमेंट का कंट्रोल भी बनाए रखता है।

जॉग फ्रेमवर्क का अवलोकन

जॉग फ्रेमवर्क का मूल सिद्धांत है कि अनुप्रयोगों का परिनियोजन सर्वर तक प्रत्यक्ष पहुँच के बिना भी सुरक्षित और प्रभावी ढंग से किया जा सकता है।

बिंदु एस. कुमार
उप महानिदेशक
bindu.sk@nic.in

विपिन बोस
वैज्ञानिक - सी
bose.vipin@nic.in

> एनआईसी केरल द्वारा विकसित जॉग फ्रेमवर्क, जेनकिंस, ओपनसर्च और गिटिया पर आधारित एक सुरक्षित एप्लिकेशन डिप्लॉयमेंट और मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। इसे डेटा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विभागों का मालिकाना हक बनाए रखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह फ्रेमवर्क प्रोडक्शन सर्वर के लिए एसएसएच या रिमोट एक्सेस की ज़रूरत को खत्म करता है, साथ ही ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट, सेंट्रलाइज़्ड मॉनिटरिंग और रियल-टाइम ऑपरेशनल विज़िबिलिटी की सुविधा भी देता है। सोर्स कंट्रोल, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन और लॉग एनालिटिक्स को एक ही वर्कफ़्लो में जोड़कर, जॉग ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन को मैनेज करने में पारदर्शिता, सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाता है।

यह फ्रेमवर्क सोर्स कोड मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑटोमेशन और लॉग एनालिटिक्स को एक ही वर्कफ़्लो में जोड़ता है। डेवलपर्स अपने मौजूदा गिट-आधारित डेवलपमेंट तरीकों का इस्तेमाल करते रहते हैं, जबकि डिप्लॉयमेंट की सभी गतिविधियाँ ऑटोमेटेड पाइपलाइन के ज़रिए की जाती हैं, जो रिपॉज़िटरी इवेंट्स से शुरू होती हैं।

जब भी गिटिया में किसी तय ब्रांच पर कोड पुश किया जाता है, तो एक सुरक्षित वेबहुक जेनकिंस में डिप्लॉयमेंट वर्कफ़्लो शुरू करता है। यह फ्रेमवर्क अपने-आप सोर्स कोड लेता है, ज़रूरी डिपेंडेंसी और रिसोर्स लाता है, बिल्ड प्रोसेस चलाता है और एप्लीकेशन को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करता है। हर स्टेज को लॉग और ऑडिट किया जाता है, जिससे डिप्लॉयमेंट गतिविधियों का पूरा पता लगाया जा सके।

साथ ही, एप्लीकेशन लॉग, सर्वर लॉग और डिप्लॉयमेंट लॉग को ओपनसर्च पर स्ट्रीम किया जाता है, जिससे डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीमों को एप्लीकेशन के व्यवहार और इंफ्रास्ट्रक्चर की परफ़ॉर्मेंस की पूरी जानकारी मिलती है। नतीजतन, सीधे सर्वर एक्सेस के बजाय सेंट्रलाइज़्ड डैशबोर्ड के ज़रिए ट्रबलशूटिंग और ऑपरेशनल सपोर्ट का काम किया जा सकता है।

प्रमुख विशेषताएँ

जॉग फ्रेमवर्क अनेक ऐसी सुविधाएँ प्रदान करता है जो सुरक्षा, पारदर्शिता और परिचालन दक्षता को सुदृढ़ बनाती हैं—

- उत्पादन वातावरणों में एसएसएच-रहित और पहुंच-मुक्त परिनियोजन
- मौजूदा गिट-आधारित शाखाकरण और विकास वर्कफ़्लो के लिए समर्थन
- सुरक्षित एच.टी.टी.पी.एस चैनलों पर वेबहुक-ट्रिगर परिनियोजन पाइपलाइन
- कॉन्फ़िगर करने योग्य स्वचालित और अनुमोदन-आधारित परिनियोजन तंत्र
- संदेश एकीकरण के माध्यम से वास्तविक समय परिनियोजन सूचनाएं
- आईपी-श्वेतसूचीबद्ध एच.टी.टी.पी.एस कनेक्शनों का उपयोग करके सुरक्षित स्रोत पुनर्प्राप्ति
- एप्लिकेशन, सर्वर और परिनियोजन लॉग का केंद्रीकृत संग्रह
- विकास टीमों के लिए प्रत्यक्ष डैशबोर्ड-आधारित निगरानी
- परिनियोजन गतिविधियों की पूर्ण ऑडिट क्षमता
- बिना किसी लाइसेंस या सदस्यता लागत के पूर्णतः ओपन-सोर्स आर्किटेक्चर

परिनियोजन कार्यप्रवाह

जॉग फ्रेमवर्क में परिनियोजन प्रक्रिया गिटिया में स्रोत कोड भेजे जाने के साथ आरंभ होती है। जैसे ही निर्धारित शाखा में नया कोड जोड़ा जाता है, एक सुरक्षित वेबहुक जेनकिंस पाइपलाइन को सक्रिय कर देता है।

इसके पश्चात जेनकिंस निम्नलिखित चरणों को स्वचालित रूप से निष्पादित करता है—

- स्रोत कोड प्राप्त करना
- आवश्यक संसाधन एवं निर्भरताएँ संकलित करना

- अनुप्रयोग का निर्माण करना
- सत्यापन एवं परिनियोजन
- परिणामों का अभिलेखीकरण एवं सूचना प्रेषण

विभाग की ज़रूरतों के आधार पर, डिप्लॉयमेंट पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो सकते हैं या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में रिलीज़ होने से पहले अप्रूवल वर्कफ़्लो से गुज़र सकते हैं।

काम पूरा होने पर, जेनकिंस डिप्लॉयमेंट के नतीजों की जानकारी प्रॉम्प्ट पोर्टल को देता है, जो बाद में संदेस के ज़रिए प्रोजेक्ट से जुड़े लोगों को नोटिफ़िकेशन भेजता है। इससे यह पक्का होता है कि प्रोडक्शन में किए गए सभी बदलावों की जानकारी तुरंत प्रोजेक्ट टीम को मिल जाए।

हर डिप्लॉयमेंट गतिविधि को ओपनसर्च में रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे एक पूरा ऑडिट ट्रेल बनता है और ऑपरेशन से जुड़ी विस्तृत एनालिसिस मुमकिन हो पाती है।

केंद्रीकृत निगरानी एवं प्रेक्षणीयता

जॉग फ्रेमवर्क की एक विशिष्ट विशेषता इसकी एकीकृत अवलोकन क्षमता वास्तुकला है।

तैनाती लॉगिंग के अलावा, फ्रेमवर्क लगातार एप्लिकेशन लॉग और सर्वर लॉग एकत्र करता है और उन्हें विभाग के स्वामित्व वाले ओपनसर्च क्लस्टर पर स्ट्रीम करता है। विकास टीमों को मॉनिटरिंग डैशबोर्ड तक नियंत्रित पहुंच प्रदान की जाती है, जिससे वे एप्लिकेशन की स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं, विसंगतियों की पहचान कर सकते हैं और वास्तविक समय में प्रदर्शन रुझानों का विश्लेषण कर सकते हैं।

यह दृष्टिकोण परिचालन सहायता को प्रतिक्रियात्मक समस्या निवारण से सक्रिय निगरानी की ओर ले जाता है। एप्लिकेशन त्रुटियां, सेवा व्यवधान और प्रदर्शन अवरोध जैसी समस्याओं की पहचान डैशबोर्ड विश्लेषण के माध्यम से की जा सकती है और उनका समाधान किया जा सकता है, जिससे सर्वर-स्तर के हस्तक्षेप की आवश्यकता काफी कम हो जाती है।

परिणामस्वरूप एक सुरक्षित परिचालन मॉडल प्राप्त होता है जो सिस्टम व्यवहार में पूर्ण दृश्यता बनाए रखते हुए एप्लिकेशन प्रबंधन और अवसंरचना पहुंच के बीच अलगाव को बनाए रखता है।

लाभ एवं प्रभाव

जॉग फ्रेमवर्क को लागू करने से कई महत्वपूर्ण फ़ायदे हुए हैं:-

- एसएसएच का उन्मूलन और उत्पादन परिवेश तक सीधी सर्वर पहुंच
- विभागीय डेटा और बुनियादी ढांचे की बढ़ी हुई सुरक्षा
- पूरी तरह से ऑडिट योग्य परिनियोजन वर्कफ़्लो के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही
- स्वचालन के माध्यम से तैनाती संबंधी मानवीय त्रुटियों में कमी
- केंद्रीकृत निगरानी के माध्यम से तेजी से समस्या की पहचान और समाधान
- स्वचालित सूचनाओं और साझा परिचालन दृश्यता के माध्यम से बेहतर सहयोग
- ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से परिचालन लागत कम करना
- मौजूदा ऑन-प्रिमाइस सरकारी बुनियादी ढांचे के भीतर पूर्ण तैनाती

स्वचालन, अवलोकन और शासन के संयोजन से, ढांचा ई-शासन अनुप्रयोगों के प्रबंधन के लिए एक सुरक्षित और स्केलेबल मॉडल स्थापित करता है।

अग्रिम राह

एनआईसी केरल द्वारा जॉग फ्रेमवर्क का विस्तार क्रमिक रूप से अन्य विभागों एवं पोर्टलों तक किया जा रहा है। भविष्य में इस रूपरेखा में उन्नत चेतावनी प्रणाली, असामान्यता पहचान क्षमता, बहु-स्तरीय अनुमोदन कार्यप्रवाह तथा परिनियोजन एवं लॉग विश्लेषिकी के बीच और अधिक गहन एकीकरण जैसी सुविधाएँ जोड़ी जाएँगी।

ये बदलाव सुरक्षित एप्लीकेशन डिलीवरी के तरीकों को और मज़बूत करेंगे और साथ ही डायरेक्ट सर्वर एक्सेस पर ऑपरेशनल निर्भरता को कम करेंगे। जैसे-जैसे सरकारी सिस्टम का दायरा बढ़ रहा है, जॉग जैसे फ्रेमवर्क डिजिटल पब्लिक सर्विस के पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल मैनेजमेंट के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करते हैं।

▼ चित्र 10.1 **जॉग फ्रेमवर्क आर्किटेक्चर**

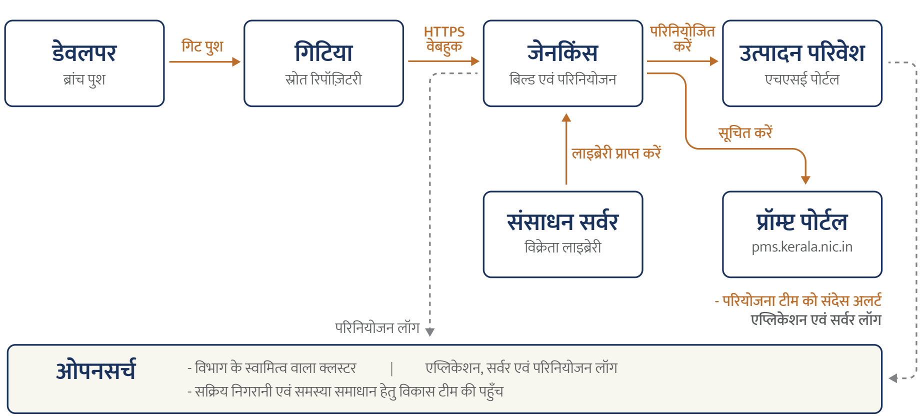

तकनीकी संरचना

जॉग फ्रेमवर्क का संपूर्ण परिनियोजन विभाग के अपने डेटा केंद्र में किया जाता है। सभी घटक मुक्त स्रोत प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं और मौजूदा सरकारी अवसंरचना का उपयोग करते हैं। इससे किसी बाहरी क्लाउड सेवा अथवा लाइसेंस शुल्क पर निर्भरता नहीं रहती।

रूपरेखा के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं—

घटक	कार्य
गिटिया	स्रोत कोड प्रबंधन
जेनकिंस	स्वचालित निर्माण एवं परिनियोजन
ओपनसर्च एवं ओपनसर्च डैशबोर्ड	लॉग संग्रहण, विश्लेषिकी एवं निगरानी
प्रॉम्प्ट पोर्टल	प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नोटिफ़िकेशन के लिए प्रोजेक्ट रिसोर्स ऑर्गनाइज़ेशन और मैनेजमेंट प्लानिंग प्लेटफ़ॉर्म
संसाधन सर्वर	संस्करणीकृत लाइब्रेरी एवं निर्माण संसाधन
फ्लुएंट बिट	लॉग संग्रहण एवं अग्रेषण
उबंटू एलटी पर एनजिनएक्स	सुरक्षित वेब सेवा एवं रिवर्स प्रॉक्सी

घटकों के मध्य सभी संचार एच.टी.टी.पी.एस, आईपी श्वेत-सूचीकरण तथा स्थानीय रूप से विश्वसनीय प्रमाणपत्र प्राधिकरण के माध्यम से सुरक्षित किए जाते हैं।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

बिंदु एस. कुमार
उप महानिदेशक
एनआईसी केरल राज्य केंद्र
सीडैक बिल्डिंग वेल्लयाम्बलम, तिरुवनंतपुरम
केरल - 695033
ईमेल: bindu.sk@nic.gov.in, फ़ोन: 0471-2725495

प्रोद्योगिकी अद्यतन

निकडीसाइन 3.0

ई-गवर्नेंस के लिए सुरक्षित और निर्बाध डिजिटल हस्ताक्षर समाधान

संपादित : **सी. जे. एंटनी**

डिजिटल हस्ताक्षर सरकारी दस्तावेजों की प्रामाणिकता और अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निकडीसाइन कई वर्षों से विभिन्न सरकारी अनुप्रयोगों में एक विश्वसनीय डिजिटल हस्ताक्षर समाधान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यह विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस प्लेटफॉर्म का समर्थन करता है तथा जावा, पीएचपी, डॉट नेट सहित विभिन्न प्रौद्योगिकियों पर आधारित अनुप्रयोगों के साथ सहज रूप से एकीकृत किया जा सकता है।

ऑनलाइन सरकारी सेवाओं के विस्तार और दस्तावेजों की बढ़ती संख्या के साथ निकडीसाइन के पूर्व संस्करण में कुछ सीमाएँ सामने आने लगीं। जावा पर निर्भरता के कारण इसकी स्थापना प्रक्रिया अपेक्षाकृत जटिल थी और प्रदर्शन पर भी प्रभाव पड़ता था। ऐसे में एक अधिक तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल डिजिटल हस्ताक्षर समाधान की आवश्यकता महसूस हुई।

इन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निकडीसाइन 3.0 का विकास किया गया। यह उच्च प्रदर्शन और मेमोरी सुरक्षा के लिए प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषा रस्ट तथा टॉरी 2 फ्रेमवर्क पर आधारित एक हल्का नेटिव डेस्कटॉप अनुप्रयोग है। इसे पूर्व संस्करणों के लिए प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन (ड्रॉप-इन रिप्लेसमेंट) के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जिससे मौजूदा सरकारी अनुप्रयोगों में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती। निकडीसाइन 3.0 डिजिटल हस्ताक्षर प्रक्रिया को अधिक तेज, सुरक्षित और सरल बनाते हुए ई-गवर्नेंस सेवाओं को नई दक्षता प्रदान करता है।

> निकडीसाइन 3.0 एक नए डिज़ाइन वाला डिजिटल साइनिंग सॉल्यूशन है। इसे रस्ट और टॉरी 2 का इस्तेमाल करके एक हल्के नेटिव डेस्कटॉप एप्लिकेशन के तौर पर बनाया गया है और यह सर्वर-साइड एपीआई से सपोर्टेड है। क्लाइंट साइड पर जावा की ज़रूरत को खत्म करके, यह बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देता है, जिससे प्रति सेकंड 12 डॉक्यूमेंट तक साइन किए जा सकते हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म 'फिल एंड साइन', सिग्नेचर को कहीं भी लगाने की सुविधा, लोकल ऑडिट लॉगिंग, आसान इंस्टॉलेशन और बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस जैसे फ़ीचर देता है।

वी. टी. संतोष
उप महानिदेशक व एसआईओ
vt.santhosh@nic.in

टी. एडवर्ड सैम
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक
edwardsam@nic.in

बीना जी
तकनीकी निदेशक
beena.g@nic.in

सेबिल टी. ए.
वैज्ञानिक - बी
cebil.ta@nic.in

निकडीसाइन 3.0 की प्रमुख विशेषताएँ

लचीला हस्ताक्षर स्थान निर्धारण एवं दृश्य अनुकूलन

निकडीसाइन 3.0 डॉक्युमेंट्स पर दिखने वाले सिग्नेचर लगाने के कई विकल्प देता है। यूज़र्स डॉक्युमेंट पर कहीं भी डबल-क्लिक करके सिग्नेचर लगा सकते हैं या उसकी जगह को ठीक करने के लिए उसे ड्रैग कर सकते हैं। डेवलपर्स सिग्नेचर लगाने की प्रक्रिया को ऑटोमेट करने के लिए कीवर्ड-बेस्ड एपीआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं; यह खास तौर पर उन स्टैंडर्ड फ़ॉर्म्स के लिए उपयोगी है जहाँ सिग्नेचर पहले से तय जगहों पर ही होने चाहिए।

स्केल वैल्यूज़ और थीम्स का इस्तेमाल करके सिग्नेचर के साइज़ और लुक को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। जिन एप्लिकेशन्स में कई पेजों या जगहों पर सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, उनके लिए मल्टी-विजेट और सभी पेजों पर स्टैम्पिंग के विकल्प भी उपलब्ध हैं।

स्वचालित टोकन पहचान के साथ सरल स्थापना

निकडीसाइन 3.0 को बहुत आसानी से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। पहली बार शुरू करने पर, यह एप्लीकेशन अपने-आप कनेक्टेड डीएससी टोकन का पता लगा लेती है। अगर ज़रूरी ड्राइवर मौजूद नहीं है, तो एप्लीकेशन टोकन मॉडल की पहचान करती है और यूज़र्स को सही ड्राइवर इंस्टॉल करने के लिए कहती है।

इसका आसान सेटअप प्रोसेस यूज़र्स को जल्दी काम शुरू करने में मदद करता है, जबकि डिटेल वाले और आसानी से समझ आने वाले एरर मैसेज समस्याओं को तेज़ी से हल करने में मदद करते हैं।

हस्ताक्षरकर्ता पूर्वावलोकन, प्रमाणपत्र विवरण एवं ऑडिट लॉग

साइन करने से पहले, यूज़र सर्टिफ़िकेट की जानकारी और डॉक्यूमेंट का थंबनेल प्रीव्यू देख सकते हैं, जिसमें सिग्नेचर की जगह दिखाई देती है। मुख्य एप्लीकेशन विंडो में सर्टिफ़िकेट की जानकारी (जैसे जारी करने वाले का विवरण और वैलिडिटी स्टेटस) और हाल ही में साइन किए गए डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखाई देती है।

निकडीसाइन 3.0 एक लोकल ऑडिट लॉग भी रखता है जिसमें डॉक्यूमेंट का नाम, तारीख और साइन करने का समय जैसी जानकारी होती है, जिससे जवाबदेही की एक अतिरिक्त परत मिलती है।

फिल एंड साइन

'फिल एंड साइन' फ़ीचर की मदद से एप्लिकेशन, एक्रोफ़ॉर्म फ़ील्ड वाले पीडीएफ फ़ॉर्म सीधे निकडीसाइन 3.0 पर भेज सकते हैं। यूज़र फ़ॉर्म फ़ील्ड को देख या अपडेट कर सकते हैं, अपना डिजिटल सिग्नेचर लगा सकते हैं और पूरे हो चुके डॉक्यूमेंट को बिना प्रिंट किए, हाथ से साइन किए या स्कैन किए सबमिट कर सकते हैं।

यह फ़ीचर खास तौर पर ऑनलाइन सर्विस डिलीवरी वर्कफ़्लो के लिए उपयोगी है, जहाँ फ़ॉर्म के लिए वेरिफिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर, दोनों की ज़रूरत होती है।

जेसन डेटा हस्ताक्षर

पीडीएफ और एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स के अलावा, निकडीसाइन 3.0जेसन डेटा की डिजिटल साइनिंग को भी सपोर्ट करता है। यूज़र्स साइन करने से पहले कंटेंट को ट्री या ग्रिड फ़ॉर्मेट में देख सकते हैं,

जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और मंज़ूर की जा रही जानकारी का वेरिफिकेशन हो जाता है।

प्रयुक्त प्रौद्योगिकियाँ

- **टौरी 2:** टौरी, जावा जैसे बड़े रनटाइम को बंडल करने के बजाय ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटिव वेब इंजन का इस्तेमाल करता है। इससे एप्लिकेशन का साइज़, स्टार्ट-अप का समय और रिसोर्स की खपत काफी कम हो जाती है।
- **रस्ट :** साइनिंग इंजन को रस्ट का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जो अपनी परफॉर्मेंस, भरोसेमंदता और मेमोरी सेफ़्टी के लिए जाना जाता है। यह एप्लिकेशन की रिस्पॉन्सिवनेस बनाए रखते हुए साइनिंग ऑपरेशन की एक साथ प्रोसेसिंग (कंकरेंट प्रोसेसिंग) को सपोर्ट करता है।
- **पीकेसीएस#11 टोकन सपोर्ट :** निक्डीसाइन 3.0 स्टैंडर्ड पीकेसीएस#11-कम्प्लायंट डीएससी हार्डवेयर टोकन को सपोर्ट करता है, जिनका इस्तेमाल विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस पर सरकारी डिप्लॉयमेंट में किया जाता है।

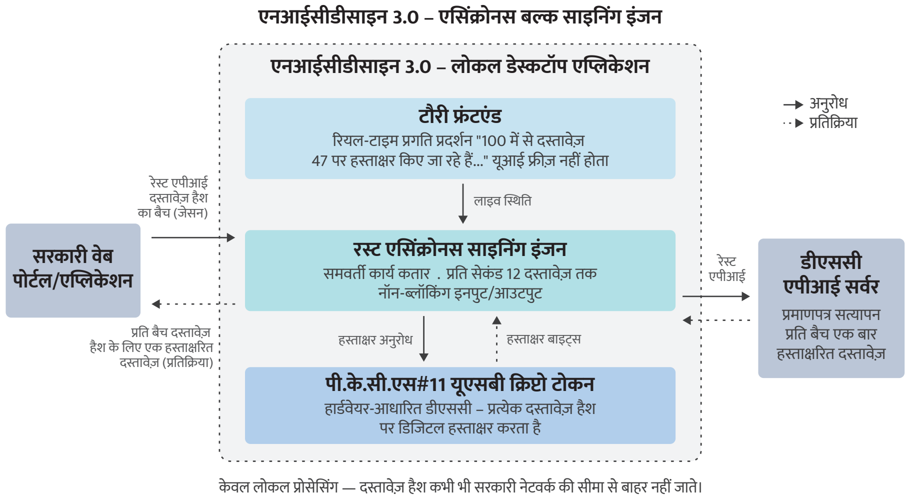

▲ चित्र 11.2 : निक्डीसाइन 3.0 सरकारी वेब पोर्टल से बल्क साइनिंग अनुरोध को कैसे प्रोसेस करता है

दस्तावेज़ हस्ताक्षर कार्यप्रवाह

निक्डीसाइन 3.0 निक्डीसाइन 3.0 में एक अहम सुधार यह है कि यह बड़ी संख्या में साइनिंग रिक्वेस्ट को तेज़ी से प्रोसेस कर सकता है। रेस्ट एपीआई के ज़रिए, एप्लिकेशन साइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स के बैच सबमिट कर सकते हैं। रस्ट-बेस्ड साइनिंग इंजन इन रिक्वेस्ट को एक साथ (पैरेलल) प्रोसेस करता है और हर डॉक्यूमेंट को डिजिटल रूप से साइन करने के लिए पीकेसीएस#11 टोकन के साथ कम्युनिकेट करता है।

यह सॉल्यूशन हर सेकंड 12 डॉक्यूमेंट्स तक प्रोसेस कर सकता है। प्रोसेस के दौरान, एक लाइव प्रोग्रेस इंडिकेटर पूरे हो चुके डॉक्यूमेंट्स का स्टेटस दिखाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान एप्लिकेशन पूरी तरह से रिस्पॉन्सिव रहता है, जिससे बिना किसी रुकावट या देरी के यूज़र को अच्छा अनुभव मिलता है। निक्डीसाइन 3.0 'आप जो देखते हैं, उसी पर साइन करते हैं (डब्ल्यू.वाई.एस.आई.डब्ल्यू.वाई.एस)' फ़ीचर को भी सपोर्ट करता है, जिससे यूज़र्स साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। इस फ़ीचर को एप्लिकेशन सेटिंग्स के ज़रिए चालू या बंद किया जा सकता है।

लाभ एवं प्रभाव

- **तेज़ी से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग:** हाई-स्पीड बल्क साइनिंग से काम करने की क्षमता बढ़ती है और सर्विस डिलीवरी तेज़ होती है।
- **इस्तेमाल में आसानी:** ऑटोमैटिक टोकन डिटेक्शन और आसान इंस्टॉलेशन की वजह से यह सॉल्यूशन टेक्निकल और नॉन-टेक्निकल, दोनों तरह के यूज़र्स के लिए इस्तेमाल करना आसान है।
- **आसानी से माइग्रेशन:** पुराने वर्शन की जगह आसानी से इस्तेमाल हो सकने के कारण, मौजूदा इंटीग्रेशन बिना किसी बदलाव के काम करते रहते हैं।
- **बेहतर सिक्योरिटी:** जावा पर निर्भरता खत्म करने और रस्ट के मेमोरी-सेफ़ आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करने से एप्लीकेशन पर हमले का खतरा कम हो जाता है। लोकल ऑडिट लॉग यह पक्का करते हैं कि साइनिंग रिकॉर्ड यूज़र के डिवाइस पर ही रहें।
- **डेडिकेटेड सपोर्ट:** निक्डीसाइन टीम नए इंटीग्रेशन और पुराने वर्शन से माइग्रेशन, दोनों के लिए मदद देती है।

निक्डीसाइन के साथ शुरुआत

निक्डीसाइन से संबंधित सभी संसाधन निक्डीसाइन पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

वेब अनुप्रयोगों के साथ एकीकरण

इंटीग्रेशन के लिए अनुरोध निक्डीसाइन पोर्टल के ज़रिए जमा किए जा सकते हैं। समीक्षा और मंज़ूरी के बाद, निक्डीसाइन टीम ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन और टेक्निकल सपोर्ट देती है।

डेमो का उपयोग करें

साफ़ इंस्टॉलेशन के लिए:

- निक्डीसाइन के किसी भी मौजूदा वर्शन को अनइंस्टॉल करें और पक्का करें कि सही टोकन ड्राइवर इंस्टॉल हो।
- पोर्टल से निक्डीसाइन 3.0 इंस्टॉलर डाउनलोड करें और उसे चलाएँ।

इंस्टॉलेशन के दौरान, सर्टिफ़िकेट इंस्टॉलेशन प्रॉम्प्ट को मंज़ूरी दें। इससे ज़रूरी सर्टिफ़िकेट विंडोज़ सर्टिफ़िकेट स्टोर में जुड़ जाता है और सुरक्षित एच.टी.टी.पी.एस कम्युनिकेशन चालू हो जाता है।

भावी दिशा

विंडोज़, लिनक्स और मैकओएस पर निक्डीसाइन को और मज़बूत और स्थिर बनाने की कोशिशें चल रही हैं, ताकि यूज़र्स को एक जैसा और भरोसेमंद अनुभव मिल सके।

भविष्य के सुधारों में आधार-आधारित ई-साइन सेवाओं के साथ इंटीग्रेशन शामिल है, जिससे डीएससी हार्डवेयर टोकन के बिना भी नागरिक दस्तावेज़ों पर डिजिटल रूप से साइन कर सकेंगे। क्लाउड-आधारित डिजिटल सिग्नेचर के लिए भी सपोर्ट पर विचार किया जा रहा है, जिससे ज़्यादा फ़्लेक्सिबिलिटी और किसी भी डिवाइस से साइन करने की सुविधा मिलेगी।

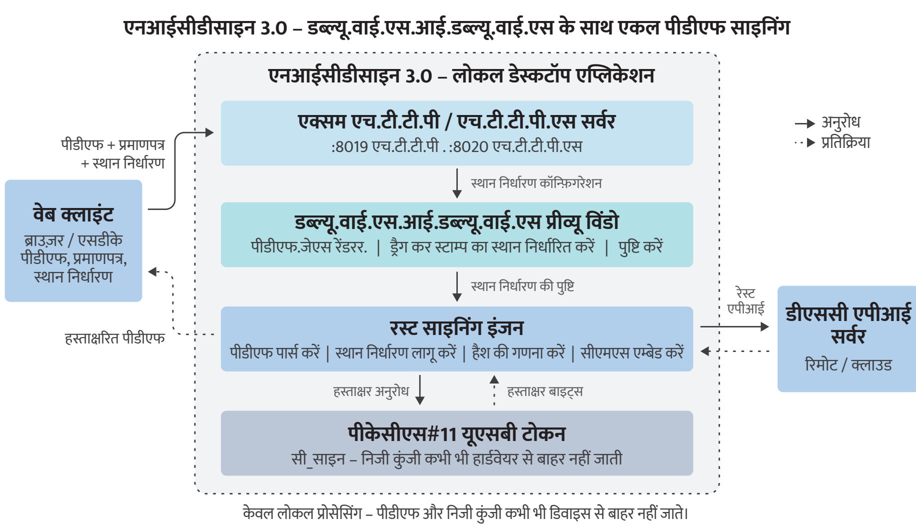

▲ चित्र 11.1 : निक्डीसाइन 3.0 वेब क्लाइंट से एक साइनिंग रिक्वेस्ट को कैसे प्रोसेस करता है

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

वी. टी. सन्तोष
उप महानिदेशक एवं एसआईओ
एनआईसी केरल राज्य केंद्र
सीडैक बिल्डिंग वेल्लयाम्बलम, तिरुवनंतपुरम
केरल - 695033
ईमेल: vt.santosh@nic.in, फ़ोन: 0471-272989

ऐपस्केप

मोबाइल तकनीक सरकारों के लिए अपने नागरिकों की सेवा करने का एक प्रमुख साधन बनकर उभरी है। इसने संचार और सहयोग के लिए पारंपरिक भौतिक नेटवर्क की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह कहीं अधिक किफायती और सुलभ भी है, जिससे बेहतर नागरिक-सरकार संपर्क के माध्यम से राष्ट्र को मजबूती मिलती है। इस संपर्क को और मज़बूत करने के लिए, एनआईसी ने एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध 730 से ज़्यादा मोबाइल ऐप्स का एक संग्रह तैयार किया है। ऐपस्केप के इस अंक में हाल ही में लॉन्च किए गए कुछ सबसे लोकप्रिय मोबाइल ऐप्स को शामिल किया गया है। ये ऐप्स प्रशासन, विकास, वित्त, सार्वजनिक वितरण, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं।

एनआईसी ऐप्स से संबंधित प्रश्नों के लिए कृपया संपर्क करें

एंड्रॉइड
संदीप सूद
ईमेल: sood.sandeep@nic.in | फोन: 0177-2880890

आईओएस
रॉय जोसेफ
ईमेल: macckan-ker@nic.in | फोन: 0497-2700761

सी.एम.आई.एस कर्मचारी कॉर्नर

सी.एम.आई.एस. कर्मचारी कॉर्नर एक सरकार-से-कर्मचारी (जी2ई) सेवा है, जिसे मणिपुर सरकार के कर्मचारियों को सुरक्षित डिजिटल मंच के माध्यम से कार्मिक एवं वेतन संबंधी जानकारी तक सुविधाजनक पहुँच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। यह अनुप्रयोग कर्मचारियों को केंद्रीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी.एम.आई.एस) में पंजीकरण करने की सुविधा देता है, जो मणिपुर सरकार के लिए विकसित एक एकीकृत कार्मिक प्रबंधन एवं वेतन प्रणाली है।

पंजीकरण के दौरान कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत एवं सेवा संबंधी अतिरिक्त जानकारी को अद्यतन कर प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे अभिलेख सटीक एवं अद्यतन बने रहते हैं। पंजीकरण के पश्चात कर्मचारी इंटरनेट सुविधा उपलब्ध होने पर कहीं से भी ऑनलाइन विभिन्न सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिनमें कर्मचारी प्रोफ़ाइल, वेतन पर्ची, वार्षिक वेतन विवरण, वेतन बिल की स्थिति, सेवा इतिहास तथा अन्य रोजगार संबंधी जानकारी शामिल हैं।

यह प्रणाली कर्मचारी पहचान पत्र तैयार करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी भी संकलित करती है, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएँ अधिक सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनती हैं। कर्मचारियों को अपनी जानकारी तक प्रत्यक्ष पहुँच एवं प्रबंधन की सुविधा प्रदान करके यह अनुप्रयोग आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ), विभागाध्यक्षों (एचओडी) तथा जिला प्रबंधन सूचना प्रणाली (डी.एम.आई.एस) अधिकारियों के प्रशासनिक कार्यभार को उल्लेखनीय रूप से कम करता है।

एन. बिनोद सिंह (sio-man@nic.in)

ए.पी.एस.टी.एस मोबाइल ऐप

ए.पी.एस.टी.एस मोबाइल ऐप एक नागरिक-केंद्रित डिजिटल मंच है, जिसे राज्यभर में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं तक सुविधाजनक एवं निर्बाध पहुँच प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य परिवहन सेवा (ए.पी.एस.टी.एस) के सहयोग से विकसित यह अनुप्रयोग यात्रियों को कहीं से भी और कभी भी विभिन्न परिवहन सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है।

यह ऐप उपयोगकर्ताओं को बस मार्गों की खोज करने, समय-सारिणी देखने तथा ऑनलाइन टिकट बुक करने की सुविधा एक सरल एवं उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफ़ेस के माध्यम से प्रदान करता है। यात्री अपने टिकटों को ऑनलाइन रद्द भी कर सकते हैं, जिससे टिकट काउंटर पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और टिकटिंग प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक एवं प्रभावी बनती है। सुरक्षित एवं सुगम लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए प्लेटफ़ॉर्म में वॉलेट-आधारित भुगतान तथा पेमेंट गेटवे सेवाओं का एकीकरण किया गया है।

टिकटिंग सेवाओं के अतिरिक्त, यह अनुप्रयोग यात्रियों की सुविधा एवं सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कई मूल्यवर्धित सुविधाएँ भी प्रदान करता है। इनमें यात्रा के दौरान आपात स्थिति में अलर्ट भेजने की सुविधा तथा शिकायतों के पंजीकरण एवं त्वरित निवारण के लिए एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शामिल है।

परिवहन सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से ए.पी.एस.टी.एस मोबाइल ऐप अरुणाचल प्रदेश में सेवाओं की पहुँच, पारदर्शिता, परिचालन दक्षता तथा यात्रियों के समग्र अनुभव को बेहतर बनाता है।

ज्योतिष रॉय (sio-arn@nic.in)

निकलर

निकलर, एनआईसी छत्तीसगढ़ द्वारा विकसित एक अभिनव मूल्यांकन समाधान है, जो शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की आवश्यकता के बिना पारंपरिक कक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) आधारित प्रश्नोत्तरी आयोजित करने में सक्षम बनाता है।

इस प्रणाली में अरूको मार्कर आधारित पहचान-पत्रों, जिन्हें निकलर आईडी कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी अपने उत्तर के अनुरूप इन कार्डों को अलग-अलग दिशा में प्रदर्शित करते हैं, जबकि शिक्षक निकलर मोबाइल एप्लिकेशन से युक्त एंड्रॉयड स्मार्टफोन के माध्यम से उत्तरों को तत्काल रिकॉर्ड कर लेते हैं। कम लागत पर विकसित यह समाधान पारंपरिक लिखित परीक्षाओं और मैनुअल मूल्यांकन में लगने वाले समय एवं श्रम को उल्लेखनीय रूप से कम करता है। यह एमसीक्यू आधारित प्रारूपिक मूल्यांकन, विषयानुसार अनुकूलित प्रश्नोत्तरी, उपस्थिति प्रबंधन तथा विद्यार्थियों के प्रदर्शन के विश्लेषण जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराता है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम प्रोफ़ाइल तैयार कर शिक्षकों को सीखने के स्तर के अनुरूप शिक्षण रणनीति अपनाने में सहायता करता है।

गेमीफिकेशन आधारित शिक्षण तकनीकों के माध्यम से निकलर कक्षा में मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक सहभागितापूर्ण, रोचक और प्रभावी बनाता है। वर्तमान में यह समाधान छत्तीसगढ़ के 30,000 से अधिक विद्यालयों में उपयोग किया जा रहा है तथा कम लागत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मूल्यांकन का सफल उदाहरण बनकर उभरा है। यह पहल दर्शाती है कि प्रौद्योगिकी का अभिनव उपयोग कक्षा मूल्यांकन को अधिक दक्ष, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बना सकता है।

तेज नारायण सिंह (sio-cg@nic.in)

ई-एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज केरल

ई-एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज केरल, केरल सरकार के रोजगार सेवा विभाग द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो नागरिकों को रोजगार कार्यालयों की सेवाएँ डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराता है। यह विभाग नियोक्ताओं और रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों के बीच सेतु के रूप में कार्य करते हुए पंजीकरण, अभ्यर्थी चयन, पंजीकरण नवीनीकरण तथा अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन जैसी सेवाएँ प्रदान करता है।

यह एप्लिकेशन पंजीकृत अभ्यर्थियों को रोजगार संबंधी सेवाओं तक ऑनलाइन पहुँच प्रदान करता है। इसके माध्यम से वे अपने रोजगार पंजीकरण का नवीनीकरण, विशेष नवीनीकरण के लिए आवेदन, व्यक्तिगत एवं संपर्क संबंधी विवरण अद्यतन तथा स्थान परिवर्तन की स्थिति में रोजगार कार्यालय के स्थानांतरण के लिए अनुरोध कर सकते हैं। सभी अनुरोध निर्धारित कार्यप्रवाह के अनुसार संसाधित किए जाते हैं और स्वीकृति के बाद संबंधित जानकारी उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल में स्वतः अद्यतन हो जाती है।

एप्लिकेशन के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी प्रोफ़ाइल, शैक्षिक योग्यता, वरिष्ठता की स्थिति, उपलब्ध रोजगार अवसरों तथा पूर्व में प्राप्त नियुक्तियों से संबंधित जानकारी भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की रिक्तियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे रोजगार के इच्छुक युवाओं को अधिक अवसर प्राप्त होते हैं।

रोजगार कार्यालय की सेवाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से यह एप्लिकेशन सेवा वितरण को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। साथ ही नागरिकों की सुविधा बढ़ाने और राज्य में रोजगार सेवाओं के कुशल प्रबंधन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

संतोष वी. टी. (sio-ker@nic.in)

जीवन प्रमाण

जीवन प्रमाण सेवा पेंशनभोगियों एवं पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए विकसित एक डिजिटल सेवा है, जिसके माध्यम से वे अपना डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र (डीएलसी) ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। इससे भौतिक रूप से जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तथा पेंशन सत्यापन प्रक्रिया अधिक सरल, सुरक्षित और सुविधाजनक बनती है। यह सेवा आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से पेंशनभोगियों की पहचान का सुरक्षित सत्यापन सुनिश्चित करती है।

जीवन प्रमाण मंच में चेहरा प्रमाणीकरण, अंगुली छाप (फिंगरप्रिंट) तथा आइरिस स्कैन सहित विभिन्न आधुनिक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सुविधाएँ उपलब्ध हैं। पेंशनभोगी अपने स्मार्टफोन पर उपलब्ध आधार फेस आरडी सेवा के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त बायोमेट्रिक उपकरण के प्रमाणीकरण कर सकते हैं। आवश्यकता होने पर पंजीकृत फिंगरप्रिंट अथवा आइरिस स्कैनर का उपयोग भी किया जा सकता है।

सफल प्रमाणीकरण के उपरांत प्रणाली स्वतः एक विशिष्ट प्रमाण आईडी जनरेट करती है तथा इसकी सूचना पेंशनभोगी को भेजी जाती है। इसके बाद डिजिटल जीवन प्रमाण-पत्र संबंधित पेंशन संवितरण प्राधिकरण को स्वतः प्रेषित कर दिया जाता है, जिससे कागजी दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। आधार आधारित सुरक्षित प्रमाणीकरण और पूर्णतः डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से जीवन प्रमाण ने पेंशनभोगियों के लिए प्रमाणन प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया है। यह पहल देशभर में डिजिटल शासन को सुदृढ़ करते हुए नागरिकों को सुविधाजनक एवं विश्वसनीय सेवाएँ उपलब्ध कराने का उत्कृष्ट उदाहरण है।

संजय कुमार पांडेय (hog-asd@nic.in)

ई-जागृति

ई-जागृति भारत सरकार की एक प्रमुख डिजिटल पहल है, जिसे देशभर में उपभोक्ता विवाद निवारण तंत्र के आधुनिकीकरण एवं एकीकरण के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह मंच डिजिटल माध्यमों के द्वारा उपभोक्ताओं को विवाद निवारण संस्थाओं से जोड़ते हुए दक्षता, सुगमता तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ बनाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों का निस्तारण त्रिस्तरीय अर्ध-न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (डीसीडीआरसी), राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एस.सी.डी.आर.सी) तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (एन.सी.डी.आर.सी) शामिल हैं।

ई-जागृति इन सभी संस्थाओं को डिजिटल रूप से एकीकृत करते हुए निर्बाध वाद प्रबंधन तथा प्रभावी सेवा वितरण सुनिश्चित करता है। इसके माध्यम से उपभोक्ता ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, वाद की प्रगति की निगरानी कर सकते हैं, वाद अभिलेखों तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं तथा बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाए बिना समय पर अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ उपलब्ध मोबाइल ऐप उपभोक्ता अधिकारों, उत्तरदायित्वों तथा सार्वजनिक वितरण सेवाओं से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए ई-जागृति उपभोक्ताओं को सशक्त बनाता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, प्रक्रियागत विलंब को कम करता है, विवाद निवारण संस्थाओं के मध्य समन्वय को सुदृढ़ करता है तथा देशभर में अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित उपभोक्ता संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

जी. मयिल मुथु कुमारन (hog-consumeraffairs@nic.in)

छत्तीसगढ़ विधानसभा ऐप

छत्तीसगढ़ विधानसभा मोबाइल ऐप छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही एवं गतिविधियों से संबंधित जानकारी को पारदर्शी, समयबद्ध और सहज रूप से उपलब्ध कराने के लिए विकसित आधिकारिक डिजिटल मंच है। विधानसभा के डिजिटलीकरण की पहल के अंतर्गत विकसित यह एप्लिकेशन जनप्रतिनिधियों, शासकीय अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा नागरिकों को अपने मोबाइल उपकरणों के माध्यम से विधानसभा की गतिविधियों से अद्यतन बनाए रखता है।

यह एप्लिकेशन विधानसभा से संबंधित प्रमाणिक सूचनाओं के केंद्रीकृत भंडार के रूप में कार्य करता है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता कार्यसूची, विधानसभा की कार्यवाही, प्रश्न एवं उत्तर, आधिकारिक सूचनाएँ, समिति बैठकों की समय-सारिणी, सदस्यों की प्रोफ़ाइल तथा मतपत्र संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त एप्लिकेशन में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण, बजट भाषण, बजट दस्तावेज तथा कटौती प्रस्तावों सहित अन्य महत्त्वपूर्ण विधायी दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे विधानसभा की कार्यवाही से संबंधित जानकारी नागरिकों तक सरलता और शीघ्रता से पहुँचती है।

विधानसभा की कार्यवाही को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराकर यह एप्लिकेशन पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनसहभागिता को प्रोत्साहित करता है। साथ ही यह पेपरलेस शासन को बढ़ावा देने, विधानसभा और नागरिकों के बीच संवाद को सुदृढ़ करने तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

तेज नारायण सिंह (sio-cg@nic.in)

भारत और वियतनाम ने उभरती एवं महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में सहयोग को नई गति दी

भारत और वियतनाम ने अपनी उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत महत्त्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों ने आर्थिक विकास और सतत प्रगति में डिजिटल नवाचार की परिवर्तनकारी भूमिका को रेखांकित करते हुए प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में सहयोग का दायरा विस्तृत करने पर सहमति व्यक्त की।

इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल के रूप में भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम के बीच वित्तीय नवाचार एवं डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत क्यूआर कोड आधारित खुदरा भुगतान प्रणालियों को परस्पर जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच पर्यटन और व्यावसायिक लेनदेन अधिक सरल एवं सुगम बन सकेंगे।

भारत और वियतनाम ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), 6जी संचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु प्रौद्योगिकी, समुद्री विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि निर्माण, उन्नत सामग्री तथा महत्त्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ, अनुसंधान एवं विकास केंद्रों की स्थापना, प्रौद्योगिकी विकास तथा नवाचार आधारित साझेदारियों को बढ़ावा दिया जाएगा।

दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा सतत विकास के लिए डिजिटल एवं उन्नत प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी सहमति व्यक्त की। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु-अनुकूल प्रौद्योगिकियाँ, स्मार्ट कृषि, सतत जल प्रबंधन, आपदा सहनशीलता तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण शामिल हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों पक्षों ने वियतनाम में आसियान-भारत ट्रैकिंग, डेटा रिसेप्शन एवं प्रोसेसिंग सुविधा की स्थापना की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत किया। यह सुविधा क्षेत्रीय अंतरिक्ष सेवाओं और वैज्ञानिक सहयोग को सुदृढ़ बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

दोनों देशों के नेताओं ने आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड तथा वियतनाम के इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ऑफ रेडियोएक्टिव एंड रेयर एलिमेंट्स के बीच दुर्लभ मृदा तत्वों एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में हुए नए समझौते का भी स्वागत किया। यह साझेदारी लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण तथा उन्नत प्रौद्योगिकी आधारित विनिर्माण को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

इन पहलों के माध्यम से भारत और वियतनाम ने नवाचार, डिजिटल परिवर्तन, आर्थिक विकास एवं सतत प्रगति को गति देने के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत प्रौद्योगिकी सहयोग की आधारशिला रखी है।

स्रोत - *प्रेस सूचना ब्यूरो*

भारत और दक्षिण अफ्रीका उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत

भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल अवसंरचना तथा उन्नत विनिर्माण को भविष्य के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में चिह्नित करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग को और सुदृढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की।

3 जून 2026 को नई दिल्ली में आयोजित द्विपक्षीय बैठक के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह तथा दक्षिण अफ्रीका की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार उपमंत्री डॉ. नोमालुंगेलो जीना ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, क्वांटम प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी तथा हाइड्रोजन ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के विस्तार पर चर्चा की।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई), क्वांटम प्रौद्योगिकी तथा स्टार्टअप-आधारित नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए अनुसंधान सहयोग को नवाचार, व्यावसायीकरण तथा उद्योग-आधारित परिणामों में परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों देशों ने उन्नत सामग्री एवं विनिर्माण, भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी तथा डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में वैज्ञानिकों, अनुसंधान संस्थानों और तकनीकी विशेषज्ञों के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने पर सहमति व्यक्त की।

बैठक के दौरान जैव प्रौद्योगिकी, जीनोमिक्स, टीका विकास, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी तथा महामारी तैयारी के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श किया गया। दक्षिण अफ्रीका ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य विज्ञान तथा कौशल विकास के क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाने में विशेष रुचि व्यक्त की।

दोनों पक्षों ने स्क्वायर किलोमीटर एरे (एसकेए) परियोजना सहित खगोल विज्ञान के क्षेत्र में जारी सहयोग की समीक्षा की तथा ब्रिक्स के अंतर्गत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च-प्रदर्शन संगणना, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा की।

बैठक में दोनों देशों ने नवाचार, स्टार्टअप सहयोग, उत्कृष्ट अनुसंधान तथा डिजिटल परिवर्तन पर आधारित भविष्य उन्मुख प्रौद्योगिकी साझेदारी को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

स्रोत - *प्रेस सूचना ब्यूरो*

भारत-नॉर्डिक साझेदारी से डिजिटल नवाचार, उभरती प्रौद्योगिकियों एवं हरित प्रौद्योगिकी को मिलेगा बढ़ावा

भारत और नॉर्डिक देशों ने अपने द्विपक्षीय सहयोग को हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक विस्तारित करते हुए डिजिटल नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान सहयोग तथा सतत प्रौद्योगिकी विकास को भविष्य के सहयोग का प्रमुख आधार बनाया है। इस संबंध में निर्णय 19 मई 2026 को ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान लिया गया।

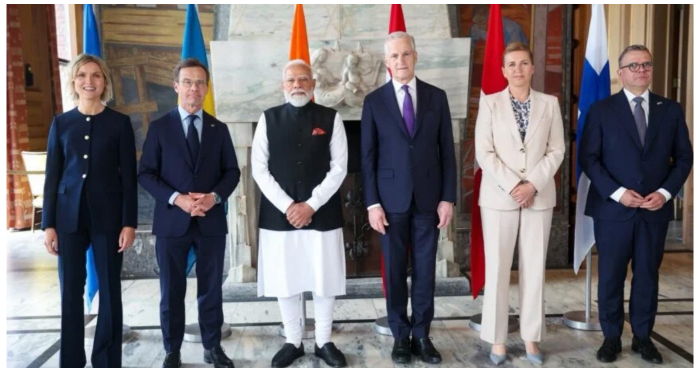

इस साझेदारी का उद्देश्य नॉर्डिक देशों की तकनीकी विशेषज्ञता को भारत की विनिर्माण क्षमता, प्रतिभा संसाधन और बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन की क्षमता के साथ जोड़कर नवाचार-आधारित विकास को गति देना है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल प्रौद्योगिकी, दूरसंचार, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, उन्नत विनिर्माण, अनुसंधान एवं नवाचार तथा अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

शिखर सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि भारत-नॉर्डिक हरित प्रौद्योगिकी एवं नवाचार रणनीतिक साझेदारी का शुभारंभ रही। इस पहल का उद्देश्य सतत प्रौद्योगिकियों को अपनाने, डिजिटल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा डेटा-संचालित शासन एवं सेवा वितरण को बढ़ावा देना है। इससे नवाचार को प्रोत्साहन मिलने, संसाधनों के बेहतर उपयोग, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तथा प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक विकास के नए अवसर सृजित होने की अपेक्षा है।

दोनों पक्षों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं गणित (एस.टी.ई.एम) के क्षेत्र में अनुसंधान सहयोग को और गहरा करने पर भी सहमति व्यक्त की। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों तथा शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। विशेष रूप से 6जी संचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान से सुदृढ़ डिजिटल अवसंरचना के विकास तथा डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की संभावना है।

नॉर्डिक देशों के साथ भारत का प्रौद्योगिकी सहयोग पहले से ही व्यापक है। डेनमार्क में सूचना प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी एवं नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में लगभग 40 भारतीय कंपनियाँ कार्यरत हैं। वहीं फिनलैंड ने अपने प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में भारतीय पेशेवरों के बढ़ते योगदान की सराहना की है। फिनलैंड में भारतीय समुदाय की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय उपस्थिति दोनों पक्षों के बीच प्रतिभा आधारित सहयोग को और सुदृढ़ बना रही है।

शिखर सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, आर्कटिक एवं ध्रुवीय अनुसंधान, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बल दिया गया। इन पहलों से दोनों क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी विकास को गति मिलने, नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने तथा स्टार्टअप, शोधकर्ताओं और प्रौद्योगिकी उद्यमों के लिए नए अवसर सृजित होने की अपेक्षा है।

स्रोत - *डीडी न्यूज़*

भारत और नेपाल बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में करेंगे सहयोग

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (मेइटी) के डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग (डीआईबीडी) ने नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (डीपीआई-एआई) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य बहुभाषी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है।

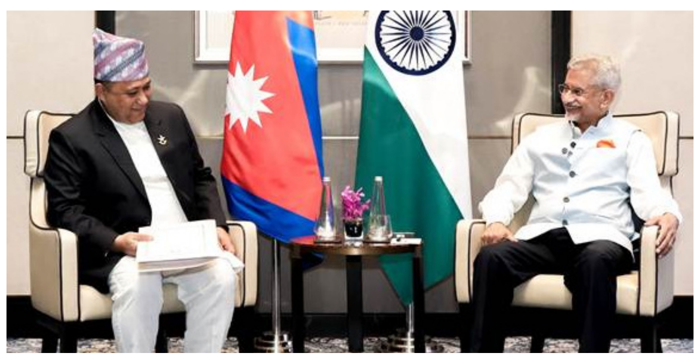

इस सहयोग के अंतर्गत नेपाली भाषा के डेटासेट, वाक् संग्रह (स्पीच कॉर्पस) तथा वाक्-से-पाठ (स्पीच-टू-टेक्स्ट), पाठ-से-वाक् (टेक्स्ट-टू-स्पीच), मशीन अनुवाद और बहुभाषी संवादात्मक एआई अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक संसाधनों का संयुक्त रूप से विकास किया जाएगा।

भाषिणी के मुक्त एवं अंतरसंचालनीय भाषा प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र का उपयोग करते हुए यह पहल नेपाल में बहुभाषी डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ-साथ भाषा एवं साक्षरता संबंधी बाधाओं को कम करने में सहायक होगी, जिससे नागरिकों को सार्वजनिक सेवाओं तक अधिक सुगम पहुँच प्राप्त होगी।

दोनों संस्थान प्राकृतिक भाषा संसाधन (एनएलपी), बहुभाषी एआई तथा डीपीआई के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान, प्रायोगिक परियोजनाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण संबंधी गतिविधियाँ भी संचालित करेंगे।

इस सहयोग का एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भारत-नेपाल क्षेत्र की अल्प-संसाधन एवं कम प्रतिनिधित्व वाली भाषाओं का डिजिटलीकरण एवं संरक्षण भी है। इसके लिए भाषा डेटासेट और एआई आधारित उपकरण विकसित किए जाएंगे, जिससे इन भाषाओं के संरक्षण और डिजिटल उपयोग को बढ़ावा मिलेगा।

भारत के एआई-संचालित बहुभाषी डिजिटल समावेशन मंच भाषिणी पर वर्तमान में 36 भारतीय पाठ भाषाओं, 23 भारतीय वाक् भाषाओं तथा 35 अंतरराष्ट्रीय भाषाओं का समर्थन उपलब्ध है। यह मंच 800 से अधिक सरकारी वेबसाइटों को भाषाई सेवाएँ प्रदान करता है तथा प्रतिदिन 1.5 करोड़ से अधिक एआई इनफरेंस संसाधित करता है।

यह साझेदारी बहुभाषी एआई क्षमताओं के विस्तार, भाषा प्रौद्योगिकी में सीमा-पार सहयोग को सुदृढ़ करने तथा भारत और नेपाल के बीच डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगी।

स्रोत - *प्रेस सूचना ब्यूरो*

विश्वसनीय सेमीकंडक्टर एवं एआई पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाने हेतु भारत 'पैक्स सिलिका' पहल में शामिल

भारत ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान औपचारिक रूप से पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल होकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को नई दिशा दी है। इस पहल के माध्यम से वैश्विक सेमीकंडक्टर तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और सुदृढ़ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

पैक्स सिलिका विश्वसनीय देशों का एक रणनीतिक गठबंधन है, जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, उन्नत एआई प्रणालियों तथा उनकी तैनाती हेतु आवश्यक अवसंरचना सहित संपूर्ण सिलिकॉन मूल्य श्रृंखला को सुरक्षित बनाना है। यह पहल विविधीकृत, लचीले तथा लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के साथ-साथ सीमित वैश्विक आपूर्ति स्रोतों पर निर्भरता कम करने का प्रयास करती है।

हस्ताक्षर समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने वैश्विक सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की विकसित होती सेमीकंडक्टर क्षमताएँ और विशाल इंजीनियरिंग प्रतिभा देश को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तकनीकी परिवर्तन के अगले चरण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाती हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग को आने वाले वर्षों में लगभग 10 लाख कुशल पेशेवरों की आवश्यकता होगी, जो भारत के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है।

अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस समझौते को आर्थिक सुरक्षा, उन्नत प्रौद्योगिकी और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग को गहरा करने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप बताया। इस पहल के अंतर्गत महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर विनिर्माण, डेटा अवसंरचना तथा अत्याधुनिक एआई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के साथ-साथ विश्वसनीय एवं लोकतांत्रिक साझेदारियों के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित किया जाएगा।

हस्ताक्षर समारोह के उपरांत आयोजित उच्चस्तरीय फायरसाइड चर्चा में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के सचिव श्री एस. कृष्णन, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर, माइक्रोन टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा, तथा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक रणधीर ठाकुर ने भाग लिया।

चर्चा के दौरान वक्ताओं ने भविष्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था के निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती परस्पर निर्भरता पर बल दिया। उन्होंने उन्नत एआई प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार विकास एवं तैनाती के लिए विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों, लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं तथा सहयोगात्मक नवाचार के महत्व को रेखांकित किया।

पैक्स सिलिका पहल में भारत की भागीदारी सुरक्षित, विश्वसनीय और सुदृढ़ प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है। साथ ही यह सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को नई गति प्रदान करेगी।

स्रोत - *प्रेस सूचना ब्यूरो*

भारत इनोवेट्स 2026 से भारत-यूरोप डीप-टेक सहयोग को मिली नई गति

भारत फ्रांस के नीस स्थित पैले देज़ एक्सपोज़िशन में भारत इनोवेट्स 2026 के प्रथम संस्करण का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने संयुक्त रूप से किया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित यह पहल भारत के डीप-टेक नवाचार पारितंत्र को वैश्विक उद्योग, निवेशकों, शिक्षाविदों और अनुसंधान संस्थानों से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है।

इस आयोजन में भारत के 120 नवोन्मेषकों, 15 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों तथा 500 से अधिक वैश्विक हितधारकों ने भाग लिया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, एडवांस्ड कंप्यूटिंग, जैव प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण सहित 13 प्रमुख क्षेत्रों में भारत की नवाचार क्षमता का प्रदर्शन किया गया।

कार्यक्रम के पहले दिन 30 से अधिक रणनीतिक साझेदारियों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें नवाचार-केंद्रित समझौता ज्ञापन (एमओयू) और संयुक्त घोषणाएँ शामिल हैं। इनका उद्देश्य अनुसंधान सहयोग, उद्यमिता, प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण तथा स्टार्टअप पारितंत्र को सुदृढ़ करना है। इसके अंतर्गत भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों और वैश्विक इनक्यूबेटरों के बीच सहयोग, अग्रणी अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी विकास एवं बाज़ार तक पहुँच से संबंधित समझौते तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी), भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) और फ्रांस के विश्वविद्यालयों के बीच छात्र एवं शोध सहयोग को बढ़ावा देने वाले समझौते शामिल हैं।

इस अवसर पर इंडिया-फ्रांस एटीएल ब्रिज पहल का भी शुभारंभ किया गया। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन तथा ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स के सहयोग से संचालित यह पहल फ्रांस में भारत के अटल टिंकरिंग लैब मॉडल पर आधारित पहला स्कूल इनोवेशन लैब स्थापित करेगी तथा दोनों देशों के युवा नवोन्मेषकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इंफोसिस के संस्थापक श्री एन. आर. नारायण मूर्ति ने कहा कि उच्च शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों की भूमिका मूल्य-आधारित उद्यमियों और प्रौद्योगिकी नेतृत्वकर्ताओं के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक तकनीकी संस्थानों की सफलता साझा मूल्यों, प्रतिभा, अनुशासित नवाचार, पारदर्शी प्रशासन और विश्वास पर आधारित होती है।

कार्यक्रम के दौरान "एआई फॉर ग्लोबल गुड", "इंडिया एंड यूरोप: डीप-टेक विदाउट बॉर्डर्स" तथा "ग्लोबल डीप-टेक कैपिटल कॉरिडोर्स" जैसे विषयों पर उच्चस्तरीय परिचर्चाएँ आयोजित की गईं। इन सत्रों में उत्तरदायी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संप्रभु एआई क्षमताओं, सीमा-पार नवाचार, उद्यम पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण तथा भरोसेमंद वैश्विक साझेदारियों के माध्यम से सुदृढ़ तकनीकी पारितंत्र के निर्माण पर विचार-विमर्श किया गया।

नीतिनिर्माताओं, उद्योग जगत, शिक्षाविदों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और शोध संस्थानों की व्यापक भागीदारी के साथ भारत इनोवेट्स 2026 ने भारत और यूरोप के बीच डीप-टेक, अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में सहयोग को नई दिशा प्रदान की है तथा वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की उभरती भूमिका को और सुदृढ़ किया है।

स्रोत - *प्रेस सूचना ब्यूरो*

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एआई-सक्षम ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया

भारतग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जून 2026 को नई दिल्ली के पूसा परिसर में आयोजित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दौरान किया

ग्रामीण विकास मंत्रालय के मुख्य नियंत्रक लेखा कार्यालय द्वारा परिकल्पित तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से विकसित यह पोर्टल आंतरिक लेखा परीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया—लेखा परीक्षा योजना, क्रियान्वयन, प्रतिवेदन, अनुपालन निगरानी तथा आपत्तियों के निस्तारण—को एकीकृत डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराता है।

यह पहल पारंपरिक कागज़-आधारित और बिखरी हुई लेखा परीक्षा प्रणाली के स्थान पर एक एकीकृत डिजिटल व्यवस्था स्थापित करती है, जिससे जोखिम-आधारित और अनुपालन लेखा परीक्षाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। सभी लेखा परीक्षा अभिलेखों, प्रतिवेदनों तथा अनुपालन संबंधी सूचनाओं के केंद्रीकरण से पारदर्शिता बढ़ेगी, निगरानी सुदृढ़ होगी तथा संस्थागत ज्ञान का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।

पोर्टल में लेखा परीक्षा की संपूर्ण डिजिटल कार्यप्रणाली उपलब्ध है, जिसमें लेखा परीक्षा की योजना, ऑडिट मेमोरेंडम तैयार करना, प्रतिवेदन तैयार करना, अनुमोदन प्रक्रिया तथा डिजिटल अभिलेख प्रबंधन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह लेखा परीक्षा टिप्पणियों तथा कार्रवाई प्रतिवेदनों का केंद्रीकृत भंडार उपलब्ध कराता है, जिससे भविष्य में संदर्भ और विश्लेषण के लिए सभी अभिलेख सुरक्षित रूप से उपलब्ध रहेंगे।

भूमिका-आधारित अभिगम व्यवस्था के माध्यम से लेखा परीक्षकों, लेखा परीक्षा के अधीन संस्थाओं, कार्यक्रम प्रभागों, राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों तथा अनुमोदन प्राधिकारियों को सुरक्षित और नियंत्रित पहुँच प्रदान की गई है। पोर्टल के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड वास्तविक समय में लेखा परीक्षा कवरेज, लंबित टिप्पणियों, अनुपालन की स्थिति तथा वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी उपलब्ध कराते हैं। वहीं, जीआईएस-आधारित इंटरफेस उन क्षेत्रों की पहचान करने में सहायता करता है जहाँ अभी तक लेखा परीक्षा नहीं हुई है, जिससे जोखिम-आधारित प्राथमिकता निर्धारण संभव हो सके।

सरकार के डिजिटल गवर्नेंस मानकों के अनुरूप विकसित इस पोर्टल में भूमिका-आधारित अभिगम नियंत्रण, सुरक्षित एपीआई एकीकरण, ऑडिट लॉगिंग, स्वचालित अपवाद प्रबंधन, नियमित सुरक्षा मूल्यांकन तथा डिजास्टर रिकवरी जैसी उन्नत सुरक्षा सुविधाएँ शामिल की गई हैं, ताकि लेखा परीक्षा संबंधी डेटा की सुरक्षा और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

ग्रामीण विकास मंत्रालय भविष्य में इस पोर्टल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उन्नत विश्लेषण, पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण, पैटर्न पहचान तथा स्वचालित जोखिम मूल्यांकन जैसी सुविधाओं को भी चरणबद्ध रूप से शामिल करने की योजना बना रहा है। इन सुविधाओं से उच्च जोखिम वाले संस्थानों की पहचान, लेखा परीक्षा की प्राथमिकता तय करने तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता मिलेगी।

इस पोर्टल को वित्त मंत्रालय के नियंत्रक महालेखा कार्यालय से भी सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिसके अंतर्गत इसे विभिन्न नागरिक मंत्रालयों एवं विभागों के प्रधान मुख्य नियंत्रक लेखा तथा नियंत्रक लेखा कार्यालयों में लागू करने की दिशा में पहल की जा रही है। इससे यह मंच डिजिटल लेखा परीक्षा प्रशासन के एक प्रभावी मॉडल के रूप में स्थापित होगा।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करते हुए ग्रामीण आंतरिक लेखा परीक्षा पोर्टल सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने, विकास कार्यक्रमों की बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण प्रशासन में पारदर्शी, उत्तरदायी और डेटा-संचालित सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

स्रोत - *प्रेस सूचना ब्यूरो*

यूआईडीएआई ने बायोमेट्रिक एसडीके बेंचमार्किंग चुनौतियाँ सफलतापूर्वक संपन्न कीं, विजेताओं को किया सम्मानित

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद (आईआईआईटी-हैदराबाद) के सहयोग से आयोजित फेस एवं आइरिस बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (एसडीके) बेंचमार्किंग चुनौतियों के विजेताओं को सम्मानित किया। यह पहल स्वदेशी बायोमेट्रिक समाधानों को बढ़ावा देने तथा बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने की दिशा में यूआईडीएआई का एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

फिंगरप्रिंट बेंचमार्किंग चुनौती की सफलता के बाद यूआईडीएआई ने दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच फेस एवं आइरिस एज वेरिएंस चैलेंज आयोजित किए। इन दोनों चुनौतियों में प्रौद्योगिकी कंपनियों और अनुसंधान संस्थानों से कुल 531 पंजीकरण प्राप्त हुए।

व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर फेस चैलेंज में स्लोवाकिया की इनोवाट्रिक्स प्रथम स्थान पर रही। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की आईडीबायो तथा लिथुआनिया की न्यूरोटेक्नोलॉजी ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं आइरिस चैलेंज में आईडीबायो विजेता रही, जबकि न्यूरोटेक्नोलॉजी और इनोवाट्रिक्स क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहीं।

इन चुनौतियों में परफिओस, ऊरू तथा आईआईआईटी-हैदराबाद सहित कई भारतीय कंपनियों और शैक्षणिक संस्थानों ने भी भाग लिया।

इन बेंचमार्किंग चुनौतियों का उद्देश्य भारत और विदेश के अग्रणी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं तथा अनुसंधान संस्थानों द्वारा विकसित वन-टू-वन (1:1) फेस एवं आइरिस मिलान समाधानों की कार्यक्षमता का आकलन करना था। इसके लिए नियंत्रित परीक्षण वातावरण में बड़े पैमाने पर अनाम बायोमेट्रिक डेटासेट का उपयोग कर प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया।

इस पहल की एक प्रमुख विशेषता 5 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के दीर्घकालिक बायोमेट्रिक डेटासेट का उपयोग रही। इसमें पाँच वर्ष के अंतराल पर एकत्रित नमूनों के आधार पर यह परखा गया कि बच्चों की बढ़ती आयु के साथ बायोमेट्रिक सत्यापन प्रणालियाँ कितनी सटीकता से कार्य करती हैं। बच्चों की बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी वास्तविक चुनौतियों के समाधान के लिए इस प्रकार के डेटासेट का उपयोग वैश्विक स्तर पर एक विशिष्ट पहल माना जा रहा है।

बायोमेट्रिक पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यूआईडीएआई ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया तथा इन चुनौतियों में भाग लेने वाले सभी संगठनों के योगदान की सराहना की।

स्रोत - *प्रेस सूचना ब्यूरो*

माननीय कृषि मंत्री ने एम.जी.यू.वी.वी के एआई-सक्षम डायनेमिक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया

उच्च कृषि शिक्षा में डिजिटल परिवर्तन को नई गति प्रदान करते हुए छत्तीसगढ़ के माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय (एम.जी.यू.वी.वी) के एआई-सक्षम डायनेमिक वेब पोर्टल का शुभारंभ किया।

नव विकसित वेब पोर्टल को विद्यार्थियों, शिक्षकों तथा अन्य हितधारकों को शैक्षणिक सेवाओं एवं सूचनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। उपयोगकर्ता-अनुकूल एवं संवादात्मक इंटरफेस से युक्त यह पोर्टल चौबीसों घंटे शैक्षणिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। देश की भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए इसमें बहुभाषी सुविधाएं भी समाहित की गई हैं।

यह पोर्टल विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों का एक केंद्रीकृत डिजिटल मंच है, जहां उद्यानिकी एवं वानिकी से संबंधित स्नातक, स्नातकोत्तर तथा शोध कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, संकाय सदस्यों की प्रोफाइल, अनुसंधान उपलब्धियां, पेटेंट, प्रकाशन तथा अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी भी पारदर्शी रूप से प्रदर्शित की गई है। पोर्टल में एकीकृत छात्रवृत्ति प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं तथा अपने आवेदन की स्थिति का वास्तविक समय में अवलोकन कर सकते हैं।

यह पहल विश्वविद्यालय में स्मार्ट शैक्षणिक प्रशासन एवं डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीकृत डिजिटल मॉड्यूल, स्वचालित शैक्षणिक प्रक्रियाओं तथा ई-गवर्नेंस आधारित सुविधाओं का कार्यान्वयन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) रवि आर. सक्सेना के नेतृत्व में किया गया।

छत्तीसगढ़ के माननीय कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वाणीकी विश्वविद्यालय (एम.जी.यू.वी.वी) के एआई-सक्षम गतिशील वेब पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

इस परियोजना का सफल क्रियान्वयन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), रायपुर द्वारा किया गया। पोर्टल का विकास श्री टी. एन. सिंह, उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, छत्तीसगढ़, तथा श्री पी. रामाराव, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक के मार्गदर्शन में किया गया। इस कार्य में श्री अभिजीत कौशिक, संयुक्त निदेशक (आईटी), एनआईसी छत्तीसगढ़ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

- सत्येश कुमार शर्मा, छत्तीसगढ़

ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी, बोलांगीर, ओडिशा में राज्य स्तरीय राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस समारोह के दौरान ई-पंचायत सभा और पंचायती राज-समीक्षा का शुभारंभ करते हुए

पंचायती राज प्रशासन को सुदृढ़ बनाने हेतु ओडिशा ने स्मार्ट डिजिटल सुशासन उपकरणों का शुभारंभ किया

बलांगीर में 24 अप्रैल, 2026 को आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर ओडिशा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता को बढ़ावा देने के लिए दो अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिला परिषदों हेतु ई-पंचायत सभा तथा पंचायती राज-समीक्षा का शुभारंभ किया।

इन अनुप्रयोगों का उद्घाटन ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी द्वारा माननीय उपमुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव, पंचायती राज, पेयजल एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री रबी नारायण नायक तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, संसदीय कार्य एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मुकेश महालिंग की गरिमामयी उपस्थिति में किया गया।

एनआईसी ओडिशा राज्य केंद्र, भुवनेश्वर द्वारा विकसित ई-पंचायत सभा जिला परिषद की बैठकों के प्रबंधन को बैठक निर्धारण, कार्यसूची प्रबंधन, कार्यवाही के अभिलेखीकरण तथा कार्यवृत्त के प्रसार सहित संपूर्ण डिजिटल कार्यप्रवाह के माध्यम से सुव्यवस्थित बनाता है। यह मंच संचार, अभिलेख प्रबंधन तथा विकास कार्यक्रमों की निगरानी को अधिक प्रभावी बनाता है।

पंचायती राज-समीक्षा पंचायती राज संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों की लेखा-परीक्षण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण करते हुए लेखा-परीक्षण संबंधी टिप्पणियों, अनुपालन की स्थिति तथा प्रतिवेदनों के अंतिम रूप दिए जाने की प्रक्रिया की वास्तविक समय में निगरानी की सुविधा प्रदान करता है। यह अनुप्रयोग निधियों के उपयोग में पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के साथ-साथ वित्तीय अनुशासन को भी प्रोत्साहित करता है।

इन अनुप्रयोगों का शुभारंभ ओडिशा में पंचायती राज संस्थाओं के डिजिटल सशक्तीकरण तथा पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिक-केंद्रित ग्रामीण सुशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

– जयंत कुमार मिश्रा, ओडिशा

सेवा सेतु के लिए एजेंटिक एआई-संचालित शिकायत प्रबंधन रूपरेखा का शुभारंभ

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), असम ने 22 अप्रैल, 2026 को राज्य के प्रमुख नागरिक सेवा मंच सेवा सेतु के लिए एजेंटिक एआई-संचालित शिकायत प्रबंधन रूपरेखा का शुभारंभ किया। इस रूपरेखा का उद्घाटन श्री प्रांजल बेजबरुआ, उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (डीडीजी एवं एसआईओ), असम द्वारा किया गया। इसके पश्चात् श्री राहुल डेका, वैज्ञानिक-डी द्वारा प्रणाली का सजीव प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया।

इस समाधान को सेवा सेतु (sewasetu.assam.gov.in) पर शिकायतों के प्रबंधन को सुव्यवस्थित एवं स्वचालित बनाने के लिए लागू किया गया है। सेवा सेतु असम सरकार का प्रमुख नागरिक सेवा मंच है, जो प्रतिदिन 10,000 से अधिक नागरिक सेवा आवेदनों का निपटान करता है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाली बड़ी संख्या में शिकायतों का भी प्रबंधन करता है।

परंपरागत रूप से शिकायत प्रबंधन में पर्याप्त मानवीय प्रयास की आवश्यकता होती थी, क्योंकि प्रत्येक शिकायत की अलग-अलग समीक्षा, वर्गीकरण और संबंधित प्राधिकारी को प्रेषण करना पड़ता था। नव कार्यान्वित एआई-संचालित रूपरेखा इस पूरी प्रक्रिया को एंड-टू-एंड स्वचालन के माध्यम से परिवर्तित करती है। विशेष रूप से प्रशिक्षित शिकायत वर्गीकरण मॉडल पर आधारित तथा n8n के माध्यम से संचालित यह प्रणाली शिकायतों का बुद्धिमत्तापूर्वक वर्गीकरण एवं उपयुक्त हितधारकों तक प्रेषण करती है। साथ ही, भुगतान सामंजस्य जैसे नियमित मामलों का स्वतः समाधान करती है तथा आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी हस्तक्षेप हेतु सहायता टिकट सृजित कर उनके निस्तारण तक की प्रक्रिया का प्रबंधन करती है।

इस रूपरेखा के कार्यान्वयन से मानवीय कार्यभार में उल्लेखनीय कमी आई है, शिकायतों के निस्तारण की गति में सुधार हुआ है तथा सेवा सेतु परियोजना के अंतर्गत शिकायत निवारण की समग्र कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

श्री प्रांजल बेजबरुआ, डीडीजी और एसआईओ, असम, एनआईसी असम में एजेंट एआई-संचालित शिकायत प्रबंधन ढांचे का शुभारंभ करते हुए

इस सफलता से उत्साहित होकर एनआईसी असम राज्य की अन्य प्रमुख ई-गवर्नेंस पहलों में भी एजेंटिक एआई-संचालित शिकायत प्रबंधन रूपरेखा का विस्तार करने की योजना बना रहा है, जिससे विभिन्न सरकारी डिजिटल मंचों पर बुद्धिमान स्वचालन को बढ़ावा मिलेगा तथा नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता और दक्षता में और सुधार होगा।

– मैत्रेयी शर्मा, असम

तेलंगाना के स्वास्थ्य, चिकित्सा और परिवार कल्याण मंत्री श्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने हेल्थकेयर सेक्टर में डिजिटल गवर्नेंस को मज़बूत करने के लिए 'क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, 2010' वेब एप्लीकेशन लॉन्च किया

तेलंगाना में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम वेब अनुप्रयोग का शुभारंभ

स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल सुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए तेलंगाना के माननीय स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री दामोदर राजा नरसिम्हा ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम, 2010 वेब अनुप्रयोग का शुभारंभ किया। इस अनुप्रयोग का विकास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), तेलंगाना द्वारा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय (डी.पी.एच.एफ.डब्ल्यू) के लिए किया गया है।

यह वेब अनुप्रयोग राज्य में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के पंजीकरण एवं विनियमन के लिए एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली प्रदान करने हेतु विकसित किया गया है। प्रमुख प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से यह मंच स्वास्थ्य पेशेवरों और नियामक प्राधिकरणों के बीच संवाद को सरल बनाते हुए कार्यकुशलता तथा अनुपालन को बढ़ावा देता है।

यह अनुप्रयोग चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को क्लिनिक तथा अन्य क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट्स के पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, उपयोगकर्ता डिजिटल रूप से प्रमाणित लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कागजी कार्यवाही में कमी आती है तथा सेवाओं के निस्तारण में तेजी सुनिश्चित होती है।

इस वेब अनुप्रयोग का शुभारंभ तेलंगाना में स्वास्थ्य प्रशासन के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह मंच सेवा वितरण को सुदृढ़ बनाने, नियामकीय निगरानी को बेहतर करने तथा चिकित्सा पेशेवरों के लिए अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक होगा।

एनआईसी तेलंगाना द्वारा विकसित यह पहल प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुशासन को सशक्त बनाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती है।

- रेनील जॉन, तेलंगाना

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित ई-कारागार शीघ्र रिहाई प्रसंस्करण मॉड्यूल का शुभारंभ किया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने 27 मई 2026 को वर्चुअल माध्यम से अखिल भारतीय स्तर पर ई-कारागार शीघ्र रिहाई प्रसंस्करण मॉड्यूल का शुभारंभ किया। यह पहल देशभर में पात्र बंदियों के दंड में छूट तथा समयपूर्व रिहाई के मामलों पर समयबद्ध, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित विचार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ।

इस मॉड्यूल का शुभारंभ माननीय श्री न्यायमूर्ति सूर्यकांत, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संरक्षक-प्रमुख द्वारा किया गया। इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष तथा माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी, न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा वर्तमान ई-कारागार मंच के अंतर्गत विकसित इस मॉड्यूल को दंड में छूट एवं समयपूर्व रिहाई से संबंधित मामलों के निस्तारण में होने वाली देरी को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यह पहल सुरेन्द्र उर्फ सुंडा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2026 आई.एन.एस.सी 414) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में विकसित की गई है।

यह डिजिटल प्रणाली पात्रता तिथि से पूर्व ही पात्र बंदियों की स्वतः पहचान, प्रस्तावों की ऑनलाइन शुरुआत एवं प्रसंस्करण, लघु संदेश सेवा तथा व्हाट्सएप के माध्यम से वास्तविक समय की स्थिति संबंधी सूचनाएँ, रंग-आधारित निगरानी तंत्र तथा प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए केंद्रीकृत डैशबोर्ड जैसी सुविधाएँ प्रदान करती है। कार्यप्रवाह के डिजिटलीकरण के माध्यम से यह मॉड्यूल जेल प्रशासन, पुलिस विभाग, विधिक सेवा संस्थानों तथा अन्य हितधारकों के बीच पारदर्शिता, जवाबदेही और समन्वय को सुदृढ़ बनाता है।

इस समाधान का प्रारंभिक परीक्षण केंद्रीय कारागार, आगरा तथा जिला कारागार, लखनऊ में किया गया था। पायलट परियोजना के सफल क्रियान्वयन के पश्चात यह मॉड्यूल अब राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा उनकी संबंधित दंड में छूट एवं समयपूर्व रिहाई नीतियों के अनुरूप अपनाए जाने के लिए तैयार है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश और नालसा के संरक्षक-प्रमुख, माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत, वर्चुअल माध्यम से पूरे देश में 'ई-प्रिजन्स अर्ली रिलीज़ प्रोसेसिंग मॉड्यूल' की शुरुआत करते हुए

यह पहल सुशासन, बेहतर सेवा प्रदायगी तथा न्यायिक सुधारों को प्रौद्योगिकी के माध्यम से सशक्त बनाने की दिशा में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सतत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ई-कारागार शीघ्र रिहाई प्रसंस्करण मॉड्यूल पात्र बंदियों के मामलों पर समय पर विचार सुनिश्चित कर कारागार प्रशासन प्रणाली में पारदर्शिता, दक्षता एवं न्याय तक पहुँच को और सुदृढ़ करेगा।

- अर्चना शर्मा, एनआईसी मुख्यालय

बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी पूरे राज्य में 'सहयोग पोर्टल' और हेल्पलाइन नंबर 1100 की शुरुआत करते हुए

बिहार ने 'सहयोग पोर्टल' एवं हेल्पलाइन 1100 का शुभारंभ किया

बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी ने राज्य में सहयोग शिविरों से संबंधित शिकायतों के प्रभावी एवं समयबद्ध निवारण के लिए 'सहयोग पोर्टल' तथा हेल्पलाइन नंबर 1100 का शुभारंभ किया। यह पहल जन शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा बिहार सरकार के लिए विकसित सहयोग पोर्टल एक रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसे शिकायतों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया है। यह पोर्टल शिकायतों के पंजीकरण, निगरानी और निस्तारण की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से संचालित करता है, जिससे प्रशासनिक कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होती है।

पोर्टल के माध्यम से नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, शिकायत की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लंबित मामलों पर अनुस्मारक भेज सकते हैं तथा शिकायत के निस्तारण के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी साझा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, हेल्पलाइन नंबर 1100 नागरिकों को शिकायतों एवं संबंधित जानकारी के लिए एक सहज और सुलभ माध्यम उपलब्ध कराता है।

सहयोग पोर्टल की रियल टाइम निगरानी क्षमता प्रशासन को शिकायतों की प्रगति पर सतत नजर रखने में सक्षम बनाती है, जिससे समयबद्ध कार्रवाई और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह पहल बिहार सरकार की सुशासन एवं नागरिक सेवा प्रदायगी को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

एनआईसी द्वारा विकसित यह डिजिटल समाधान राज्य में जन शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

– सैयद मुमताज़ हुसैन, बिहार

पंजाब के माननीय वित्त मंत्री, सरदार हरपाल सिंह चीमा, एकीकृत स्वीकृति प्रबधंन प्रणाली (यू.एस.एम.एस) की शुरुआत करते हुए

सरकारी स्वीकृतियों के डिजिटलीकरण हेतु पंजाब ने एकीकृत स्वीकृति प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया

पंजाब के माननीय वित्त मंत्री सरदार हरपाल सिंह चीमा ने एकीकृत स्वीकृति प्रबंधन प्रणाली (यू.एस.एम.एस) का शुभारंभ किया। यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने तथा राज्य की भुगतान प्रणालियों के साथ निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया गया है।

एनआईसी के साथ मिलकर ट्रेजरी और अकाउंट्स विभाग द्वारा विकसित 'ई-सैंक्शन मॉड्यूल', मंज़ूरी देने की पारंपरिक कागज़ी प्रक्रिया की जगह पूरी तरह से डिजिटल वर्कफ़्लो लाता है। इस पहल का मकसद सरकारी विभागों में कार्यक्षमता, पारदर्शिता, जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को बेहतर बनाना है।

चंडीगढ़ में पंजाब म्युनिसिपल भवन में लॉन्च किया गया यह प्लेटफ़ॉर्म मंज़ूरी को ऑनलाइन जारी करने और बिल बनाने व पेमेंट प्रोसेस के लिए 'इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम' (आई.एफ.एम.एस) के साथ उनके ऑटोमैटिक इंटीग्रेशन की सुविधा देता है। एक एकीकृत डिजिटल वर्कफ़्लो बनाकर, यह सिस्टम मैन्युअल दखल को काफी कम करता है और मंज़ूरी देने की प्रक्रिया को तेज़ करता है।

यू.एस.एम.एस की एक मुख्य विशेषता इसका व्यापक ऑडिट ट्रेल मैकेनिज़्म है। मंज़ूरी प्रक्रिया के हर चरण को टाइमस्टैम्प, यूज़र क्रेडेंशियल्स और मंज़ूरी के पदानुक्रम के साथ डिजिटल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे पूरी ट्रेसिबिलिटी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। यह प्लेटफ़ॉर्म मंज़ूरी जारी करने से पहले बजट की उपलब्धता की भी जांच करता है, जिससे विभागों को अतिरिक्त खर्च से बचने और मंज़ूर बजट प्रावधानों का पालन करने में मदद मिलती है।

यह सिस्टम स्टैंडर्ड मंज़ूरी फ़ॉर्मेट पेश करता है और ऑटोमैटिक वैलिडेशन चेक शामिल करता है ताकि अकाउंट हेड, स्कीम मैपिंग और लाभार्थी विवरण से जुड़ी प्रक्रियात्मक विसंगतियों और क्लर्क संबंधी गलतियों को कम किया जा सके। इन उपायों से विभागों में वित्तीय लेन-देन की सटीकता और विश्वसनीयता में सुधार होने की उम्मीद है।

इस पहल को 'कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एस.ए.एस.सी.आई) योजना 2026–27' के तहत भारत सरकार के वित्तीय सुधार दिशानिर्देशों के अनुसार विकसित किया गया है। सिस्टम के सफल कार्यान्वयन से पंजाब के इस योजना के तहत ₹50 करोड़ के प्रोत्साहन के लिए पात्र होने की उम्मीद है, साथ ही सरकारी मंज़ूरी की एंड-टू-एंड निगरानी भी मज़बूत होगी।

– परमिंदर कौर, पंजाब

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता एवं कल्याण सेवाओं को सशक्त बनाने हेतु 'जीवन' ऐप लॉन्च

प्रौद्योगिकी-संचालित सेवाओं के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेन्द्र कुमार ने जीवन (जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंस नेटवर्क) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया। यह पहल देशभर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सुरक्षित, समावेशी और सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए विकसित जीवन ऐप एक समर्पित डिजिटल मंच है, जो कल्याणकारी सेवाओं, स्वास्थ्य संबंधी सहायता, आपातकालीन सहायता तथा विभिन्न सरकारी पहलों से संबंधित जानकारी तक सरल पहुँच प्रदान करता है। एकीकृत संसाधन मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया यह ऐप वरिष्ठ नागरिकों को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर आवश्यक सेवाओं और सहायता तंत्र तक सुविधाजनक पहुँच उपलब्ध कराता है।

ऐप की प्रमुख विशेषताओं में वरिष्ठ नागरिकों के लिए संचालित विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना शामिल है। उपयोगकर्ता योजनाओं के लाभ, पात्रता मानदंड तथा अन्य आवश्यक जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, ऐप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समर्थित वृद्धाश्रमों की जानकारी भी प्रदान करता है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों एवं उनके परिवारों को उपयुक्त देखभाल सुविधाओं की पहचान करने में सहायता मिलती है।

जीवन ऐप आपातकालीन सहायता सेवाओं से संबंधित जानकारी भी उपलब्ध कराता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर समय पर सहायता सुनिश्चित की जा सके। वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित इस मंच में सरल नेविगेशन तथा उपयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेस जैसी सुविधाएँ शामिल की गई हैं। उपलब्ध सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सहायता तंत्र तक पहुँच को सुगम बनाने के माध्यम से जीवन वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, गरिमा, समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है।

डॉ. वीरेंद्र कुमार, माननीय केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, जीवन मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च करते हुए

- अर्चना शर्मा, एनआईसी मुख्यालय

निक्सी के 23वें स्थापना दिवस पर एनआईसी को कई सम्मान प्राप्त हुए

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को राष्ट्रीय इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया (निक्सी) के 23वें स्थापना दिवस समारोह में भारत की डिजिटल अवसंरचना, इंटरनेट सुरक्षा तथा कंटेंट डिलीवरी पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने में उसके उल्लेखनीय योगदान के लिए अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

एनआईसी को "रजिस्ट्रार ऑफ द ईयर – हाईएस्ट डी.एन.एस.एस.ई.सी" पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान डोमेन नेम सिस्टम सिक्योरिटी एक्सटेंशन्स (डी.एन.एस.एस.ई.सी) के प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रचार-प्रसार के माध्यम से इंटरनेट आधारित सेवाओं की सुरक्षा और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रदान किया गया। यह पुरस्कार एनआईसी की ओर से वेब प्रौद्योगिकी प्रभाग की श्रीमती सुनीता सिंह ने ग्रहण किया।

इसके अतिरिक्त, एनआईसी को "बेस्ट रिसोर्स मैनेज्ड अकाउंट अवॉर्ड" से भी सम्मानित किया गया। यह सम्मान बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल (बीजीपी) रूटिंग में रिसोर्स पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर.पी.के.आई) के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रदान किया गया, जो इंटरनेट ट्रैफिक रूटिंग की सुरक्षा एवं विश्वसनीयता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

एनआईसी को "इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अवॉर्ड" भी प्रदान किया गया। यह सम्मान निक्सी को सर्वाधिक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) ट्रैफिक उपलब्ध कराने के लिए दिया गया, जो देशभर में डिजिटल सेवाओं के कुशल और प्रभावी वितरण में एनआईसी की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इन दोनों पुरस्कारों को एनआईसी की ओर से नेटवर्क्स प्रभाग के विभागाध्यक्ष श्री करुणाकर गुप्ता ने प्राप्त किया।

ये सम्मान उन्नत इंटरनेट प्रौद्योगिकियों को अपनाने, साइबर सुरक्षा को सशक्त बनाने तथा नागरिकों एवं सरकारी हितधारकों के लिए सुरक्षित, विश्वसनीय और उच्च प्रदर्शन वाली डिजिटल सेवाएँ उपलब्ध कराने के प्रति एनआईसी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। साथ ही, ये उपलब्धियाँ भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण और प्रबंधन में एनआईसी की अग्रणी भूमिका को और सुदृढ़ करती हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाया

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (माईटी) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली में एक योग सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव, माईटी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सर्विसेज इन्कॉरपोरेटेड (निक्सी) के प्रबंध निदेशक, वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रालय के कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की।

प्रतिभागियों ने विभिन्न योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास करते हुए स्वस्थ एवं संतुलित जीवनशैली अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस सत्र ने शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण एवं समग्र स्वास्थ्य संवर्धन में योग के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाने के लिए प्रेरित किया।

यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की भावना तथा "योग से निरोगी काया, स्वास्थ्य से समृद्धि" के संदेश के अनुरूप कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, कल्याण एवं सजगता की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के प्रति माईटी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।